• 'पावर' के इंतजार में महापौर और अध्यक्ष • ग्रामीणों को सरकार पिलाएगी शुद्ध पानी

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

www.akshnews.com

विवादों का फ्लाईओवर

वर्ष 18, अंक-17 | 1 से 15 जून 2020 | मूल्य 25 रूपये

R.N.I. No.HIN/2002/8718 M.P. BPL/642/2018-20

विश्व शक्ति बनने का मौका

लॉकडाउन 5.0 (अनलॉक 1.0) में मिली छूट का दुरुपयोग न करें... आपकी सतर्कता आपके हाथ में है...

राष्ट्रीय पाक्षिक पत्रिका

अक्स

कोरोना के इस संक्रमण काल में भी
आपके साथ, आपके लिए

इस अंक में

राजपाट

9 | बसपा बिगाड़ेगी गणित

प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बसपा ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर मुकाबले को रोचक बना दिया है। वैसे तो मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होगा, लेकिन बसपा चुनावी गणित बिगाड़ेगी।

राजपथ

10-11 | गांवों में रोजी-रोटी की जुगाड़

कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण किए गए लॉकडाउन से मप्र में करीब 12 लाख प्रवासी मजदूर आए हैं। ये सभी मजदूर प्रदेश के 54,903 गांवों में गए हैं। इससे गांवों पर बोझ बढ़ गया है। लेकिन सरकार ने इन मजदूरों...

योजना

15 | सरकार पिलाएगी शुद्ध पानी

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को मप्र में साकार करने के लिए प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इस योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हर घर में नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है।

विवाद

19 | चोरी और सीनाजोरी

मप्र में शराब की बिक्री सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा माध्यम है। इस वित्तीय वर्ष में सरकार को इससे करीब साढ़े 13 हजार करोड़ रुपए की वार्षिक आय होने की उम्मीद थी और विभिन्न तरह के लाइसेंस शुल्क को भी मिला लिया जाए तो करीब 15 हजार करोड़ रुपए का राजस्व आबकारी...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

कोरोना वायरस आफत के साथ संभावनाओं को भी लेकर आया है। जहां इस महामारी ने भारत में 15 करोड़ से अधिक लोगों को बेरोजगार कर दिया है, वहीं नई संभावनाओं का द्वार भी खोल दिया है। केंद्र हो या राज्य सरकारें सभी का फोकस गांवों पर हो गया है। इससे गांवों में ही रोजगार के अवसर निर्मित करने की योजना पर काम चल रहा है। वहीं यह कोशिश भी शुरू हो गई है कि विदेशी कंपनियों के लिए द्वार खोलकर भारत को विश्व शक्ति बनाया जाए।

13

18

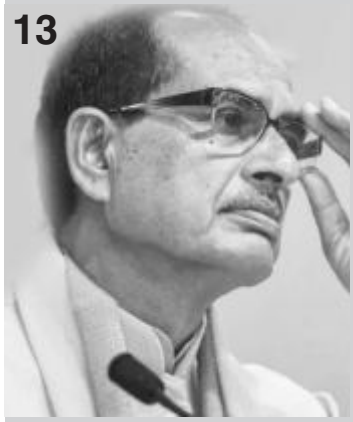

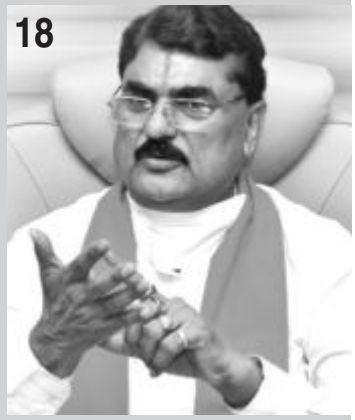

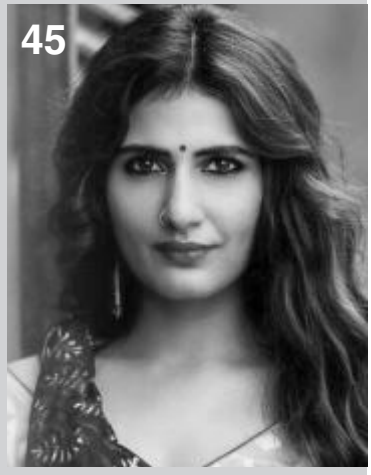

38

45

राजनीति

30-31 | बाकी राज्यों में चुनाव कब?

महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'अभूतपूर्व हस्तक्षेप' के बाद विधान परिषद का चुनाव संपन्न हो गया, साथ ही इससे एक नया सवाल यह खड़ा हो गया है कि महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में विधान परिषद और कई राज्यों में राज्यसभा के लिए लंबित उपचुनावों का क्या...

सियासत

32-33 | 'न्याय' किसके लिए?

छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू कर दी है। कांग्रेस के नजरिए से देखा जाए तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना एक तरीके से मनरेगा 2.0 ही है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में न्याय लागू कर कांग्रेस सरकार...

महाराष्ट्र

36 | खतरे में उद्धव सरकार?

महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर किए गए लॉकडाउन के बीच एकबार फिर से सियासी हलचल शुरू हो गई है। एक ओर जहां महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उनके आवास पर मुलाकात कर राष्ट्रपति शासन...

6 -7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

बिजली का झटका जोर से

मप्र में इन दिनों लोगों के पास बिजली का मनमाना बिल पहुंच रहा है। बिजली का बिल देखकर लोगों के मुंह से कुछ इस तरह के अल्फाज निकल रहे हैं...

मुमकिन नहीं चमन में दोनों की जिद हो पूरी
या बिजलियां रहेंगी या आशियां रहेगा

वैसे तो शायर ने ये पंक्तियां आसमानी बिजली के लिए लिखी हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण किए गए लॉकडाउन के इस दौर में आर्थिक मंदी के बीच लोगों के पास जो बिजली का बिल पहुंच रहा है वह किसी आसमानी बिजली के कहर से कम नहीं है। लोगों के पास भी इस कहर को बर्दाश्त करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि बिजली विभाग का मूलमंत्र है- तुम लाख झालरें लगा लो अपने घरों की दीवार पर, रोशनी तो हमारे आने से ही होगी। हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ सरकार लोगों को राहत देने के बड़े-बड़े दावे कर रही है और दूसरी तरफ उन्हें पिछले साल के बिजली बिल के मुताबिक बिल भिजवा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि लॉकडाउन के कारण पिछले दो महीने से जो संस्थान बंद थे, उन्हें भी भारी-भरकम बिल भेजा जा रहा है। आलम यह है कि 44 डिग्री टेम्प्रेचर में लोगों को जितनी घबराहट नहीं हो रही है, उतनी बिजली बिल को देखकर हो रही है। यह हालत तब है जब मप्र में सबसे अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है। बिजली बिल का करंट लगने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहां अधिकतर बिजली प्राइवेट कंपनियों से महंगी दर पर खरीदी जा रही है। सरकारी विद्युत उत्पादन इकाइयां बंद पड़ी हैं। ऐसे में सरकार प्राइवेट बिजली उत्पादन कंपनियों को राहत देने के लिए आम उपभोक्ताओं पर भार डाल रही है। हैरानी की बात तो यह है कि बिजली कंपनियां उद्योगों से 129 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल वसूल रही हैं। जबकि आम उपभोक्ताओं को हजारों रुपए के बिल भेजे जा रहे हैं। जिसको लेकर उपभोक्ता लॉकडाउन में बिजली कंपनी की मनमानी से परेशान हैं। उद्योगों ने मांग की है कि लॉकडाउन अवधि तक सरकार अन्य राज्यों की तरह फिक्स चार्ज हटाए। सिर्फ यूनिट खपत के आधार पर बिल वसूली की जाए। प्रदेश में अप्रैल-मई में भी 90 प्रतिशत उद्योग बंद हैं, लेकिन इनके बिलों की दरें जस की तस बनी हुई हैं। जानकारों का भी कहना है कि इस आपदा की खड़ी में लोगों और उद्योगों से फिक्स चार्ज, मिनिमम चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूला जाना गलत है। इसलिए अन्य राज्यों की तरह जून तक उद्योगों की बिजली में किसी तरह का चार्ज न लिया जाए। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण जहां लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। वहीं उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं। ऐसे में हर किसी के सामने आर्थिक तंगी मुंह फैलाए खड़ी है। इस घड़ी में सरकार को लोगों और कंपनियों को राहत देनी चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि पिछले दो महीने से बिजली कंपनियां आकलित बिल भेज रही है। जो इसकी शिकायत कर रहा है उसे आश्वासन दिया जा रहा है कि अभी मीटर रीडिंग नहीं हो रही है, इसलिए आपको जो बिजली बिल मिल रहा है, उसका भुगतान कर दीजिए। बाद में जरूरत पड़ी तो उसे अगले बिल में समायोजित कर लिया जाएगा। लोगों का कहना है कि सरकार एक तरफ तो कह रही है कि स्वयं मीटर रीडिंग कर कंपनी को भेजें जिससे वास्तविक खपत का बिल भेजा जाए और दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को मनमाना बिल भेजा जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो कोरोना महामारी के इस दौर में लोग बिजली बिल के करंट का झटका भी नहीं सह पाएंगे।

-राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 18, अंक 17, 1 से 15 जून, 2020

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2015-17

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:-** इंद्रकुमार, **जयपुर:-** आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:-** संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :-** मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
094259 85070, (मंदसौर) धर्मवीर रत्नावत
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-
फोन : 011 25495021, 011 25494676
मुंबई : बी-1, 41 शिव पावर्ती चेम्बर प्लाट नंबर 106-110 सेक्टर-21
नेरूल, नवी मुंबई-400706 मो.-093211 54411
कोलकाता : 70/2 हजरा रोड कोलकाता
फोन-033 24763787, मोबाइल: 09331 033446
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
फोन- 0141 2295805, मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई,
मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिंलटर निपानिया, इंदौर
मोबाइल - 094251 25096

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

दिलचस्प होगा उपचुनाव

प्रदेश में होने वाले 24 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का दम देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस से भाजपा में आए सिंधिया जी कैसे अपने समर्थकों को जिताने में कामयाब होंगे सबकी नजरें इसी पर हैं। वहीं कांग्रेस पर भी जीतने की चुनौती होगी।

● **हेमलता सिंह,** राजगढ़ (म.प्र.)

खर्चों में कटौती

इस समय देश का हर गरीब, मजदूर जहां रोटी के लिए तरस रहा है, वहीं दूसरी तरफ विधायक-सांसदों के वेतनभत्तों और सुख-सुविधाओं पर हर साल अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सरकार को इन खर्चों पर कटौती करनी चाहिए, ताकि जरूरतमंदों की भूख मिटाई जा सके।

● **सौरभ सोनी,** गुना (म.प्र.)

किसानों के लिए सोचें

कोरोना वायरस के कारण भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी डगमगा रही है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र को किसानों के बारे में सोचना होगा। ताकि देश के हर किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल सके और वे इस संक्रमणकाल में अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके।

● **अभिनव शर्मा,** रायसेन (म.प्र.)

स्वास्थ्य विभाग उठाए जरूरी कदम

प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इस महामारी से जंग लड़ने के लिए सरकार को प्रदेश के अस्पतालों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अस्पतालों में बड़ी संख्या में संक्रमितों का इलाज करने के लिए डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को जरूरी कदम उठाना चाहिए। अस्पतालों में मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रहीं हैं या नहीं, उन्हें सही इलाज मिल पा रहा है या नहीं इसका ध्यान रखना आवश्यक है। प्रदेश में आने वाले समय में कोरोना वायरस के संक्रमितों के लिए अस्पतालों में वेंटिलेटरों का इंतजाम करना भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

● **गंगाराम,** भोपाल (म.प्र.)

महामारी में खिल उठी प्रकृति

प्रदेश सहित देशभर में कोरोना का संक्रमण तो फैल रहा है, लेकिन इसके कारण प्रकृति खिल उठी है। लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं तो दूर-दूर तक प्रदूषण का नाम मात्र भी नहीं दिख रहा है। अन्य वर्षों के मुकाबले इस वर्ष हवा का स्तर अधिक स्वच्छ है। प्रदेश सहित देशभर की फैक्ट्रियां बंद होने से नदियों का पानी स्वच्छ और शुद्ध हो रहा है। इस कोरोना के संक्रमणकाल में एक बात तो जाहिर है कि यदि मनुष्य प्रकृति के बारे में सोचेगा तो प्रकृति भी उसका ध्यान रखेगी।

● **नीलम चौधरी,** सीहोर (म.प्र.)

पीने का शुद्ध पानी मिले

गांवों में 84 प्रतिशत आबादी जलापूर्ति से वंचित है। जिन्हें पानी मिल रहा है, उसमें 70 प्रतिशत प्रदूषित है। प्रदेश के कई गांवों में लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। कोरोना वायरस के इस संक्रमणकाल में गांवों की ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। प्रदेश में 20 प्रतिशत भूजल के स्त्रोत का अति शोषण हो रहा है। बारिश के पानी को बचाने के लिए, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की जरूरत है।

● **विनोद चतुर्वेदी,** इंदौर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

गुटबाजी का अंजाम

राजीव बिंदल के इस्तीफे ने हिमाचल प्रदेश भाजपा के अंदरूनी घमासान और गुटबाजी को सतह पर ला दिया है। राजीव बिंदल ने ऐलान किया है कि प्रदेश भाजपा की सूबेदारी उन्होंने उच्च नैतिक मूल्यों के लिए छोड़ी है। हैरानी की बात तो यह है कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने राजीव बिंदल पर प्रत्यक्ष आरोप नहीं लगाया। बस यह सवाल जरूर पूछा कि 5 लाख रुपए के रिश्वत घोटाले के आरोपी डॉ. अजय गुप्ता से उनका क्या रिश्ता है? पर सच सिर्फ वह नहीं है जो दिख रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इस घोटाले की शिकायत प्रधानमंत्री तक भी पहुंची थी। प्रधानमंत्री दफ्तर के हस्तक्षेप के बाद ही बिंदल ने इस्तीफा दिया। खुद नहीं बल्कि मांगने पर। तभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस्तीफा स्वीकार करने में देर भी नहीं लगाई। कहने को तो सोलन की स्थानीय राजनीति में बिंदल के विरोधी महेंद्रनाथ सोफत द्वारा मामले को तूल दिए जाने की बात कही जा रही है। पर इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता कि खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी अपने पार्टी अध्यक्ष से खुश नहीं थे। दोनों के रिश्ते मधुर होते तो ठाकुर उन्हें अपना विधानसभा अध्यक्ष न बनाते। मंत्री पद देते। बिंदल खुद मंत्री ही बनना चाहते थे, लेकिन आलाकमान के सामने उनकी एक नहीं चली। अब वे अपने पद से इस्तीफा देकर अपना विरोध जता चुके हैं।

प्रियंका से त्रस्त यूपी के बाबू

उत्तर प्रदेश सरकार के नौकरशाह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से खासे त्रस्त बताए जा रहे हैं। प्रियंका ने उत्तर प्रदेश में हाशिए पर पड़ी कांग्रेस को वापस ट्रैक पर लाने के लिए कमर कस रखी है। वे बेहद आक्रामक तरीकों से योगी आदित्यनाथ सरकार को अपने निशाने पर रखे हुए हैं जिसका खामियाजा नौकरशाहों को भुगतना पड़ रहा है। खबर है कि प्रियंका गांधी के हर ट्वीट, हर फेसबुक पोस्ट पर सीएम कार्यालय की पैनी नजर रहती है। ऐसे में यदि प्रियंका सरकार की किसी चूक की बाबत कुछ पोस्ट करती हैं तो योगी सरकार तुरंत एक्शन पर आ जाती है। खबर यह भी जोरों पर है कि कई बार जो काम नौकरशाह कर नहीं पाते वे उसे प्रियंका गांधी से ट्वीट करवाकर पूरा करवा लेते हैं। योगी-प्रियंका के बीच चल रही रस्साकशी से कांग्रेस नेता भी खासे घबराए हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लल्लू सिंह और प्रियंका के निजी सचिव पर उत्तर प्रदेश सरकार ने धोखाधड़ी का केस कांग्रेस द्वारा मजदूरों के लिए हजार बसें उपलब्ध कराए जाने की पेशकश के बाद दर्ज करा है, उससे कांग्रेसियों में खासी बेचैनी है। दूसरी तरफ नौकरशाह भी कम परेशान नहीं हैं। राजस्थान में कांग्रेस नेताओं ने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और डीएम आगरा के खिलाफ राज्य के मजदूरों संग धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज करा बाबुओं के बीच बेचैनी बढ़ाने का काम कर डाला है।

पुनर्वास की आस पर फिरा पानी

राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस के कुछ नेता तो कोरोना को पानी पी-पीकर कोस रहे हैं। जिन्हें अपने पुनर्वास की आस थी वे कुछ ज्यादा ही हताश और निराश दिख रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र के समापन का इंतजार था सबको। विधायकों को मंत्री पद पाने की उम्मीद थी क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत दिए थे। साथ ही कुछ लोगों को मलाईदार ओहदों पर नियुक्त करके सत्तासुख की अनुभूति करानी थी। बसपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए आधा दर्जन विधायकों के साथ ज्यादा ही बुरा बीता। मंत्री बनना तय था। पर कोरोना के प्रकोप ने सबकुछ गुड़-गोबर कर दिया। सारे अरमान धरे रह गए। कांग्रेस में भी कम से कम दो दर्जन नेता तो जरूर होंगे, जिन्हें मलाईदार कुर्सी के सपने आ रहे थे। इसमें गलत भी क्या था? पार्टी आलाकमान की हरी झंडी भी मिल चुकी थी। पर कोरोना महामारी के बाद तो मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी ही क्यों हर किसी की प्राथमिकता बदलेगी। एक तो अभी तक महामारी खत्म नहीं हुई है और जब होगी भी तो आर्थिक हालात चिंताजनक होंगे। इसमें संदेह नहीं। यानी कोई भरोसा नहीं कि निकट भविष्य में सियासी पुनर्वास हो भी जाएगा या नहीं। सत्यानाश हो तेरा कोरोना।

जलवा पीके का

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में एक रिटायर नौकरशाह का जलवा दूसरे रिटायर नौकरशाहों से कहीं ज्यादा नजर आ रहा है। मोदी-1 में सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूर्व आईपीएस अजीत डोभाल सबसे ताकतवर माने जाते थे। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा की गिनती डोभाल के बाद ही होती थी। नृपेंद्र मिश्रा के बाद इस सरकार में पीके सिन्हा पीएम के प्रमुख सचिव बनाए गए। पूर्व कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा को प्रधानमंत्री का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया। इन तीनों पूर्व नौकरशाहों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर पीएम ने अपने मंत्रिमंडलीय साथियों के भीतर भारी बेचैनी पैदा कर डाली। अब ताजा खबर यह है कि अजीत डोभाल और नृपेंद्र मिश्रा से कहीं ज्यादा पीके सिन्हा इस सरकार में प्रभावशाली हैं। पीएम कार्यालय में उन्हें आर्थिक और ऊर्जा से संबंधित सारे मंत्रालय की देख-रेख का जिम्मा सौंपा गया है। डोभाल पहले की भांति राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों के प्रभारी हैं।

कौन बनेगा मुख्य सचिव

उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह का सेवाकाल महज 31 जुलाई तक है। ऐसे में नए मुख्य सचिव की तैनाती करनी होगी। जिन्हें इस कुर्सी की दरकार है, वे अपनी लाबिंग कर रहे हैं। उत्पल कुमार सिंह के बारे में चर्चा है कि मुख्यमंत्री या तो कोरोना के मद्देनजर उन्हें तीन महीने का सेवा विस्तार दे सकते हैं। उन्हें सेवा विस्तार न मिला तो 1987 बैच के ओमप्रकाश का दावा प्रबल होगा। जो अभी अपर मुख्य सचिव हैं। मुख्यमंत्री का उन्हीं को सबसे विश्वासपात्र भी माना जाता है। पर वे ठहरे बिहारी। लिहाजा, पर्वतीय मूल के अफसरों की लाबी उनका विरोध कर रही है। पर्वतीय मूल की राधा रतूड़ी उनसे एक बैच जूनियर होने के बावजूद मुख्य सचिव पद की दौड़ में हैं। राधा रतूड़ी के ही बैच के एसएस संधू भी केंद्र में सेवारत हैं। मुख्यमंत्री को कहने को तो तीन अफसरों की सूची केंद्र को स्वीकृति के लिए भेजनी होगी। पर वहां भी सरकार भाजपा की है तो जिसे वे चाहेंगे, उसी के नाम की स्वीकृति मिलने में अड़चन शायद न आए।

अब तो दो किसान पुत्र

प्रदेश की राजनीति में इन दिनों किसान राजनीति का केंद्र बना हुआ है। इसकी एक वजह यह है कि प्रदेश में रबी फसलों की बिक्री का दौर चल रहा है। और दूसरी वजह यह है कि 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वे सीटें किसान बहुल हैं। ऐसे में भाजपा के साथ ही कांग्रेस की भी रणनीति में किसान शामिल है। लेकिन हैरानी की बात यह देखने को मिल रही है कि सरकार में ही इन दिनों 2 किसान पुत्र नजर आ रहे हैं। एक तो जगत विख्यात किसान पुत्र हैं। वे अपने हर भाषण, अपनी हर सभा, अपनी हर बैठक में अपने आपको किसान पुत्र कहने से चूकते नहीं हैं। यही नहीं उनकी योजनाएं-परियोजनाएं भी किसान के इर्द-गिर्द घूमती रहती हैं। वहीं इनके एक अन्य साथी भी अपने आपको किसान पुत्र समझने लगे हैं। जबकि सभी जानते हैं कि वे किसान हैं। आलम यह है कि वे बात-बात में अपने आपको किसान और किसान पुत्र साबित करते हैं। यही नहीं उनसे किसी भी मुद्दे पर बात करिए तो वे हर मुद्दे को किसानों से जोड़ देते हैं। कभी-कभी तो उनकी बातचीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे वे पहले वाले नेताजी से किसानपुत्र का तमगा छीनना चाहते हैं। हालांकि उनकी मंशा में ऐसा कुछ नजर नहीं आता, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। आलम यह है कि इन माननीय के पास काम भी किसानों से संबंधित है। इसलिए उनका पूरा फोकस किसानों पर ही रहता है।

सरकार खुद बेच सकती है शराब

प्रदेश को सबसे अधिक राजस्व आबकारी विभाग से मिलता है। लेकिन आर्थिक मंदी के इस दौर में शराब की बिक्री को लेकर सरकार और शराब ठेकेदारों के बीच ठन गई है। मामला कोर्ट में पहुंच गया है। हालांकि सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का निर्देश कई स्तरों पर दिया है, लेकिन शराब व्यापारी मानने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में अब लगने लगा है कि कहीं ऐसा न हो कि सरकार को खुद शराब बेचनी पड़े। दरअसल, लॉकडाउन के कारण पिछले दो महीने से सारा कारोबार ठप पड़ा है। ऐसे में शराब की दुकानें भी बंद पड़ी हैं। सरकार ने दुकानें खोलने का निर्देश दिया तो व्यापारी आधी-अधूरी दुकानें ही खोल पाए। इसके पीछे उनका तर्क था कि लॉकडाउन के कारण शराब की बिक्री कैसे हो पाएगी। लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अगर हम शराब की दुकानें खोलते हैं तो हमारे ऊपर बोझ पड़ेगा। इसको लेकर 30 ठेकेदार जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। पहली सुनवाई में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। उधर, सूत्रों का कहना है कि सरकार शराब बिक्री की तैयारी कर रही है। मृगनयनी में तो हैंडमेड ओपनर भी बिकने लगा है। अब देखना यह है कि सरकार का अगला कदम क्या होगा?

उपचुनाव की जमावट

प्रदेश में सरकार का भविष्य 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर टिका है। ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश है कि वह अधिक से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में बनी रहे। इसके लिए राजनीतिक सक्रियता के साथ ही प्रशासनिक जमावट भी की जा रही है। इसी कड़ी में 2001 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक सेवानिवृत अधिकारी को मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी नियुक्त किया गया है। दरअसल, उक्त रिटायर्ड अधिकारी को संविदा नियुक्ति देने के पीछे सरकार की बड़ी रणनीतिक सोच है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार उक्त अधिकारी की प्रशासनिक दक्षता का उपयोग कर उपचुनाव में अधिक से अधिक फायदा उठाना चाहती है। उक्त अधिकारी ग्वालियर-चंबल संभाग के अधिकांश जिलों में उच्च पदों पर पदस्थ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यों से जनता के बीच में अपनी पैठ बनाई है। साथ ही क्षेत्र की जनता की मानसिकता को वे भलीभांति जानते हैं। यही नहीं वे इस क्षेत्र के साथ ही प्रदेश के अन्य उन क्षेत्रों में भी पदस्थ रहे हैं, जहां उपचुनाव होने हैं। ऐसे में उक्त अधिकारी उपचुनाव में सरकार के लिए बड़े रणनीतिकार साबित हो सकते हैं। बताया जाता है कि अपनी कुर्सी संभालने के साथ ही उक्त साहब उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में अपने सूत्रों के माध्यम से सर्वे के कार्य में जुट गए हैं। अब देखना यह है कि उनका फायदा सरकार को कितना होता है।

इसलिए गई कुर्सी

कोरोना का यह संक्रमण कई नौकरशाहों के लिए परेशानी का सबब रहा है। जहां लापरवाही के कारण कुछ अफसरों की कुर्सी छिन गई वहीं कुछ की अपने साथियों के साथ पटरी न बैठने के कारण। ऐसा ही कुछ वाक्या भोपाल में भी सामने आया है। दरअसल, संभाग की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठी एक अधिकारी का अचानक तबादला होना चर्चा का विषय बन गया था। जबकि उक्त अधिकारी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही थीं। ऐसे में जब पड़ताल की गई तो यह बात सामने आई कि उनकी अपने संभाग के एक प्रमुख जिले के बड़े साहब से पटरी नहीं बैठ रही थी। सूत्र बताते हैं कि कोरोनावायरस को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में जब दोनों अधिकारियों से प्रशासनिक मुखिया चर्चा कर रहे थे तो किसी मुद्दे को लेकर दोनों आपस में लड़ पड़े। बताया जाता है कि प्रशासनिक मुखिया ने इस बात को गंभीरता से लिया और उक्त प्रकरण में महिला अधिकारी को दोषी मानते हुए उनका तबादला कर दिया। हालांकि उक्त अधिकारी प्रमुख सचिव बन गई थीं। इसलिए उनका जाना तो तय था, लेकिन इस तरह जाना होगा, ये नहीं सोचा था।

...कर दिया वीआरएस अप्लाई

क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं कि एक अधिकारी को अपने सीनियर अधिकारी की डांट इतनी बुरी लगी कि उन्होंने वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया है। लेकिन यह सत्य है। दरअसल, कोरोना वायरस के इस संक्रमणकाल में लोग शारीरिक रूप से भले ही दुरुस्त हैं, लेकिन सभी मानसिक तनाव में हैं। चाहे वह अधिकारी हो या आमजन। ऐसा ही कुछ विगत दिनों प्रदेश को स्वस्थ रखने वाले विभाग में भी देखने को मिला। इस विभाग में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर एक बैठक हो रही थी। उस बैठक में विभाग के प्रमुख ने अपने से नीचे ओहदे के एक जिम्मेदार अफसर को कुछ लापरवाहियों के कारण जमकर डांट पिलाई। साहब की डांट उक्त अफसर को इतनी खली कि वे छुट्टी पर चले गए। यहां तक तो ठीक था। उन्होंने वीआरएस के लिए भी अप्लाई कर दिया। बड़े साहब का उक्त अफसर को डांटना और अफसर द्वारा वीआरएस के लिए अप्लाई करना यह दर्शाता है कि कोरोना वायरस के कारण लोग किस तरह मानसिक तनाव में हैं।

कोरोना वायरस के संकट के समय विभिन्न समितियों एवं कार्यबल को दरकिनार किया जा रहा है और सिर्फ एक व्यक्ति के स्तर पर फैसले हो रहे हैं। सरकार में कोई संवेदनशीलता और क्षमता नहीं है। यह इस सरकार की पहचान बन गई है।

● **अभिषेक मनु सिंघवी**

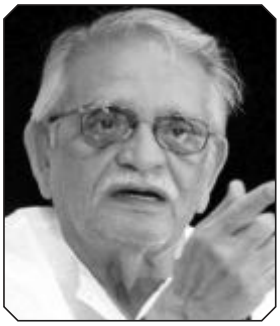

कोरोना वायरस का पूरे विश्व के साथ ही भारत पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। लेकिन इस संकट की घड़ी में भी हमारी पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी योद्धा की तरह डटे हुए हैं। आप लोगों से जरूरी बात कहना है, कि पुलिसमैन एक मुहाफिज का नाम है, हिफाजत करने वालों का...वो एक मददगार है, मदद करता है। उस पुलिसमैन की इज्जत करना हर शहरी का फर्ज बनता है।

● **गुलजार**

मैं मैदान पर कब उतरूंगा, यह नहीं जानता। लार लगाना मेरे लिए स्वाभाविक (आदत) है। इस आदत को छुड़ाने के लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। यदि हमें साथ में रहना है, तो कोशिश करनी होगी और इसे अपनाना होगा। समय के साथ हर किसी को बदलना पड़ता है। इसलिए अब क्रिकेटरों को भी अपनी आदत बदलने की जरूरत है।

● **आर अश्विन**

चीन के शासन का प्रतिनिधित्व 1949 से एक क्रूर, तानाशाही सरकार करती आई है। चीन के कई फैसले विश्व के लिए घातक सिद्ध हुए हैं। हम सोचते रहे कि चीन की सरकार हमारी तरह बनेगी, लेकिन वह घृणा और द्वेष की नीति अपना रही है।

● **माइक पोम्पियो**

मुझे यकीन नहीं हुआ था जब मुझे पता चला था कि मैं महानायक अमिताभ बच्चन जी के साथ युद्ध नामक शो करने वाली हूं। मेरे करियर के शुरुआती दिनों में अमिताभ जी जैसे एक्टर के साथ काम करना मेरा सौभाग्य है। मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी। हमने डेढ़ साल साथ काम किया और उनके साथ वक्त बिता पाना मेरे लिए बड़ी बात है। शो इतना सफल नहीं हुआ लेकिन उसके खत्म होने के बाद भी मेरे हर बर्थडे पर अमित जी सबके पहले विश करते हैं। पिछले 6 सालों में कोई ऐसा इंसान जो मुझे मेरे बर्थडे पर सबसे पहले मैसेज करते हैं चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं तो वो है अमिताभ बच्चन जी। हर साल ठीक 12:00 बजे सबसे पहला बर्थडे मैसेज मुझे बच्चन जी का होता है।

● **आहाना कुमरा**

वाक्युद्ध

केंद्र सरकार ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन कर दिया था। इस कारण करोड़ों लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया। जब भूखो मरने की नौबत आई तो लोग अपने घरों की ओर पलायन करने को मजबूर हुए। अब सरकार ने राहत पैकेज दिया है वह भी अपर्याप्त है। सरकार पूरी तरह फेल हो गई है।

● **सोनिया गांधी**

कोरोना वायरस से बचने का एकमात्र उपाय लॉकडाउन था। मोदी सरकार ने समय पर कदम उठाकर वायरस के संक्रमण पर काफी हद तक सफलता पाई है। कांग्रेस को ऐसे समय में राजनीति करने की बजाय सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। लेकिन वह जनता को बरगला रही है।

● **जेपी नड्डा**

बसपा बिगाड़ेगी गणित

प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बसपा ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर मुकाबले को रोचक बना दिया है। वैसे तो मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होगा, लेकिन बसपा चुनावी गणित बिगाड़ेगी। 2018 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो उपचुनाव में बसपा 8 सीटों पर जीत-हार में प्रभावी भूमिका निभाएगी। गौरतलब है कि जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होना है 2018 में उनमें से 23 पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे। इन 23 सीटों में से 8 पर जीत-हार के अंतर से अधिक बसपा को वोट मिले थे। यानि इन सीटों पर भाजपा की हार बसपा के कारण हुई थी। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि इन सीटों पर उपचुनाव में बसपा जीत का गणित बिगाड़ सकती है।

मप्र बसपा अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने बताया कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तरप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के आदेशानुसार मध्यप्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव में बसपा सभी 24 सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इन 24 सीटों में से हम ग्वालियर-चंबल क्षेत्र की 16 सीटों पर पूरे दमखम से लड़ेंगे। इस संभाग की मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी एवं अशोकनगर जिलों की करीब 13 सीटों पर पहले हमारे विधायक रह चुके हैं। पिप्पल ने बताया कि बाकी 8 सीटों पर भी हमारे प्रत्याशी खड़े होंगे और उन सीटों पर पार्टी की स्थिति को बेहतर करेंगे। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के लिए हमारी तैयारी जमीनी स्तर पर चल रही है। हालांकि, कोरोना वायरस की महामारी को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते हमारी तैयारी थोड़ी धीमी हुई है। पिप्पल ने बताया, किसानों की कर्जमाफी एवं बेरोजगारी हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे। इसके अलावा, हम अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मुद्दे भी उठाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह में दावेदारी आवेदन फॉर्म लिए जाएंगे। उसके बाद पैनल सूची मायावती को भेजी जाएगी। पिप्पल ने बताया कि बसपा के सभी कार्यकर्ता दिन-रात संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं और पूरी तैयारी से चुनावी मैदान में उतरेगी।

2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने जिन सीटों पर जीत के अंतर से अधिक वोट पाया था वे हैं जौरा, सुमावली, मुरैना, अंबाह, करैरा, पोहरी, मुंगावली, सुवासरा। इन्हीं सीटों पर अपने प्रभाव के कारण बसपा ने उपचुनाव में ताल ठोकने की घोषणा की। अगर पूर्व के चुनाव परिणामों को देखें तो बसपा का 6 सीटों पर अधिक प्रभाव है। ये सीटें हैं जौरा, सुमावली, मुरैना, अंबाह, करैरा और पोहरी। इनमें से 2018 के चुनाव में बसपा जौरा और पोहरी में दूसरे स्थान पर रहीं।

दरअसल वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने दो सीटें जीती थीं। दमोह के पथरिया सीट पर पार्टी की उम्मीदवार रामबाई ने जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में पार्टी विरोधी बयानबाजी के चलते उन्हें निलंबित करने की कार्रवाई की गई। वहीं भिंड से संजीव सिंह कुशवाह जीत हासिल कर विधायक बन गए थे। बसपा ने 2018 के चुनाव के बाद कांग्रेस को बाहर से समर्थन देकर राज्य में कमलनाथ सरकार बनवाने में मदद की थी। इसके अलावा कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने पर हुए उपचुनाव में बसपा में अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करने का फैसला किया था। लेकिन अब बदले सियासी घटनाक्रम के बीच बसपा ने सभी 24 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी कर ली है। बसपा ने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। पार्टी ने भले ही 2 सीटों पर जीत हासिल की हो। लेकिन कई सीटों पर वो दूसरे या तीसरे नंबर पर रही थी। इसके अलावा बसपा ने कई सीटों पर भाजपा और कांग्रेस का सियासी गणित बिगाड़ने का भी काम किया था।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

24 सीटों पर बसपा की स्थिति (2018 में)

विधानसभा सीट	जीत का अंतर	बसपा
जौरा	15173	41,014 (दूसरे स्थान पर)
आगर	2490	1978 (पांचवा स्थान)
ग्वालियर	21044	4596 (तीसरा स्थान)
डबरा	57446	13155 (तीसरा स्थान)
बमौरी	27920	13155 (चौथा स्थान)
सुरखी	21418	चुनाव नही लड़ा
सांची	10813	1029 (पांचवा स्थान)
सांवेर	2945	2844 (तीसरा स्थान)
सुमावली	9313	31331 (तीसरा स्थान)
मुरैना	20849	21149 (तीसरा स्थान)
दिमनी	18447	14456 (तीसरा स्थान)
अंबाह	7547	22179 (चौथा स्थान)
मेहगांव	25814	7597 (चौथा स्थान)
गौहद	23989	15438 (तीसरा स्थान)
ग्वालियर पूर्व	17819	5446 (तीसरा स्थान)
भांडेर	39896	2642 (तीसरा स्थान)
करैरा	14824	40026 (तीसरा स्थान)
पोहरी	7918	52736 (दूसरा स्थान)
अशोकनगर	9730	9559 (तीसरा स्थान)
मुंगावली	2136	14202 (तीसरा स्थान)
अनुपपूर	11561	चुनाव नहीं लड़ा
हाटपिपल्या	13519	2347 (तीसरा स्थान)
बदनावर	41506	2099 (छठवां स्थान)
सुवासरा	350	1688 (छठवां स्थान)

ग्वालियर-चंबल में है ज्यादा प्रभाव

राज्य के ग्वालियर-चंबल इलाके में बसपा का खासा दबदबा है। पार्टी यहां कई बार विधानसभा चुनावों में प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियों- भाजपा और कांग्रेस के लिए सिरदर्द साबित हो चुकी है। ऐसे में अब होने वाले उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर बसपा का बड़ा रोल होगा। वहीं राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बसपा यदि सभी 24 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है तो इसका नुकसान कांग्रेस को ज्यादा हो सकता है। बसपा के उपचुनाव में उतरने के ऐलान के बाद प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बसपा का चुनाव लड़ने का फैसला, उनकी पार्टी का फैसला है। लेकिन यदि बसपा चुनाव मैदान में उतरती है तो सबको पता है कि हाथी की चाल में कौन रौंदा जाएगा।

कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण किए गए लॉकडाउन से मप्र में करीब 12 लाख प्रवासी मजदूर आए हैं। ये सभी मजदूर प्रदेश के 54,903 गांवों में गए हैं। इससे गांवों पर बोझ बढ़ गया है। लेकिन सरकार ने इन मजदूरों की रोजी-रोटी का जुगाड़ गांव में ही करने का इंतजाम करना शुरु कर दिया है। इसके लिए मनरेगा सहित अन्य ग्रामीण योजनाओं को आधार बनाया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत दिनों श्रम सिद्धि योजना शुरु की है। जिसके तहत हर व्यक्ति को रोजगार दिया जाना है।

गांवों में रोजी-रोटी की जुगाड़

को रोना वायरस ने देश के हर वर्ग को प्रभावित किया है। लेकिन पहले से बुरे दौर से गुजर रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था इससे बुरी तरह चरमरा रही है। अगर मप्र की बात करें तो यहां 54,903 गांव हैं, लेकिन उनकी स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है कि वे प्रवासी मजदूरों को रोजगार दे सकें। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार ने दूसरे प्रदेशों से आए प्रवासी मजदूरों सहित प्रदेश में रह रहे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का अभियान शुरू किया है। इसके लिए प्रदेश की हर पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है। श्रम सिद्धि अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे मजदूर जिनके जॉब कार्ड नहीं है, उनके जॉब कार्ड बनवाकर, प्रत्येक मजदूर को काम दिलाया जाएगा।

श्रम सिद्धि अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति को कार्य दिया जाएगा। इसके लिए घर-घर सर्वे किया जाएगा तथा जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है उनके जॉब कार्ड बनाकर दिए जाएंगे। जो मजदूर अकुशल होंगे उन्हें मनरेगा में कार्य दिलाया जाएगा तथा कुशल मजदूरों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिलाया जाएगा। वहीं शासन ने संबल योजना को पुनः प्रारंभ किया है। अब प्रवासी मजदूरों को भी इस योजना से जोड़ रहे हैं। यह योजना गरीबों के लिए वरदान है। इसके अंतर्गत गरीबों के बच्चों की फीस, बच्चे के जन्म व उसके पश्चात मां को 16 हजार रुपए की राशि, बच्ची के विवाह की व्यवस्था, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख तथा अंतिम संस्कार के लिए 5 हजार रुपए प्रदाय किए जाते हैं।

श्रम सिद्धि अभियान के तहत अच्छा कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को 2 लाख रुपए का प्रथम, एक लाख रुपए का द्वितीय तथा 50 हजार रुपए का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार सबसे ज्यादा जॉब कार्ड बनवाने, सबसे ज्यादा मजदूरों को काम पर लगवाने, सबसे ज्यादा कार्य प्रारंभ करवाने, सबसे ज्यादा स्थाई महत्व की संरचनाएं बनवाने तथा श्रेष्ठ गुणवत्ता के कार्यों के लिए दिए जाएंगे।

मजदूरों, किसानों और गरीबों की सहायता की

मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना संकट के दौरान शासन द्वारा निरंतर प्रदेश के मजदूरों, किसानों, गरीबों आदि की निरंतर सहायता की गई। मजदूरों को उनके खातों में राशि भिजवाई गई, बच्चों को छात्रवृत्ति की राशि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को दो माह की अग्रिम पेंशन, सहरिया, बैगा, भारिया जनजाति की बहनों को राशि, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों, मध्यान्ह भोजन के रसोईयों आदि को राशि उनके खातों में अंतरित की गई। किसानों को फसल बीमा की राशि, शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण तथा गेहूं उपार्जन की राशि उनके खातों में भिजवाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे मजदूरों, गरीबों, किसानों में भगवान दिखाई देते हैं। इनकी सेवा मेरे लिए भगवान की सेवा है। हमने विभिन्न प्रदेशों में फंसे हुए हमारे मजदूरों को प्रदेश लाने के साथ ही अन्य प्रदेशों के मध्यप्रदेश में आए तथा यहां से गुजरने वाले मजदूरों की भी पूरी सहायता की। मुख्यमंत्री ने सरपंचों को बताया कि शासन द्वारा प्रत्येक गांव में पहले तीन माह का उचित मूल्य राशन प्रदाय किया गया था। अब दो माह का निःशुल्क राशन प्रदान किया गया है। यह राशन, राशन कार्डधारियों के अलावा उन्हें भी दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। सरपंच यह सुनिश्चित करें कि पात्र व्यक्तियों तक राशन पहुंच जाए।

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश की 22 हजार 809 ग्राम पंचायतों में से 22 हजार 695 में मनरेगा के कार्य चल रहे हैं। इन कार्यों में अभी तक 21 लाख एक हजार 600 मजदूरों को रोजगार दिया गया है, जो कि गत वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना है। गौरतलब है कि प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के साथ ही अन्य बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज के क्रियान्वयन के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने वाला मप्र पहला राज्य बना है। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों तथा रोजगार की तलाश में बाहर गए श्रमिकों को वापस आने पर उनके गांव और ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए कृत संकल्पित है। इसके लिए मनरेगा योजना के तहत बड़े स्तर पर रोजगार मूलक कार्य प्रारंभ किए गए हैं। इन कार्यों में नए श्रमिकों को जोड़ा जाएगा। इसी कड़ी में 22 मई को मनरेगा रोजगार कार्ड वितरण महाअभियान श्रम सिद्धि अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। कोई नहीं रहेगा बेरोजगार सबको मिलेगा रोजगार अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों के मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। सरकार ने तय किया है कि मनरेगा में मंदिर सरोवर, मंदिर उद्यान और मंदिर गौशाला भी बनेगी।

गौशाला का संचालन मंदिर द्वारा किया जाएगा।

श्रम सिद्धि अभियान के तहत श्रमिकों का विभिन्न श्रेणियों में पंजीयन किया जाएगा और उन्हें उसके अनुरूप रोजगार मुहैया कराया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कोरोना के कारण आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप होने से सरकार के पास भी पैसे की तंगी है, लेकिन गरीबों और श्रमिकों के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भी मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराने पैसा दे रही है। सभी श्रमिक इसका लाभ उठाएं और गांवों में बेहतर गुणवत्ता के साथ ऐसे कार्य किए जाएं, जो गांवों के लिए उपयोगी हों।

मप्र के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि प्रदेश में हर **जरूरतमंद को काम** मिलेगा। प्रदेश में इस समय जरूरतमंद श्रमिकों को काम की आवश्यकता है, जिससे उनकी रोजी-रोटी का ठीक से प्रबंध हो सके। इस उद्देश्य को देखते हुए सरकार मनरेगा के तहत हर जरूरतमंद को रोजगार की व्यवस्था कर रही है। प्रदेश में गौशाला निर्माण, मंदिर सरोवर, मंदिर उद्यान के अधिकाधिक कार्य मनरेगा के अंतर्गत किए जाएंगे। मंदिर गौशाला के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए ग्रामीण विकास और पशुपालन विभाग संयुक्त रूप से कार्यवाही करेंगे। मिश्रा कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि मनरेगा के अंतर्गत ऐसी संरचनाएं निर्मित की जाएं जिनमें बारिश में भी कार्य संभव हो सकें। इन कार्यों में मशीनों का प्रयोग न किया जाए। इसके साथ ही स्थायी प्रभाव वाले कार्य संपन्न हों। स्टाप डेम, चेक डेम, सरोवर निर्माण, खेत तालाब, मेड़ बंधान, नंदन फलोद्यान जैसे कार्य करवाए जाएं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में श्रमिकों को मनरेगा कार्यों से रोजगार का बड़ा सहारा मिल रहा है। वर्तमान में प्रदेश की 22 हजार 809 ग्राम पंचायतों में से 22 हजार 695 में मनरेगा के कार्य चल रहे हैं। इन कार्यों में अभी तक 21 लाख एक हजार 600 मजदूरों को रोजगार दिया गया है, जो कि गत वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना है। यहां तक कि साढ़े सत्रह हजार दिव्यांग भी कार्यों से जुड़े हैं। प्रति

ग्राम पंचायत औसतन 90 श्रमिक काम कर रहे हैं। कोरोना संकट के समय एक अप्रैल से लेकर अभी तक 35 लाख 45 हजार 242 मजदूरों को मनरेगा अंतर्गत रोजगार प्रदान किया गया है। इसमें 42.2 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार दिया गया है।

कोरोना संक्रमण के कारण हो रही मजदूरों की घर वापसी से पंचायतों में काम की डिमांड बढ़ गई है। प्रदेश में हर दिन करीब 60 से 70 हजार मजदूर मनरेगा में काम मांग रहे हैं। वहीं, मजदूरों के काम की डिमांड के चलते निर्माण कार्य और विकास की गति बढ़ा दी गई है। क्योंकि, इन मजदूरों को काम देने की जिम्मेदारी पंचायत एवं ग्राम सहायकों को दी गई है। प्रदेश में करीब 68 लाख जॉब कार्डधारी परिवार हैं। इसमें से 30 अप्रैल तक 10 लाख परिवार मजदूरों ने ही काम मांगा था। पंचायत विभाग ने इन मजदूरों को उनके घर के पास काम उपलब्ध भी करा दिया था। 30 अप्रैल के बाद से काम की डिमांड एकदम बढ़ने लगी है।

गांवों में सभी विभागों से जुड़े अधोसंरचना के काम तैयार किए जाएंगे, इससे जहां गांव का विकास होगा। वहीं, जॉब कार्डधारी परिवारों को काम भी मिलेगा। इसके अलावा पंचायतें खुद मजदूरों को काम देने के लिए गांव के विकास कार्यों को प्रारंभ करेंगे। इसके साथ ही केंद्र और राज्य के हितग्राही मूलक योजनाओं जैसे शौचालय, सड़क, नाली निर्माण, पुल-पुलिया, प्रधानमंत्री आवास, सामुदायिक, पंचायत भवन सहित अन्य कार्य भी प्रारंभ किए जाएंगे, जिससे 100 फीसदी मजदूरों को पर्याप्त काम मिल सके।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों के विकास और मजदूरी के लिए 20 हजार करोड़ का बजट रखा है। अधिकारियों का मानना है कि करीब 30 से 40 लाख मजदूर काम की डिमांड करेंगे। इसके लिए पंचायत स्तर पर विकास कार्यों के साथ मजदूरों को काम उपलब्ध कराने की रूपरेखा तैयार की है। बाहरी राज्यों से मध्यप्रदेश में वापस लौटे करीब 12 लाख से ज्यादा मैनपॉवर अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। अभी तक इन मजदूरों को काम देने को लेकर सरकार मनरेगा के अलावा दूसरे विकल्पों पर विचार नहीं कर पाई है, लेकिन यदि इस मैनपॉवर को मध्यप्रदेश सरकार रोक लेती है तो यह प्रदेश के विकास में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। दूसरी ओर यदि इस मैनपॉवर को काम नहीं मिल पाता तो यह उतनी ही ज्यादा समस्या भी साबित होंगे। सरकार का दावा है कि वर्तमान में 20 लाख मजदूर मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर पूर्व से मध्यप्रदेश में ही रहने वाले मजदूर हैं।

● **कुमार राजेन्द्र**

मनरेगा में हर प्रवासी मजदूर को मिलेगा काम

उधर, कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दावा है कि इस संक्रमण काल में मनरेगा प्रवासी मजदूरों के लिए संजीवनी बनेगी। मजदूरों के अपने गांव लौटने के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सरकार के समक्ष चुनौतियों से संबंधित सवाल का जबाव देते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार ने मनरेगा बजट में 40 हजार करोड़ रुपए की राशि दी है। जिनके पास कार्ड नहीं है, ऐसे मजदूरों को जॉब कार्ड मुहैया कराने के लिए राज्य की सरकारों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। तोमर ने बताया कि पहली बार किसी वित्त

वर्ष में मनरेगा अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि व्यय की जाएगी। क्योंकि कोविड-19 की स्थिति नियंत्रित होने पर गांव लौटे लोग अपने पुराने रोजगार पर भी वापस लौट जाएंगे, लेकिन संभावना है कि कुछ गांवों में ही रहने का फैसला कर सकते हैं। चूंकि, इनमें से ज्यादातर कुशल मजदूर है, इसलिए सरकार को भरोसा है कि इनसे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसको देखते हुए ही भारत सरकार ने इनके लिए पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने की योजना पर काम शुरू कर दिया है।

उम्मीदवारों की तलाश बड़ी चुनौती

ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती ग्वालियर-अंचल में जिताऊ उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने की है। इस चुनौती से निपटने के लिए कमलनाथ लॉकडाउन के बीच पार्टी नेताओं से लगातार संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद अंचल में उभरे नए राजनीतिक समीकरण भी कमलनाथ की परेशानी की वजह हैं।

मध्य प्रदेश में पहली बार एक साथ 24 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है। विधानसभा की खाली सीटों को भरने की छह माह की अवधि सितंबर में समाप्त होगी। चुनाव आयोग को सितंबर से पहले उपचुनाव संपन्न कराना है। 22 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक 22 कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे के कारण हो रहे हैं। दो सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली हुई हैं। ये सीटें आगर और जौरा की हैं। जौरा विधानसभा क्षेत्र सिंधिया के प्रभाव वाले मुरैना जिले में आता है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर सिंधिया समर्थक बनवारी लाल शर्मा चुनाव जीते थे। कांग्रेस ने हमेशा ही इस सीट पर सिंधिया की पसंद के आधार पर टिकट दिया है। ग्वालियर-चंबल अंचल में जौरा के अलावा 14 अन्य सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होना है। सबसे ज्यादा पांच सीटों पर उपचुनाव मुरैना जिले में ही होना है। मुरैना केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का निर्वाचन क्षेत्र भी है।

प्रदेश में दलबदल के कारण हुए सत्ता परिवर्तन में दिग्विजय सिंह समर्थक ऐंदल सिंह कंसाना और बिसाहूलाल सिंह भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। कंसाना मुरैना जिले के सुमावली से और बिसाहूलाल सिंह अनूपपुर से विधायक थे। बिसाहूलाल सिंह आदिवासी वर्ग से हैं। नौ सीटें अनुसूचित जाति वर्ग की हैं। इनमें आठ सीटें सिंधिया समर्थकों की हैं। ग्वालियर-अंचल की कुल पंद्रह सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होना है। कांग्रेस के लिए इन सीटों पर मजबूत उम्मीदवार तलाश करना काफी चुनौतीपूर्ण है। पिछले चार दशक से कांग्रेस इस क्षेत्र में टिकटों का वितरण महल की पंसद के आधार पर करती रही है। अंचल में पहली बार कांग्रेस सिंधिया राज परिवार के बगैर चुनाव मैदान में होगी। इससे पूर्व एक बार माधवराव सिंधिया ने भी कांग्रेस छोड़ी थी। पीवी नरसिंहाराव उस वक्त प्रधानमंत्री थे। लेकिन, उस दौरान विधानसभा का कोई चुनाव नहीं हुआ था। सिर्फ लोकसभा का ही चुनाव हुआ था। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। इस बार पूरा सिंधिया राज परिवार एक साथ भारतीय जनता पार्टी में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी से विधायक हैं। शिवपुरी जिले में दो विधानसभा क्षेत्र करैरा और पोहरी में उपचुनाव होना है। बुआ और भतीजे के एक ही दल में होने के कारण इस बार महल समर्थकों के बीच चुनाव को लेकर किसी तरह के भ्रम की स्थिति नहीं है।

भाजपा के असंतुष्टों को तोड़ने की कोशिश

सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने से भाजपा का गणित भी गड़बड़ा गया है। भाजपा के जो नेता परंपरागत तौर पर सिंधिया और उनके समर्थकों के विरोध की राजनीति कर रहे थे, वे अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा नाराज नेताओं को मनाने में लगे हुए हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी के तेवर भी तीखे हैं। मनोज चौधरी के भाजपा में शामिल होने से पार्टी के भीतर ही उनका एक प्रतिस्पर्धी आ गया है। मनोज चौधरी ने हाट पिपल्या विधानसभा सीट पर दीपक जोशी को ही हराया था। उपचुनाव में मनोज चौधरी को पार्टी फिर टिकट दे रही है। इससे जोशी नाराज हैं। शर्मा से मुलाकात के बाद जोशी ने अभी चुप्पी साध रखी है। कमलनाथ, जोशी के भाजपा छोड़ने की संभावनाओं को भी तलाश कर रहे हैं। इंदौर में सिंधिया के कट्टर समर्थक तुलसी सिलावट को घेरने के लिए प्रेमचंद्र गुड्डू को कांग्रेस में वापस लिए जाने की संभावना बन रही है। गुड्डू कहते हैं कि मैंने फरवरी में भाजपा छोड़ दी है। सिंधिया के एक अन्य कट्टर समर्थक गोविंद राजपूत को घेरने के लिए सागर जिले के भाजपा नेताओं को तोड़ने की कोशिश चल रही है। मध्यप्रदेश भाजपा के प्रवक्ता आशीष अग्रवाल कहते हैं कि भाजपा का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी यह अच्छी तरह जानता है कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने से सबसे ज्यादा खुश वे नेता हैं, जो पिछले चार दशक से पार्टी में महल विरोधी राजनीति कर रहे हैं। सिंधिया को घेरने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ महल विरोधी नेताओं से सलाह-मशवरा भी कर रहे हैं। सिंधिया के प्रभाव वाले जिलों में कांग्रेस के नए अध्यक्ष नियुक्त भी कर दिए हैं। ग्वालियर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष अशोक सिंह को बनाया गया है। अशोक सिंह के कारण कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच दूरी बननी शुरू हुई थी। अशोक सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं। दिग्विजय सिंह की अनुशंसा पर ही कमलनाथ ने अशोक सिंह को मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का अध्यक्ष बनाया था। शिवपुरी में कट्टर विरोधी श्रीप्रकाश शर्मा को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। श्योपुर और गुना जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बदल दिए गए हैं। सिंधिया के गढ़ शिवपुरी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्रीप्रकाश शर्मा कहते हैं कि यदि यह उनका गढ़ होता तो लोकसभा का चुनाव वे नहीं हारते।

सिंधिया परिवार के **प्रभाव से मुक्त** होते ही ग्वालियर-चंबल अंचल में अपना-अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में कांग्रेस के दिग्गज नेता लगे हुए हैं। सिंधिया के बाद इस अंचल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और अजय सिंह के समर्थकों की संख्या ज्यादा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहली बार इस अंचल में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए सक्रिय हुए हैं। कमलनाथ की नजर उन नेताओं पर है, जो अब तक मुख्यधारा में नहीं आ सके हैं। किसी दौर में सुरेश पचौरी के समर्थक रहे पूर्व मंत्री राकेश चतुर्वेदी को कमलनाथ आगे बढ़ा रहे हैं। राकेश चतुर्वेदी वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। लोकसभा चुनाव के समय वापस लौटे हैं। सिंधिया ने कांग्रेस में वापसी कराई थी। चतुर्वेदी को मेहगांव विधानसभा सीट से टिकट दिए जाने की चर्चा है। चतुर्वेदी को टिकट दिए जाने का विरोध अजय सिंह और गोविंद सिंह कर रहे हैं। बताया जाता है कि उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए कमलनाथ द्वारा बुलाई गई बैठक में अजय सिंह ने कहा कि यदि दलबदलुओं को टिकट दिया गया तो वे पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होंगे। कमलनाथ उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार में वापसी की एक और कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के रवैए से राह मुश्किल होती जा रही है।

● **भोपाल से रजनीकांत पारे**

देश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में होती है जो संतुलित, संगठित, संयमित और सहज भाव से राजनीति करते हैं। लेकिन इस बाद वे बदले-बदले नजर आ रहे हैं। उनमें न तो पहले जैसे तेवर हैं और न ही ऊर्जा। इससे ऐसा लग रहा है जैसे वे राजनीतिक दबाव में हैं।

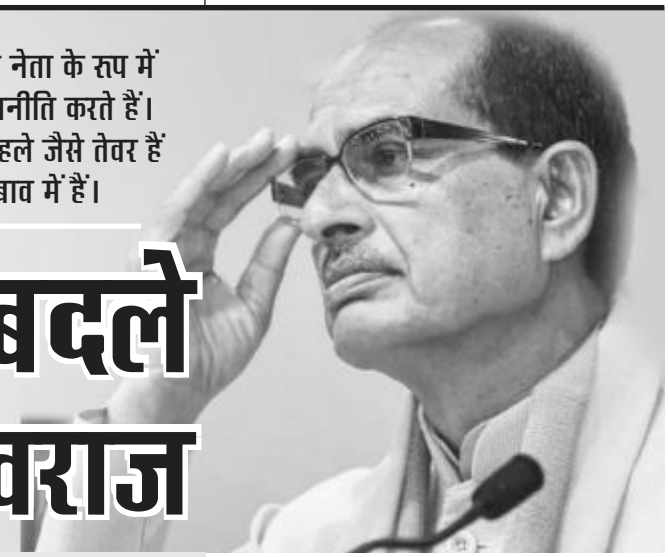

इस बार बदले-बदले नजर आ रहे शिवराज

15 माह पुराने कमलनाथ सरकार के पतन के बाद शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री का पद संभाला तो उनके चेहरे पर पहले की तरह ऊर्जा और आभा नजर आई। उन्होंने इसी तेवर के साथ करीब 1 महीने तक सत्ता का संचालन किया, लेकिन 21 अप्रैल को मंत्रिमंडल गठन के साथ ही उनके तेवर बदल गए। इससे ऐसा लग रहा है जैसे वे किसी दबाव में हैं। सूत्रों की मानें तो इस बार आलाकमान की तरफ से उन्हें फ्री हैंड नहीं मिला है। इसलिए वे गाइडलाइन में बंधकर काम कर रहे हैं। इसका असर यह हो रहा है कि शासन के साथ ही प्रशासन में भी उनकी धमक फीकी पड़ गई है।

इसके इतर अगर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 15 माह के शासनकाल को देखें तो उसमें और शिवराज सिंह चौहान के इस शासनकाल में जमीन-आसमान का अंतर नजर आ रहा है। जहां शिवराज सिंह चौहान की ब्यूरोक्रेसी पर कमांड नजर नहीं आ रहा है, वहीं कमलनाथ के सामने पूरी ब्यूरोक्रेसी नतमस्तक रहती थी। कमलनाथ ने 15 माह के शासनकाल के दौरान भले ही जिलों में दस्तक नहीं दी, लेकिन मंत्रालय से लेकर जिला प्रशासन तक में उनकी धमक दिखाई देती थी। जानकारों का कहना है कि केंद्र सरकार में मंत्री रहने के कारण कमलनाथ को इसका अनुभव पर्याप्त है कि नौकरशाही पर किस तरह नियंत्रण रखा जाए। हालांकि इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। कमलनाथ नौकरशाही पर नकेल कसने में लगे रहे और उनका कुनबा उनके नियंत्रण से बाहर होता चला गया।

जहां तक शिवराज सिंह चौहान की इस पारी का सवाल है तो अभी तक यह देखने को मिला है कि उनका न तो शासन पर और न ही प्रशासन पर नियंत्रण है। सरकार में जो 5 मंत्री शामिल हैं। उन्हें देखकर यह तो साफ दिखता है कि उन पर मुख्यमंत्री का नियंत्रण नहीं है। क्योंकि वे अलग-अलग गुटों से आए हुए हैं। दरअसल, कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार से सत्ता छीनने के लिए भाजपा ने जिस तरह एड़ी-चोटी का जोर लगाया था, अलग-अलग गुटों को साथ लेकर चलना उसकी मजबूरी थी। सरकार बन जाने के बाद ये सभी गुट सत्ता में अपने प्रतिनिधित्व को लेकर उतावले हो रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज चाहकर भी सभी गुटों को संतुष्ट नहीं कर सकते। ऐसे में पार्टी आलाकमान ने बीच का रास्ता निकाला, जिसमें सभी गुटों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व देकर उन्हें साधने की कोशिश की गई है। जिन पांच मंत्रियों ने शपथ ली है उसमें कमल पटेल का नाम चौंकाने वाला है। कमल पटेल पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के खेमे के माने जाते हैं। शिवराज की पिछली सरकार में भी मंत्री रहे हैं। उस दौरान उन्होंने अपनी ही सरकार पर अवैध खनन को लेकर कई तरह के आरोप लगाए थे, जिसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज की फजीहत हो चुकी है। माना जा रहा था कि शिवराज उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है।

यही हाल मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद को भी देखकर लग रहा है। पिछले एक माह से अधिक समय से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगाई जा रही हैं। सूची बनने और बिगड़ने की खबरें आ रही हैं। जिस तरह मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर रोज समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि इस सरकार में शिवराज सिंह चौहान की भी नहीं चल पा रही है। दरअसल, भाजपा सूत्रों की मानें तो इस बार की शिवराज सिंह चौहान की सरकार में भाजपा, संघ और सिंधिया की तिकड़ी का जोर है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि तीनों में संतुलन साधने में शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा को रोज पसीना बहाना पड़ रहा है। आलम यह है कि शिवराज सिंह चौहान को कई मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है। जहां एक तरफ उन्हें कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ रही है वहीं उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार के लिए संतुलन बनाना पड़ रहा है। उसके ऊपर आलम यह है कि अफसरों को भी साधना पड़ रहा है। इस तरह कई मोर्चों पर जूझ रहे शिवराज सिंह चौहान के लिए इस बार सरकार चलाना चुनौती भरा काम है। अब देखना यह है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में वे अपने पसंदीदा विधायकों को मंत्री बनवा पाते हैं या नहीं।

● **जितेन्द्र तिवारी**

ब्यूरोक्रेसी पर कमांड नहीं

अपनी चौथी पारी में शिवराज सिंह चौहान फ्री हैंड होकर काम नहीं कर पा रहे हैं। इसका असर यह हो रहा है कि ब्यूरोक्रेसी निरंकुश हो गई है। खासकर इनके इस शासनकाल में महिला आईएएस अधिकारियों की निरंकुशता तो हद पार कर रही है। अभी हाल ही में कोरोना संक्रमण के इस दौर में सागर और खंडवा कलेक्टर की लापरवाही सामने आ चुकी है। सरकार के निर्देशों के बाद भी सागर की कलेक्टर रहीं प्रीति मैथिल और खंडवा की कलेक्टर रहीं तन्वी सुद्रियाल ने कोरोना संक्रमण के लिए जारी निर्देशों का पालन नहीं किया। इन दोनों के खिलाफ स्थानीय नेताओं ने भी शिकायत की। उसके बाद मुख्यमंत्री इन्हें हटाने के लिए मजबूर हुए। वहीं दो अन्य जिलों रतलाम और शिवपुरी की कलेक्टर की भी शिकायतें सरकार के पास पहुंच रही हैं। सूत्र बताते हैं कि रतलाम कलेक्टर रुचिका चौहान की भी विदाई की तैयारी कर ली गई है। जल्द ही उनके स्थान पर किसी अन्य को पदस्थ किया जा सकता है। वहीं शिवपुरी कलेक्टर अनुग्रह पी. की भी कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर महिला कलेक्टर सरकार के निर्देशों का पालन क्यों नहीं कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं इन महिला अफसरों पर किसी और का प्रभाव है।

विवादों का फ्लाईओवर

लोकसभा चुनाव के पहले 22 फरवरी 2019 को जबलपुर में जिस बहुप्रतिक्षित मध्यप्रदेश के सबसे बड़े फ्लाई ओवर की आधारशिला खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रखी थी वह एक बार फिर विवादों में फंसती नजर आ रही है। हालांकि स्वॉइल टेस्टिंग से फ्लाइओवर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यह काम एनसीसी कंपनी करवा रही है, जिसे इस फ्लाई ओवर को बनाने का ठेका मिला है। उधर, टेंडर प्रक्रिया से अयोग्य घोषित की गई यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी हाईकोर्ट पहुंच गई है। कंपनी ने आरोप लगाया है कि टेंडर प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार करते हुए उसे अयोग्य घोषित कर ज्यादा बोली वाली एनसीसी को यह काम दिया गया है। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है।

गौरतलब है कि जबलपुर के दमोह नाका से लेकर मदन महल तक बनने वाले इस ऐलिवेटिड फ्लाइओवर का निर्माण करीब 7 किलोमीटर लंबाई का होगा जिसकी लागत 758.54 करोड़ है। बार-बार टेंडर की प्रक्रिया और राजनीति की भेंट चढ़ी इस कार्ययोजना के निर्माण का ठेका एनसीसी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। जानकारी के अनुसार मामला कोर्ट में है फिर भी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने एनसीसी से स्वॉइल टेस्टिंग का कार्य शुरू करा दिया है। करीब दो सौ प्वाइंटस पर स्वॉइल टेस्टिंग का काम किया जाएगा। पूरे फ्लाइओवर में करीब 200 पिलर खड़े किए जाएंगे जिसकी स्वॉइल टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद गहराई का काम किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जब मामला हाईकोर्ट में चल रहा है तो विभाग को इतनी हड़बड़ी क्यों है? इसमें कहीं न कहीं मिलीभगत और भ्रष्टाचार की बू आ रही है।

गौरतलब है कि दमोह नाका से मदनमहल के बीच बनने वाले फ्लाईओवर की टेंडर प्रक्रिया से अयोग्य घोषित यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी ने पूरी प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने विगत दिनों मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई के बाद राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

लखनऊ (उप्र) की यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि जबलपुर के दमोह नाका से मदन महल तक प्रस्तावित फ्लाई ओवर बनाने के लिए बुलाई गई निविदा में उसने भी टेंडर भरा था। 11 मार्च को याचिकाकर्ता कंपनी को उसके एक कर्मचारी पर दर्ज आपराधिक मुकदमे की जानकारी छिपाने के आरोप में इस टेंडर की प्रक्रिया से अयोग्य ठहरा दिया गया था। याचिकाकर्ता कंपनी का दावा है कि जिस मुकदमे को आधार बनाकर उसे टेंडर से अयोग्य घोषित किया गया, उस मुकदमे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। ऐसे में निविदा जमा करते समय कंपनी के खिलाफ कोई प्रकरण लंबित नहीं था। ऐसे में 6 मार्च को उसे अयोग्य घोषित किया जाना न्याय संगत नहीं है। कंपनी का यह भी दावा है कि फ्लाई ओवर के निर्माण का ठेका एक ऐसी कंपनी को दे दिया गया, जिसकी राशि याचिकाकर्ता से 85 करोड़ रुपए अधिक है। इस टेंडर की वजह से सरकार पर 85 करोड़ रुपए के भुगतान का अनावश्यक भार पड़ेगा। याचिका में मप्र सरकार के लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव, चीफ इंजीनियर, हैदराबाद की एनसीसी लिमिटेड और मुंबई की एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को पक्षकार बनाया गया है। अभी हाईकोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन अफसरों ने आनन-फानन में फ्लाई ओवर का काम शुरू करवा दिया है।

गौरतलब है कि मार्च 2019 में भी इस फ्लाई ओवर का टेंडर रद्द हो चुका है। इसके पीछे की वजह ठेकेदार द्वारा की जा रही लापरवाही बताई जा रही है। ज्ञात हो कि जब से मदनमहल से दमोह नाका फ्लाई ओवर निर्माण की बात की जा रही थी कुछ ना कुछ परेशानी सामने आ रही थी। पहले रेलवे ने भी अपनी जमीन पर दो खंभे लगाने की परमिशन देने से मना कर दिया था। उसके बाद मार्च 2019 में फ्लाई ओवर निर्माण का टेंडर जिस कंपनी को दिया गया था, उसे रद्द कर दिया गया था। बताया जाता है कि पीडब्ल्यूडी ने गुजरात की एजेंसी रंजीत बिल्डकॉन को इसका टेंडर दिया था। लेकिन कंपनी ने ठेका लेकर मप्र लोक निर्माण विभाग से अनुबंध नहीं किया था। इसलिए पीडब्ल्यूडी ने यह ठेका निरस्त करके कंपनी द्वारा जमा 616 लाख रुपए जब्त कर लिए।

● **जबलपुर से सिद्धार्थ पाण्डे**

भवन विशेषज्ञों के हवाले परियोजना

सूत्र बताते हैं कि इस बहुप्रतीक्षित परियोजना में हर स्तर पर गलती हुई है। दरअसल, इस परियोजना का संपादन मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु परिक्षेत्र भोपाल के अधीनस्थ अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग जबलपुर को करना था क्योंकि यह प्रोजेक्ट सेतु विभाग के ही इंजीनियर पूरा करने में सक्षम होते हैं दूसरे नहीं। परंतु दलाली के चक्कर में परियोजना को पूरा करने के लिए सेतु विशेषज्ञों से हटाकर भवन विशेषज्ञों अर्थात कार्यपालन यंत्री जबलपुर संभाग भवन, रोड-2 को सौंप दिया गया। सरकार द्वारा अनुमोदित मंत्री समूह की समिति ने इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग से कराने की अनुशंसा की थी। परंतु तत्कालीन कमलनाथ सरकार के एक स्थानीय मंत्री ने इसे अपने अधिक फायदे के लिए लोक निर्माण भवन, सड़क विभाग के कार्यपालन यंत्री को उपकृत करने के लिए सेतु विभाग के बजाय लोक निर्माण विभाग भवन, सड़क के लोक निर्माण संभाग 2 जबलपुर को स्थानांतरित कर दिया। हालांकि सरकार बदलने के बाद लगातार मिल रही शिकायतों के चलते 24 अप्रैल को पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन प्रमुख अभियंता मेहरा ने आदेश निकालकर प्रोजेक्ट को मुख्य अभियंता लोक निर्माण सेतु परिक्षेत्र भोपाल के अंतर्गत अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री सेतु संभाग लोक निर्माण विभाग जबलपुर द्वारा संपादित कराने को कहा। परंतु 29 अप्रैल को उपरोक्त आदेश निरस्त कर दिए गए और कहा गया कि फ्लाई ओवर का काम अब भवन, सड़क संभाग-2 के अधीक्षण, कार्यपालन यंत्री द्वारा संपादित किया जाएगा। 6 मई को रातो-रात चार्ज भी हैंड ओवर करने के आदेश के बाद अब सेतु निर्माण का काम सेतु के इंजीनियर के बजाय भवन, सड़क के कार्यपालन यंत्री गोपाल गुप्ता द्वारा संपादित किया जा रहा है।

सरकार पिलाएगी शुद्ध पानी

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को मप्र में साकार करने के लिए प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इस योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हर घर में नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। योजना के प्रथम चरण में 1 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से करीब 1500 करोड़ रुपए के बजट की मांग की। इस साल करीब 20 लाख कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके लिए पुरानी नल-जल योजनाओं का सहारा लिया जाएगा। यह जानकारी देते हुए लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव ने बताया कि योजना का खाका तैयार करने और योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित कर दी गई है। इससे लगने लगा है कि अब तक ठंडे बस्ते में पड़ी यह योजना जल्द ही आकार लेनी शुरू कर देगी।

गौरतलब है कि मप्र के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अब यह समस्या जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि प्रदेश सरकार राष्ट्रीय जल मिशन के तहत हर घर में नल का सपना साकार करने जा रही है। यह अंशदायिनी योजना है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कुल खर्च में आधे-आधे का अंशदान होगा। इस योजना के तहत मुख्य पाइप लाइन से हितग्राही के घर तक कनेक्शन के लिए पंचायत कुल खर्च का सामान्य वर्ग से 10 प्रतिशत और एससी-एसटी से 5 प्रतिशत लेगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए एक पैनल बनाया जाएगा, जिसमें कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला समिति और पंचायतों की एक उपसमिति भी शामिल होगी। यह पैनल योजना का रेट तय करेगा। उसके बाद लघु उद्योग निगम के माध्यम से टेंडर निकाला जाएगा। इस योजना को 4 साल में पूरा करना है। प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत काफी सक्रिय हैं। इसकी वजह यह है कि वे एक पीएचई के इंजीनियर के पुत्र हैं। अत: उन्हें देशभर में पेयजल की स्थिति का पूरा ज्ञान है।

गौरतलब है कि केंद्र द्वारा लक्ष्य को वर्ष 2024 के स्थान पर वर्ष 2023 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, तदानुसार योजना का पुनर्निर्धारण कर मिशन मोड में कार्य किया जाएगा। इस वर्ष केंद्र सरकार मिशन के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश को 1280 करोड़ रुपए का बजट देगी। इतनी ही राशि राज्य सरकार मिलाएगी। इसके साथ इस बार मध्यप्रदेश को लगभग 6500 करोड़ रुपए मनरेगा के अंतर्गत प्रदाय किए जाएंगे। मनरेगा में 65 प्रतिशत राशि जल संबंधी कार्यों के लिए खर्च की जानी है। अत: इसमें से भी कुछ राशि का उपयोग जल जीवन मिशन के लिए किया जा सकता है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में घर पर नल के माध्यम से जल प्रदाय से शेष लगभग 85 प्रतिशत (103.67 लाख) परिवारों को एफएचटीसी (फंक्शनल हाऊसहोल्ड टैप कनेक्शन) के माध्यम से वर्ष 2023-24 तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है। इस योजना के तहत मवेशियों के लिए भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

पीएचई के प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव ने बताया कि भारत के कुल क्षेत्रफल में 2 प्रतिशत जमीन, 4 प्रतिशत पानी, 15 प्रतिशत जानवर और 18 प्रतिशत मनुष्य हैं। विभागीय सूत्रों का कहना है कि प्रदेश के कुल 321 गुणवत्ता प्रभावित गांवों में शुद्ध पेयजल इस वर्ष के अंत तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। वर्ष 2020-21 की प्रस्तावित कार्ययोजना में अधिक से अधिक अजा-अजजा बाहुल्य गांवों में कार्य प्रारंभ कराए जाएंगे। सांसद आदर्श ग्राम तथा आकांक्षी जिलों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। जल निगम द्वारा 1231 करोड़ की 19 समूह योजनाओं को पूरा कर लिया गया है, जिनके माध्यम से प्रदेश के 805 गांवों में 1 लाख 31 हजार से अधिक क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान किए गए हैं। जल निगम के अंतर्गत वर्तमान में 39 समूह योजनाओं में 8 हजार 375 करोड़ रुपए के कार्य प्रगति पर हैं। नल-जल योजनाओं के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता का पेयजल गांव में मिल सके इसके लिए जिलों की जल प्रयोगशालाओं का चरणबद्ध तरीके से एनएबीएल प्रमाणीकरण कराया जाएगा।

● **नवीन रघुवंशी**

क्या है जल जीवन मिशन?

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शत-प्रतिशत परिवारों को अच्छी गुणवत्ता का पेयजल निरंतर एवं पर्याप्त मात्रा में प्रदाय कराने के लिए जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर में क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से 55 लीटर शुद्ध पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाना निर्धारित किया गया। अब इस लक्ष्य को पूर्ण करने की समय-सीमा वर्ष 2023 कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 'जल जीवन मिशन' पर साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इस मिशन के तहत 2024 तक हर घर में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से आगे आने और जल संसाधनों के संरक्षण में योगदान देने का भी आग्रह किया। जल जीवन मिशन की शुरुआत 2050 की आवश्यकता को ध्यान में रखकर की गई है। योजना के तहत पानी की उपलब्धता 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है। वर्षा जल के संचयन के लिए पारंपरिक जल स्त्रोतों के कायाकल्प और आधारभूत संरचना के विकास को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने घरों से निकलने वाले अशुद्ध जल को कृषि में इस्तेमाल करने की योजना तैयार की है, ताकि अशुद्ध जल को नदियों में गिरने से रोका जा सके। मोदी सरकार ने ग्राउंड वॉटर को रिचार्ज करने का फैसला किया है। इसके लिए 25 दिसंबर, 2019 को अटल भू-जल योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य भू-जल स्तर को ऊपर उठाना है। योजना पर छह हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना से सात राज्यों के 8,350 गांवों को फायदा होगा।

मास्टर स्ट्रोक

मप्र में 24 विधानसभा सीटों पर आने वाले समय में होने वाला उपचुनाव किसी महायुद्ध से कम नहीं होगा। दरअसल, इन सीटों के चुनाव परिणाम सरकार की दिशा और दशा तय करेंगे। इसके लिए अभी से रणनीति बनने लगी है। तू डाल-डाल, मैं पाथ-पाथ की तर्ज पर भाजपा और कांग्रेस गोटियां बिछा रही है। हालांकि मैदानी तैयारी में भाजपा कांग्रेस से फिलहाल काफी आगे है।

मध्य प्रदेश की सियासत में आगामी विधानसभा उप चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब साफ तौर पर दिखने लगी हैं। जैसे-जैसे कोरोना फीवर कम हो रहा है, राजनीति गहरी होती जा रही है। ऐसे समय में उपचुनाव से ठीक पहले मप्र भाजपा ने ग्वालियर-चंबल की 16 सीटों पर मास्टर स्ट्रोक खेला है। भाजपा ने तीन राज्यों को जोड़ने वाले 'चंबल एक्सप्रेस-वे' का नाम बदलकर 'चंबल प्रोग्रेस-वे' कर दिया है। इस प्रोजेक्ट का काम जल्द शुरू होगा और इसके लिए भूमिपूजन का ऐलान भी जल्दी ही होगा। माना जा रहा है कि 24 सीटों पर उपचुनाव के कारण सरकार इसे लेकर हड़बड़ी में दिखाई दे रही है क्योंकि 16 विधानसभा सीटें इसी ग्वालियर चंबल इलाके में हैं। इसके बाद कांग्रेस भी अलर्ट मोड पर आ गई है और मुख्यमंत्री शिवराज एवं भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर झूठ बोलकर **प्रोजेक्ट का क्रेडिट** लेने का गंभीर आरोप लगाया है।

दरअसल, केंद्र सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के मुरैना से राजस्थान के कोटा तक 352 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस-वे बनाया जाना है। इस प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने और जमीन अधिग्रहित करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है लेकिन इसे बनाने का दारोमदार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जिम्मे है। चंबल प्रोग्रेस-वे से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित तीन जिलों को आपस में जोड़ा जाना है। 8 लेन का ये एक्सप्रेस-वे चंबल नदी के किनारे बनाया जाना प्रस्तावित है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से राज्य सरकार ने सहमति ले ली है।

ये भी बता दें कि चंबल-प्रोग्रेस-वे ग्वालियर चंबल इलाके के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। चंबल के विकास के लिए यह महापथ होगा। इसके जरिए औद्योगिक इकाइयां और व्यापारिक व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। प्रदेश की जिन 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें से 16 विधानसभा सीटें इसी ग्वालियर चंबल इलाके में हैं। चूंकि जून के बाद कभी भी उपचुनावों का ऐलान किया जाना संभावित है, उससे पहले-पहले शिवराज सरकार प्रोजेक्टिव का भूमिपूजन कर नींव का पत्थर गाड़ देना चाहती है। इसी कारण सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर हड़बड़ी में दिखाई दे रही है।

मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, 'चंबल एक्सप्रेस-वे बनाने का जो फैसला भाजपा सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में किया था। इसे कांग्रेस सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब प्रदेश की भाजपा सरकार एक नए प्रारूप में चंबल एक्सप्रेस-वे को चंबल प्रोग्रेस-वे के नाम से तैयार करेगी।'

भाजपा के सामने बड़ी चुनौती

भाजपा के सिर पर भी सरकार बचाए रखने का भारी बोझ है। कांग्रेस को बराबरी का मुकाबला करने के लिए कम से कम 15 सीटों पर जीत की जरूरत है। ऐसे में कांग्रेस उक्त प्रोजेक्ट का क्रेडिट लेकर इलाके की 16 विधानसभा सीटों पर अपना कब्जा करने की फिराक में है। वैसे ये सभी सीटें कांग्रेस के कब्जे में ही थी। वहीं ग्वालियर के महाराज भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। वैसे तो यहां से जीते सभी विधायक सिंधिया खेमे के ही हैं, लेकिन अचानक से इस्तीफा देकर दल बदलने से इन सभी की छवि पर गहरा असर पड़ा है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए यहां सीटें जीतना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ऐसे में इस सेतु का क्रेडिट लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां जीत का रास्ता पार करना चाह रही हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के चंबल एक्सप्रेस-वे के काम को फिर से शुरू करने को लेकर भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। शिवराज की घोषणा के बाद सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट को कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इसके लिए सिंधिया ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी आभार जताया। सिंधिया ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, 'पूर्व की कांग्रेस सरकार ने चंबल के विकास, प्रगति और उन्नति को गति देने के लिए बनने वाले 'चंबल एक्सप्रेस-वे' को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, उसे आज मप्र सरकार ने 'चंबल प्रोग्रेस-वे' के नाम से तुरंत बनाने का निर्णय लिया है।'

अब इस प्रोजेक्ट का क्रेडिट लेने में कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली है। यही वजह है कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान भी इस एक्सप्रेस-वे की याद पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार को भी आ रही है। कांग्रेस ने एक्सप्रेस-वे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज के बयान पर जवाबी हमला बोलते हुए इस प्रोजेक्ट को अपना बताया है। इस संबंध में पूर्व पीडब्लूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, 'चंबल एक्सप्रेस-वे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया झूठ बोल रहे हैं। चंबल एक्सप्रेस-वे कांग्रेस के प्रयासों से शुरू हुई बहुआयामी योजना है। इसके लिए कांग्रेस ने हर स्तर पर प्रयास किए हैं।' चूंकि पूर्व कांग्रेस नेता सिंधिया के भाजपा में जाने और एकसाथ 24 विधायकों के इस्तीफे देने के चलते कमलनाथ सरकार के हाथों से प्रदेश की कमान निकलकर फिर से शिवराज सिंह के हाथों में आई है, ऐसे में कांग्रेस सत्ता की बागड़ौर फिर से हथियाने के मूड में है। कांग्रेस नेता पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर झंडा मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ ही फहराएंगे। इस बात का सीधा-सीधा मतलब ये है कि कांग्रेस 24 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में जीत के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती।

उधर, भाजपा को जिताने के लिए संघ ने मोर्चा संभाल लिया है। भाजपा और संघ ने सभी सीटों पर पूर्णकालिकों को तैनात कर दिया है। गौरतलब है कि उपचुनाव के परिणाम पर सरकार का भविष्य निर्भर है। इसलिए भाजपा और संघ ने चुनावी घोषणा से पहले संघ के पूर्णकालिकों को विधानसभावार जिम्मेदारी सौंप दी है। ये पूर्णकालिक सभी 24 सीटों पर बूथ स्तर की कमेटियां बनाएंगे, साथ ही निचले स्तर पर नेताओं की नाराजगी को दूर करने के साथ बात करेंगे। इन्हें भाजपा के साथ बूथों पर सिंधिया के लोगों के साथ समन्वय बिठाकर टीमें बनाने को कहा गया है। उपचुनाव वाले क्षेत्र में तैनात पूर्णकालिकों को यह भी सर्वे करना है कि क्षेत्र में संभावित उम्मीदवार के पक्ष में क्या माहौल है। गौरतलब है कि भाजपा की ओर से 22 सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय हैं। कुछ क्षेत्रों में उम्मीदवार को लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। ऐसे में पूर्णकालिकों को समन्वय बनाना है। साथ ही हर सप्ताह संगठन को रिपोर्ट भेजनी है। उस रिपोर्ट के आधार पर संघ और भाजपा अगला कदम उठाएंगे। भाजपा के सभी उम्मीदवार आयतित हैं। इस कारण से उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य बैठाना पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। इन विधानसभा क्षेत्रों से लंबे अरसे से काम कर रहे नेता भी इन उम्मीदवारों का ईमानदारी से साथ देंगे, या फिर औपचारिकता निभाएंगे।

भाजपा सूत्रों के अनुसार, 22 में से करीब आधा दर्जन से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा कार्यकर्ता सिंधिया समर्थक नेताओं को महत्व नहीं दे रहे हैं। यही नहीं संगठन में भी सिंधिया और उनके समर्थकों को अधिक भाव नहीं मिल रहा है। एक समय था जब ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिलों में कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष की नियुक्ति भी सिंधिया से पूछे बिना नहीं होती थी। लेकिन भाजपा ने सिंधिया के ग्वालियर में ही संगठन के जिला एवं ग्रामीण अध्यक्षों की नियुक्ति करते समय सिंधिया को पूछा तक नहीं है। भाजपा संगठन में हुई नियुक्तियों के बाद सिंधिया समर्थकों में हलचल तेज हुई है। समर्थकों का मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बेशक भाजपा में आकर सत्ता की नजदीकी हासिल कर लें, लेकिन फिलहाल संगठन स्तर पर **उन्हें और उनके समर्थकों को महत्व नहीं** दिया जा रहा है। भाजपा कार्यालयों में लगे बैनर, पोस्टर में शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर तो दिखते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा अभी किसी बैनर में दिखाई नहीं देता।

● भोपाल से अरविंद नारद

ग्वालियर-चंबल पर खास नजर

उपचुनावों को लेकर यदि कांग्रेस की बात करें, तो उसे उम्मीदवार खोजने में ही कठिनाई आ रही है। क्योंकि पहली बार ग्वालियर-चंबल में कांग्रेस पार्टी सिंधिया के बिना चुनाव लड़ेगी। सिंधिया और भाजपा की चुनौती से कांग्रेस को लड़ना होगा। इसी कारण भाजपा के कुछ प्रभावशाली नेताओं से कांग्रेस संपर्क कर रही है। 15 साल प्रदेश में शासन करने के बाद ग्वालियर-चंबल अंचल ने ही चौथी बार भाजपा को सरकार बनाने में बैरिकेट्स लगा दिया था। एक बार फिर ग्वालियर-चंबल अंचल को तय करना है कि भोपाल में शिवराज सरकार रहेगी या फिर कमलनाथ सरकार की वापसी होगी। क्योंकि उपचुनाव में अंचल की 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। इनमें से 15 विधानसभा क्षेत्रों से चुने गए विधायकों के कारण ही कांग्रेस सरकार से बाहर हुई है। उपचुनाव के मद्देनजर भाजपा ने मैदानी जमावट के साथ ही अपने विधायकों और नेताओं की निगरानी भी बढ़ा दी है। इसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में कुछ चुनिंदा भाजपा कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे विधायक और नेताओं की एक-एक रिपोर्ट भेजें। संघ सूत्रों के अनुसार, 2018 का विधानसभा चुनाव भाजपा अपने मंत्रियों और कुछ विधायकों की कार्यप्रणाली के कारण हारी थी। इसलिए संघ ने विधायकों की कार्यप्रणाली दुरुस्त रखने के लिए अभी से अपने अय्यारों को मुस्तैद कर दिया है। बताया जाता है कि संघ द्वारा तैनात कार्यकर्ता कर सप्ताह विधायक की कार्यप्रणाली की रिपोर्ट भेजेंगे। फिर रिपोर्ट के आधार पर विधायक को दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। उधर, भाजपा का किसान मोर्चा किसानों और श्रमिकों के बीच कोविड-19 को माध्यम बनाकर सक्रिय हो गया है। वह किसानों को गमछा और काढ़ा बांट रहा है। साथ ही भाजपा को जिताने की अपील भी कर रहा है।

मप्र में कमलनाथ सरकार ने किसानों के साथ कर्जमाफी के नाम पर फर्जीवाड़ा किया है। इससे किसान आहत हैं। लेकिन अब प्रदेश में किसान पुत्र शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। यह सरकार किसानों की हर समस्या का समाधान करेगी।

किसानों का एक-एक दाना खरीदेगी सरकार

मप्र में इस बार गेहूं का रिकार्डतोड़ उपार्जन हुआ है। 31 मई तक प्रदेश में एक करोड़ 22 लाख 28 हजार 379 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 17 हजार 430 करोड़ 51 लाख 78 हजार 323 रुपए का भुगतान किया गया है। ये आंकड़ें दर्शाते हैं कि मप्र की शिवराज सिंह चौहान सरकार कितनी किसान हितैषी है। मुख्यमंत्री ने तो पदभार संभालते ही घोषणा कर दी थी कि किसानों का एक-एक दाना सरकार खरीदेगी और ऐसा करके हम दिखा रहे हैं। यह कहना है प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल का।

राष्ट्रीय पाक्षिक अक्स से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले साल कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में बंपर उत्पादन के बावजूद किसानों से 63 लाख मीट्रिक टन ही गेहूं खरीदा था। यही नहीं कमलनाथ सरकार ने कर्जमाफी के नाम पर किसानों के साथ ठगी की है। किसानों ने इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जल्द ही सरकार इस मामले की जांच कराकर हकीकत को उजागर करेगी। पटेल ने कहा कि कमलनाथ सरकार के समय प्रदेश में माफिया, अफसर और वेयर हाउस संचालकों का ऐसा गठजोड़ बना था, जिससे किसानों का खूब शोषण किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे शासनकाल में एक शिकायत आने पर हम जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवा रहे हैं।

प्रदेश में 31 मई तक 882 खरीदी केंद्रों पर 1 लाख 83 हजार 913 किसानों से 3 लाख 82 हजार 410 मीट्रिक टन चना, मसूर एवं सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई। पटेल ने बताया कि सरकार ने चना और सरसों की खरीदी की सीमा प्रति हेक्टेयर 20 क्विंटल करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के पंजीकृत पांच लाख 30 हजार किसानों को फायदा मिलेगा। चने के विक्रय से लगभग 325 करोड़ रुपए और सरसों के विक्रय से लगभग 146 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ किसानों को होगा।

अब जुर्माना देकर नहीं छूट पाएंगे रेत माफिया

प्रदेश में अवैध खनन करने वाले रेत माफिया अब सिर्फ जुर्माना देकर नहीं छूट सकेंगे, बल्कि उनके खिलाफ चोरी और चोरी का सामान छिपाने की धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश में अवैध खनन बड़ी समस्या है। सरकार ने नर्मदा सहित प्रदेश की सभी नदियों में रेत के अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कई कठोर कदम उठाए हैं, लेकिन माफिया पर अंकुश नहीं लग पाया है। दरअसल कृषि मंत्री कमल पटेल ने जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के सभी कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखकर निर्देश जारी किया है कि अवैध रेत उत्खनन करने वालों को केवल जुर्माना लगाने की कार्रवाई के बाद ना छोड़ा जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ चोरी और चोरी का सामान छिपाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। इतना ही नहीं, यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर कोई गाड़ी अवैध रेत खनन करते हुए पकड़ी जाती है तो फिर गाड़ी चालक पर एफआईआर करने के साथ-साथ गाड़ी मालिक के खिलाफ भी इन्हीं चोरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। मंत्री कमल पटेल की ओर से अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि अगर ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि अधिकारी जुर्माना देकर गाड़ियां छोड़ रहे हैं तो फिर खनिज अधिकारी से लेकर बाकी सभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कमल पटेल ने बताया है कि प्रदेश में किसान उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर फल-सब्जियों का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कर रहे हैं। तकनीक के इस्तेमाल से उत्पादन में वृद्धि हुई है। किसानों के उत्पाद प्रदेश के अतिरिक्त देश के विभिन्न हिस्सों में बेचे जा रहे हैं। पटेल ने बताया कि कृषि एवं प्र-संस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के माध्यम से महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के 10 से अधिक निर्यातकों ने मध्यप्रदेश के कृषि उत्पादों में रूचि दर्शाई है। पटेल ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का फायदा पहुंचाने के लिए प्रदेश में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग, निर्यात के लिए तय मापदंडों से अवगत कराने विशेषज्ञ समूह आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रहे हैं।

पटेल ने बताया कि कोरोना महामारी के संकटकाल ने मध्यप्रदेश में किसानों को एक ऐसी सौगात दे दी है, सामान्य दिनों में जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कोरोना संकट के दौर में किसानों को आर्थिक परेशानियों से बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक ही झटके में मंडी अधिनियम में संशोधन करके किसानों को एक तरह से ग्लोबल मार्केटिंग से जोड़ने का करिश्मा कर दिखाया। आढ़त का काम कर रहे व्यापारियों को अगर लाइसेंस राज से मुक्ति मिली है तो किसानों के लिए भी यह एक तरह से आर्थिक रूप से अपने को मजबूत बनाने का मौका कहा जा सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने ई-टेंडरिंग का भी इंतजाम किया है। इसके तहत पूरे देश की मंडियों के दाम किसान को मिल जाएंगे। वो देश की किसी भी मंडी में, जहां उसे दाम ज्यादा मिल रहे हों, अपनी फसल का सौदा कर सकेगा।

● **लोकेश शर्मा**

चोरी और सीनाजोरी

बिना एग्रीमेंट और बिना गारंटी चल रहे शराब के ठेके

प्रदेश में ई-टेंडर के माध्यम से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट, सागर, राजगढ़, सतना, रीवा, शहडोल, सिंगरौली, ग्वालियर, शिवपुरी के ई-टेंडर हुए थे। 25 फरवरी को राजपत्र क्रमांक 77 के अनुसार 31 मार्च 2020 के पहले प्रतिभूति राशि जमा करने और अनुबंध करने के निर्देश शासन द्वारा राजपत्र में नियम प्रकाशित कराए थे। कंडिका 20 के अनुसार 18 पोस्ट डेटेड चेक अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में जमा करना अनिवार्य था। इसके बाद भी, बिना चेक जमा कराए तथा बिना बैंक गारंटी के शराब के ठेके अवैधानिक रूप से संचालित हो रहे हैं। मध्यप्रदेश में पहली बार हो रहा है कि शराब के ठेके बिना किसी अनुबंध के चल रहे हैं। 25 फरवरी को राजपत्र में कंडिका 21 के अनुसार 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लाइसेंस के लिए अनुबंध करना था। जो ठेकेदारों द्वारा नहीं किया गया है। इसी तरह कंडिका 15.11 के अनुसार भागीदारी फर्म होने की दशा में पार्टनरशिप डीड एवं रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी के पंजीयन की जानकारी ठेकेदारों को अनिवार्य रूप से अपलोड करनी थी। जो अभी तक नहीं हुए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो जाने से शराब दुकानें बंद थी। नई सरकार आने के बाद नई शराब दुकानें खोलने के आदेश शासन स्तर पर जारी हो रहे हैं। ठेकेदारों ने सरकार के ऊपर दबाव बनाकर न तो चेक जमा किए, न ही बैंक गारंटी जमा की है। सरकार से ठेकेदारों का कोई अनुबंध भी नहीं है। इसके बाद भी मध्य प्रदेश में शराब के ठेके धड़ल्ले से शुरू हो गए हैं।

म प्र में शराब की बिक्री सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा माध्यम है। इस वित्तीय वर्ष में सरकार को इससे करीब साढ़े 13 हजार करोड़ रुपए की वार्षिक आय होने की उम्मीद थी और विभिन्न तरह के लाइसेंस शुल्क को भी मिला लिया जाए तो करीब 15 हजार करोड़ रुपए का राजस्व आबकारी से मिलने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन कोरोना महामारी ने सरकार की मंशा पर पानी फेर दिया है। दरअसल, कोरोना के कारण किए गए लॉकडाउन में शराब की दुकानें 57 दिन बंद रहीं। उसके बाद उन्हें खोलने का निर्देश दिया गया तो शराब ठेकेदार तैयार नहीं हो रहे हैं। इस कारण सरकार और शराब ठेकेदार आमने-सामने आ गए हैं। उधर, मामला हाईकोर्ट में चला गया है। जहां 2 जून को सुनवाई होनी है।

कोरोना महामारी के चलते सरकार को बीते वित्त वर्ष का अंतिम माह लॉकडाउन के चलते भारी पड़ चुका है और अब भी स्थिति में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। हालात यह है कि लॉकडाउन में लिकर व्यवसायी अभी भी सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी दुकानें न खोलने की जिद पर अड़े हुए हैं, जिससे सरकार को हर दिन करोड़ों रुपए की आय से हाथ धोना पड़ रहा है। मार्च माह के अंतिम दिनों में अचानक दुकानें बंद होने से अंतिम दिन के स्टॉक के रूप में सरकार को मिलने वाले राजस्व के रूप में करोड़ों की चपत खजाने को पहले ही लग चुकी है। इस बीच प्रदेश में सक्रिय शराब माफिया और तस्करों ने जमकर चांद काटी तो सरकार को अपनी ही नीतियों की वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ गया है।

दरअसल इस मौके का फायदा उठाकर अधिकांश ठेकेदारों ने बचा हुआ माल निकाल दिया, जिसकी वजह से उनके पास नाम मात्र का ही स्टॉक रह गया। अब सरकार चाहती है कि शराब दुकानें खुल जाएं, तो ठेकेदार इसके लिए तैयार नहीं हैं। ठेकेदारों का कहना है कि उन्होंने जब ठेके लिए थे, तब निविदा की शर्तें कुछ और थीं। लेकिन 23 मार्च के बाद से परिस्थितियां बदल गईं हैं। लॉकडाउन के चलते 57 दिन दुकानें बंद रहीं। अब इन्हें खोलने की अनुमति भी दी गई है, तो कठोर शर्तों के साथ। फिर भी राज्य सरकार ने ठेकों की निर्धारित राशि (बिड) कम करने के लिए कोई पहल नहीं की है।

गौरतलब है कि सरकार हर साल आबकारी नीति में 15 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती है। इससे सरकार को दी जाने वाली राशि भी बढ़ जाती है। ऐसे में शराब का ठेका महंगा पड़ जाता है। इस बार ऐसा करने से ठेकेदारों को महंगी दरों पर शराब दुकानों का ठेका मिला है। फिर भी उन्होंने ठेका लिया है। जिस समय ठेका हुआ है उस समय कोरोना का संक्रमण नहीं था और न ही लॉकडाउन की संभावना थी। लेकिन लॉकडाउन होने के कारण विदेशी शराब दुकानों के अहाते बंद हैं, बार-होटल बंद हैं, लोगों का मूवमेंट बंद है, पर्यटन बंद है। ऐसे में शराब की मांग खत्म हो गई है। यही नहीं ठेके में शराब की दुकान खोलने का समय सुबह 9:30 बजे से रात 11 बजे तक था, लेकिन अब सुबह 7 से शाम 7 कर दिया गया है। ऐसे में शराब का कारोबार कम हो गया है। इससे शराब कारोबारी शराब दुकानें खोलने से कतरा रहे हैं।

प्रदेश में इस बार 3,605 (1 हजार 61 विदेशी और 2 हजार 544 देसी) शराब दुकानों के लिए 25 प्रतिशत अधिक दर पर ठेके हुए हैं। ठेकेदारों ने आकर्षक आबकारी नीति के तहत ठेके लिए थे, लेकिन नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही कोरोना महामारी ने ऐसी दस्तक दी कि लॉकडाउन हो गया और शराब दुकानें करीब डेढ़ माह खुल ही नहीं पाईं। जबकि ठेकेदारों के मुताबिक यही वह सीजन होता है, जब शराब की सर्वाधिक खपत होती है। अब शराब दुकानें खोलने का मामला हाईकोर्ट में चला गया है। उधर, सरकार की कोशिश है कि शराब कारोबारी कैसे भी करके दुकानें खोलें। इसके लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं एसोसिएशन की मांग है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के आबकारी राजस्व को पुन: निर्धारित किया जाए और इसे वर्ष 2019-20 के राजस्व के समतुल्य किया जाए। वर्ष 2020-21 की ठेका अवधि को संशोधित करके 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया जाए। वर्ष 2021-22 के लिए वर्ष 2019-20 में वार्षिक मूल्य में 25 फीसदी की वृद्धि करते हुए वार्षिक मूल्य निर्धारण किया जाए। शासन द्वारा निर्धारित 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी राशि की वसूली वर्ष 2021-22 में की जाए।

● **विकास दुबे**

मप्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को संपन्न बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों और सहकारी समितियों की मिलीभगत से किसानों के साथ ठगी की जा रही है। खरीदी केंद्रों पर गेहूं बेचने गए किसानों से प्रति क्विंटल पर 700 ग्राम से अधिक गेहूं तुलवाकर उन्हें करोड़ों रुपए की चपत लगाई गई है।

किसानों के साथ ठगी

प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी जारी है। गेहूं का एक-एक दाना सहेजकर बेचने के लिए वेयर हाउस और उपार्जन केंद्रों पर ले जा रहे किसानों के साथ तौल में गड़बड़ी कर बड़ी ठगी की जा रही है। अधिकतर वेयर हाउसों और उपार्जन केंद्रों पर किसानों से गेहूं की प्रति क्विंटल 700 ग्राम से लेकर 5 किलो तक ज्यादा तुलाई की जा रही है। ऐसा गेहूं खरीदी के लिए उपयोग किए जा रहे बारदाने के वजन और गेहूं में नमी के बराबर गेहूं की तुलाई के नाम पर किया जा रहा है। वेयर हाउस संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर इस कारनामे को अंजाम दे रहे हैं। इससे किसानों को करोड़ों रुपए की चपत लग रही है।

मप्र में एक तरफ गेहूं खरीदी का रिकार्ड बना है, वहीं दूसरी तरफ खरीदी केंद्रों पर किसानों के साथ अत्याचार और शोषण हो रहा है। दूर-दराज की बात तो छोड़िए, राजधानी भोपाल के खरीदी केंद्रों पर भी किसानों से ठगी की जा रही है। जिले के गेहूं उपार्जन केंद्र ग्राम धमर्रा के खरीदी केंद्र पर वहां के सहायक प्रबंधक लालता प्रसाद विश्कर्मा के खिलाफ गेहूं खरीदी में भ्रष्टाचार करने पर एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि वहां का सहायक प्रबंधक तुलाई के बाद हर किसान से पांच किलो अतिरिक्त गेहूं लिया करता था। अवैध गेहूं को जब्त कर आरोपी सहायक प्रबंधक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया है। गुनगा थाने के प्रभारी सुनील भदौरिया के अनुसार ग्राम धमर्रा में गेहूं उपार्जन केंद्र है। वहां के सहायक प्रबंधक लालता प्रसाद विश्कर्मा हैं। उनके खिलाफ लगातार शिकायतें पहुंच रही थीं। शितान्शु धुर्वे सहायक निरिक्षक खाद्य आपूर्ति निगम टीम के साथ धमर्रा उपार्जन केंद्र में आए थे। वहां उन्होंने छापेमार कार्रवाई कर 14 क्विंटल अवैध रूप से रखा गेहूं जब्त किया था। जिसका कोई हिसाब उपार्जन केंद्र में मौजूद स्टॉफ नहीं दे सका था। केंद्र में भ्रष्टाचार की शिकायत उन्हें एक किसान द्वारा पूर्व में की गई थी। अवैध गेहूं को जब्त कर शितान्शु की शिकायत पर आरोपी लालता प्रसाद के खिलाफ शासकीय माल में आमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है।

वहीं विदिशा जिले में 50 किलो की बोरी पर 250 से 350 ग्राम ज्यादा गेहूं की तुलाई की जा रही है। जूट की बोरी का वजन 500 ग्राम होता है, लेकिन उपार्जन केंद्रों पर प्रति बोरी 50 किलो 850 ग्राम तक तुलाई हो रही है। प्रति 50 किलोग्राम गेहूं की तुलाई पर किसानों से 350 ग्राम अतिरिक्त गेहूं तौला जा रहा है। ऐसे ही प्लास्टिक की बोरी का वजन करीब 100 ग्राम होता है, लेकिन वेयर हाउस केंद्रों पर किसानों से 50 किलो 350 ग्राम तक ज्यादा गेहूं तौला जा रहा है। इस तरह प्रति 50 किलोग्राम गेहूं की तुलाई पर किसानों से 250 ग्राम अतिरिक्त गेहूं तौला जा रहा है। चूंकि सरकार लाखों मीट्रिक टन गेहूं खरीद रही है, इसलिए किसानों को लाखों क्विंटल की चपत लगाई जा रही है। इसी तरह की शिकायतें रीवा, सतना, सिंगरौली, सीधी, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, जबलपुर, नरसिंहपुर, नरसिंहगढ़, राजगढ़ के खरीदी केंद्रों से भी आ रही हैं कि वहां किसानों से प्रति क्विंटल 700 ग्राम से लेकर 1 किलो तक अधिक गेहूं तौलाया जा रहा है। कृषि मंत्री कमल पटेल कहते हैं कि एक-दो शिकायतें मिलने के बाद हमने अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है।

● **सुनील सिंह**

प्रदेश में गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी रखने की जगह नहीं

पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। प्रदेश सरकार ने 100 लाख टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया था। इसके मुकाबले 116 लाख टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। लक्ष्य से ज्यादा खरीदी होने से अब गेहूं के भंडारण की समस्या आ गई है क्योंकि सरकार ने लक्ष्य के हिसाब से गेहूं भंडारण की व्यवस्था कर रखी थी। जबकि लक्ष्य से ज्यादा खरीदी हो गई है। ऐसे में भंडारण के लिए गेहूं अब राजस्थान भेजा जा रहा है। इधर रिकॉर्ड खरीदी को देखते हुए राज्य सरकार ने गोदामों में कैपेसिटी से 25 फीसदी ज्यादा गेहूं भंडारण के आदेश दिए हैं। यानी जिन गोदामों की कैपेसिटी 5000 टन है। उन गोदामों में अब 6000 टन गेहूं का भंडारण किया जा रहा है। पिछले साल यह स्थिति थी कि इस समय तक गेहूं की खरीदी 74 लाख मीट्रिक टन ही हुई थी। इससे 5000 टन की क्षमता के गोदामों में महज 2500 से 3000 टन गेहूं का भंडारण किया था। इस साल गोदामों में दोगुना गेहूं का भंडारण किया जा रहा है।

दोहरी मार

देश और प्रदेश में लोग कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं कि इसी बीच किसानों के लिए टिड्डी दल आफत बनकर टूट पड़ा है। राजस्थान में तबाही मचाने के लिए टिड्डी दल अब मप्र में तबाही मचा रहा है। यह दल प्रदेश में सीहोर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, खंडवा, सागर, जबलपुर, दमोह, कटनी सहित एक दर्जन से अधिक जिलों में फसलें चट कर चुका है। टिड्डी दल को रोकने के लिए किसानों और प्रशासन के सारे प्रयास फेल हो गए हैं। अब तक यह दल हजारों एकड़ की फसल और पेड़-पौधे चट कर चुका है।

मध्यप्रदेश में साधारण टिड्डी (ग्रास हूपर) का हमला तो सामान्य रहा है, लेकिन रेगिस्तानी टिड्डी (डेजर्ट लोकस्ट) का यह हमला तकरीबन 26 साल बाद हुआ है। इससे पहले यहां 1993 में यह हमला हुआ था। लोकस्ट विशेषज्ञ अनिल शर्मा ने बताया कि रेगस्तानी टिड्डे, ग्रास हूपर्स के मुकाबले अधिक दूरी तय करते हैं और काफी तबाही मचाते हैं। वे अपने रास्ते में आने वाली हरियाली को चट कर जाते हैं। अनिल शर्मा के मुताबिक राजस्थान से टिड्डे हवा के बहाव के साथ उत्तरप्रदेश, बिहार और पंजाब का रुख करते हैं, लेकिन संभव है मौसम में बदलाव की वजह से वे इस बार मध्यप्रदेश की तरफ पहुंच गए हों।

जिला स्तर पर टिड्डी दल के आक्रमण से निपटने की कई कोशिशें हो रही है। मंदसौर के कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि सेंट्रल लोकस्ट की एक टीम टिड्डी दल के नियंत्रण में लगी है, जिसके साथ जिला प्रशासन की टीम भी दवा छिड़काव कर रही है। प्रशासन सेंट्रल लोकस्ट के द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के मुताबिक छिड़काव कर स्थिति से निपट रहा है। जिले के किसान कल्याण और कृषि विकास के उपसंचालक अजीत सिंह राठौर ने कहा कि पहली बार जिले में टिड्डी दल का आक्रमण हुआ है। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि यह रेगिस्तानी टिड्डी ही है। उन्होंने कहा कि जिले में राजस्थान की ओर से टिड्डी दल भानपुरा और गरोठ ब्लॉक के गावों में फैला है।

वह कहते हैं कि वर्तमान में कोई भी कृषि फसल प्रभावित नहीं होने के कारण ज्यादा प्रकोप की कोई आशंका नहीं हैं। इस इलाके में उद्यानिकी फसलों में मुख्य रूप से संतरा पाया जाता है जिसे अब तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। टिड्डी के बचाव से किसानों को जागरूकता के लिए विभाग ने 76 हजार किसानों को एसएमएस और वॉट्सएप पर संदेश भेजे हैं।

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कीट विशेषज्ञ एके भौमिक ने बताया कि टिड्डी दल का हमला मध्यप्रदेश की कृषि पर एक बड़ा संकट है और इससे निपटने के लिए सरकारी स्तर पर व्यापक प्रबंध करना होगा। छोटे किसान जब तक दवाई खरीदकर छिड़काव की तैयारी करेंगे, तब तक उनका खेत खराब हो जाएगा। सरकार को ड्रोन के माध्यम से हवा में दवा का छिड़काव करना चाहिए और टिड्डी दल के आगमन का पूर्वानुमान लगाकर ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।

कृषि विभाग की मानें तो एक टिड्डी दल में लाखों की संख्या में किट होते हैं। इनकी गिनती करना मुश्किल होता है। इसलिए इनका अनुमान किलोमीटर के हिसाब से लगाया जाता है। अब तक सबसे बड़ा दल 8 से 10 किमी लंबा नापा गया है। कृषि विभाग के अनुसार ये टिड्डी दिन में ऊंचाई पर उड़ती है और रात होते ही जमीन पर आ जाती है। इससे जहां भी यह दल रुकता है। वहां तबाही मचा देता है। इसलिए कृषि विभाग इन टिड्डियों पर सतत निगाह रख रहा है। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) का मानना है कि लॉकडाउन ने टिड्डी दल को फैलने में बड़ी मदद की है। अप्रैल के मध्य में भारत, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में एफएओ के अधिकारियों ने कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के असर पर चर्चा की थी। बैठक में एक चिंताजनक तथ्य यह पता चला था कि लॉकडाउन के कारण ईरान ने टिड्डी दलों को मारने के लिए केमिकल का छिड़काव रोक दिया है। इस बैठक में एफएओ के अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि टिड्डी दलों के रोकथाम के अभाव में इनका लगातार प्रजनन होगा और हालात बेकाबू हो जाएंगे। उन्होंने चेताया था कि ये टिड्डी दल भारत के नए भौगौलिक क्षेत्रों और पड़ोसी देशों का रुख करेंगे।

● **बृजेश साहू**

जून-जुलाई में हो सकता है सबसे भीषण हमला

कोरोना से जूझ रहे मप्र के लोगों की आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बार जून-जुलाई में सीमा पार से टिड्डियों का भीषण हमला होने के हालात बन रहे हैं। भारत में मार्च और अप्रैल में टिड्डी दलों के लिए अनुकूल स्थितियां बन चुकी थीं। बारिश के कारण आई नमी और हरियाली ने इन टिड्डी दलों को भारत आने के लिए प्रेरित किया। उधर, टिड्डी दलों को नियंत्रित करने के संबंध में एफएओ अधिकारियों की अहम बैठक हुई। एफएओ के महानिदेशक क्यूयू डोंक्यू का कहना है कि जीवन-यापन और खाद्य सुरक्षा पर कोविड-19 और टिड्डी दल के विनाशकारी परिणाम होंगे। पाकिस्तान के एक तिहाई से अधिक हिस्से में टिड्डियां अंडे दे चुकी हैं। अगले माह के अंत तक पूर्वी अफ्रीका से करोड़ों टिड्डियों के समूह भारत की तरफ आएंगे। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि एजेंसी ने भी इस बारे में चेतावनी जारी की है। प्रदेश में टिड्डियों के छोटे समूहों के हमले एक माह से चल रहे हैं और यहां चलने वाली आंधियों के कारण ये यहां से काफी आगे तक पहुंच चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि एजेंसी के एक शीर्ष अधिकारी ने आगाह किया कि टिड्डियों का दल अगले महीने पूर्वी अफ्रीका से भारत और पाकिस्तान की ओर बढ़ सकते हैं। हम दशकों में अब तक के सबसे खराब मरुस्थलीय टिड्डी हमले की स्थिति का सामना कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में टिड्डियों का हमला केन्या, सोमालिया, इथोपिया, दक्षिण ईरान और पाकिस्तान के कई हिस्सों में सबसे अधिक गंभीर है।

पेड़ों की अवैध कटाई

मप्र में लॉकडाउन के कारण भले ही लोग घरों में कैद हैं, लेकिन माफिया और तस्कर इस लॉकडाउन का जमकर फायदा उठा रहे हैं। खासकर प्रदेश के वनक्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई जोरों पर है। राजधानी भोपाल का वनक्षेत्र हो या प्रदेश के दूरदराज के इलाके का जंगल, माफिया बेखौफ होकर पेड़ों की कटाई कर रहा है। अनूपपुर, खंडवा, बैतूल, बालाघाट सहित दर्जनभर जिलों में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले सामने आ चुके हैं। हद तो यह है कि भोपाल के बाघ भ्रमण क्षेत्र में एक बार फिर जंगल माफियाओं का दखल शुरू हो गया है। लॉकडाउन का फायदा उठाकर चंदनपुरा के आगे कलियासोत के जंगलों की कटाई की गई। अब तक यहां 500 से अधिक हरे-भरे पेड़ों को काट दिया गया। जंगल में पेड़ों की कटाई का मामला उजागर न हो इसके लिए दस से बीस पेड़ों को छोड़कर कटाई की गई। मामले की शिकायत भी कलेक्टर, वन विभाग के अधिकारी और निगमायुक्त से की गई है। शिकायतकर्ता राशिद नूर खान ने बताया कि इन क्षेत्रों में पहले भी जंगलों को साफ करने के लिए पेड़ों की कटाई की गई। इसके साथ ही कई बार अज्ञात कारणों से आग भी लगाई गई, जहां पेड़ों की कटाई की गई उनका अधिकतर हिस्सा राजस्व भूमि व वन विभाग का है। इसमें कई पेड़ सागौन, बांस, नीम, आम व इमारती लकड़ियों के हैं। लॉकडाउन के कारण जिम्मेदारों की निगरानी में लापरवाही की गई। इसका फायदा उठाकर जंगल व भू-माफिया सक्रिय हो गए और पांच सौ से अधिक पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई।

जिस क्षेत्र में पेडों की कटाई की गई वह बाघ मूवमेंट एरिया में आता है। वन विभाग के आंकड़ों में यहां 18 बाघों का मूवमेंट है। इसमें चंदनपुरा, मेंडोरा, मेंडोरी, दामखेड़ा, कलियासोत व केरवा समेत अन्य क्षेत्रों के जंगल शामिल हैं। शिकायत में बताया गया है कि जंगलों की कटाई से बाघों के अस्तिव पर खतरा मंडरा रहा है। पहले भी अधिकारियों की अनदेखी से इन क्षेत्रों में प्रतिबंध के बावजूद भी निर्माण कार्य किए गए। मामले पर शिकायतों के बाद भी अमल नहीं किया गया। बाघ भ्रमण क्षेत्र चंदनपुरा में बीते 2 माह पहले रातोंरात 10 एकड़ के जंगल को साफ कर दिया गया था। इस क्षेत्र में करीब 250 से ज्यादा पेड़ों की कटाई की गई थी। वन परिक्षेत्र में वनों की कटाई की गई वह निजी भूमि है। अधिकारियों की मिलीभगत से बिना जांच-पड़ताल के ही भू-स्वामी को पेड़ काटने की अनुमति दी गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने फरवरी में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान शहरी वन परिक्षेत्र में मैपिंग का आदेश दिया था। एनजीटी ने मिनिस्ट्री ऑफ इनवायर्मेंट एंड फॉरेस्ट से शहर के वन परिक्षेत्र की रिपोर्ट मांगी थी। एनजीटी ने वन विभाग को शहर के सभी क्षेत्रों में फॉरेस्ट एरिया को दोबारा चि-ति करने का निर्देश दिया है। जिन स्थानों पर पेड़ों की कटाई की गई उस वन परिक्षेत्र की भी मैपिंग की जानी थी, जो अब तक शुरू नहीं की गई है।

उधर, खंडवा के पश्चिम कालीभीत के दो-तीन बीटों में वन माफिया जमकर सक्रिय है। यह लॉकडाउन का जमकर फायदा उठा रहे हैं। माफिया केवल सागौन की कटाई ही नहीं कर रहे बल्कि बेखौफ मौके पर ही पटिए तैयार कर सप्लाई कर रहे हैं। इधर वन विभाग के अफसर भी लॉकडाउन का बहाना कर जंगल जाने से बच रहे हैं। उनका कहना है लॉकडाउन में नाकेदारों की ड्यूटी चैक पोस्ट पर लगा दी है तो जंगल में कौन देखने जाएगा। यह अवैध कटाई उत्तर कालीभीत के अंबाड़ा व सिराल्या सर्किल में पूर्व अंबाड़ा, उत्तर अंबाड़ा, मुहालखारी, जोशी नाला बीट में जोरों पर चल रही है। पांच दर्जन से अधिक सागौन के पेड़ काट दिए गए हैं। अंबाड़ा सर्किल के बाराकुंड बीट में सागौन के पेड़ जमीन पर पड़े दिखाई दे रहे हैं तो कहीं पटिए बनाने के अवशेष भी पड़े हैं। नाकेदारों के अलावा वनपाल, वन सुरक्षा समिति सहित अन्य लोगों पर वनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। नाके भी बनने हैं और वनपालों के लिए रहने की व्यवस्था भी है। इसके बावजूद तेजी से जंगल साफ हो रहा है। कई हरे पेड़ आधे काटकर सुखा रहे हैं ताकि कुछ दिन बाद यह खुद ही गिर जाएं। रेंजर तो महीनों जंगल में नहीं झांकते। यही हाल अनूपपुर सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में है। जंगलों में ताबड़तोड़ पेड़ काटे जा रहे हैं लेकिन वन अमला सुस्त पड़ा हुआ है।

● राजेश बोरकर

200 करोड़ से निजी कंपनी करेगी वनों की सुरक्षा

राज्य में वन विभाग अमले द्वारा किए जा रहे तमाम प्रयासों के बाद भी वनों की पूरी तरह से सुरक्षा नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से लगातार वन क्षेत्रफल में कमी आती जा रही है। इसके चलते अब राज्य सरकार वनों पर नजर रखने का काम हैदाराबाद की एक निजी कंपनी को देने की तैयारी कर रही है। यह कंपनी करीब दो सौ करोड़ रुपए में सैटेलाइट इमेजरी के जरिए नजर रखेगी। इसके लिए प्रोजेक्ट तैयार करने की जिम्मेदारी स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर को दी गई है। सरकार की मंशा इसके माध्यम से जंगलों में जारी अवैध कटाई, अतिक्रमण और अवैध उत्खनन पर रोक लगाने की है। इस प्रोजेक्ट के तहत सैटेलाइट से मिलने वाले चित्रों की लगातार समीक्षा कर इनका तुलनात्मक अध्ययन कर जानकारी हासिल की जाएगी। विभाग का मानना है कि लगातार मिलने वाले चित्रों से यह आसानी से पता चल सकेगा कि जंगल के किस हिस्से में हरियाली कम हो रही है। इसी आधार पर विभाग प्रभावी कदम उठाएगा। वन विभाग का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तैयार हो रहे इस प्रोजेक्ट की मॉनीटरिंग कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसएफआरआई) को पहली किश्त के रूप में 50 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इसके लिए कुछ राशि क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैपा) से दी जाएगी। माना जा रहा है कि अगले साल से वनों पर नजर रखने का काम शुरू हो सकता है।

'पावर' के इंतजार में महापौर

अब जनता ही चुनेगी महापौर और अध्यक्ष

मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलटने जा रही है। इस फैसले के तहत मध्य प्रदेश में मेयर के चुनाव अब प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होंगे यानि मेयर चुनाव के लिए जनता ही वोट करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि कैबिनेट का कोरम पूरा होने के बाद सरकार यह प्रस्ताव कैबिनेट में लेकर आएगी और फिर उसके बाद या तो विधानसभा में बिल लाकर या फिर अध्यादेश के जरिए इसे लागू कर दिया जाएगा। अपने कार्यकाल में कमलनाथ सरकार ने संशोधन करते हुए यह तय किया था कि प्रदेश में मेयर के चुनाव प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष प्रणाली से किए जाएंगे। भाजपा ने उस समय भी इसका पुरजोर विरोध किया था और फैसले को वापस लेने की मांग की थी लेकिन कांग्रेस सरकार ने फैसले को यथावत रखा था। अब जबकि प्रदेश में भाजपा सत्ता पर काबिज हो गई है। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रस्ताव को बदलने की सैद्धांतिक तौर पर सहमति दे दी है। कैबिनेट कोरम पूरा होने के बाद यह माना जा रहा है कि सरकार इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लेकर आएगी उसके बाद अगर मानसून सत्र में देरी हुई तो फिर इसके लिए अध्यादेश भी लाया जा सकता है। मेयर चुनाव को लेकर अब एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने आ गई हैं। भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का कहना है भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करती है। लिहाजा जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाना ही बेहतर है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने इसे मनमर्जी का फैसला बताया है। भूपेंद्र गुप्ता के मुताबिक जैसे प्रधानमंत्री का चयन सांसद और मुख्यमंत्री का चयन विधायक करते हैं उसी तरह मेयर का चयन भी पार्षदों के जरिए ही होना चाहिए।

प्रदेश में सरकार बनने के एक माह बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 नगर निगमों सहित 297 नगरीय निकायों में पुरानी परिषद बहाल करने की घोषणा की थी। सरकार की घोषणा के बाद पूर्व महापौरों और अध्यक्षों सहित तमाम पार्षदों के चेहरे खिल गए थे। लेकिन इस घोषणा के लगभग एक माह बाद भी सरकार ने प्रशासकीय समितियों का गठन नहीं किया है। इससे नगरीय निकायों में अभी भी अफसर प्रशासक के रूप में पदस्थ हैं। वहीं महापौर और अध्यक्ष पावर मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

गौरतलब है कि मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नगर निगम और नपा अधिनियमों में संशोधन कर अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रशासकीय समितियां बनाकर महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों को उसमें शामिल करना था। लेकिन अभी तक न तो समितियां बनीं और न ही समितियों के अधिकार और कर्त्तव्य तय हो पाए। इस कारण अभी भी संभाग मुख्यालय पर संभागायुक्त और जिला मुख्यालय पर कलेक्टर नगरीय निकाय के प्रशासक हैं। अन्य जगहों पर संबंधित एसडीएम को प्रशासक बनाया गया है।

समय पर चुनाव नहीं हो पाने के कारण कांग्रेस के शासनकाल में सरकार ने कार्यकाल समाप्त होने वाले नगरीय निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति की थी। चुनाव की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी कि कोरोना का संक्रमण फैलने लगा। ऐसे में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय निकायों का कार्यकाल एक साल बढ़ाने की घोषणा कर दी। इसके लिए अधिनियम की धारा 328 व 423 में प्रावधान हैं। उसके आधार पर प्रशासक या प्रशासकीय समिति गठित करने की व्यवस्था है। लेकिन एक माह बाद भी प्रशासकीय समिति गठित नहीं हो पाई।

अगर सरकार प्रशासकीय समिति गठित कर अध्यादेश के माध्यम से उसे लागू कर देती तो नगर निगम में महापौर रहे और नगर पालिका व नगर परिषद में अध्यक्ष रहे व्यक्ति प्रशासकीय समिति के प्रमुख के रूप में एक तरह से महापौर व अध्यक्ष की हैसियत से ही काम करने लगते। सरकार अपनी इच्छानुसार पूर्व पार्षदों को भी समिति में सदस्य बना सकती थी। लेकिन अभी तक सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा पाई है। सरकार ने प्रशासकीय समिति गठित कर उसमें तत्कालीन महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को शामिल करने की घोषणा की थी तो महीनों से घर बैठे नेता सक्रिय हो गए थे। लेकिन एक पखवाड़े के इंतजार के बाद भी जब समिति का गठन नहीं हो पाया तो सभी अपने घर बैठ गए।

सूत्र बताते हैं कि प्रशासकीय समिति गठित करने के मामले में सरकार में समन्वय नहीं बन पा रहा है। बताया जाता है कि वरिष्ठ अधिकारी इस पक्ष में नहीं हैं कि प्रशासक के तौर पर काम कर रहे अधिकारियों से अधिकार छीनकर महापौर या अध्यक्ष को फिर से अधिकार दिया जाए। बताया जाता है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सरकार प्रशासकीय समिति गठित कर सकती है।

सूत्र बताते हैं कि नगरीय निकायों में पूर्व महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों को प्रशासकीय समिति बनाकर फिर जिम्मेदारी सौंपने की घोषणा कर अभी अमली जामा पहनाया ही नहीं गया है कि सरकार सहकारिता के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में जुट गई है। इसके तहत सांसद और विधायकों के लिए सहकारी संस्थाओं के रास्ते खुल जाएंगे। वे प्रशासक और अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। सहकारी अधिनियम में अभी तक इस पर प्रतिबंध है, लेकिन सियासी समीकरणों के मद्देनजर आयोग, प्राधिकरण और परिषदों के अलावा एक और विकल्प तैयार किया जा रहा है, जहां नेताओं को समायोजित किया जा सके। इसके लिए अधिनियम की धारा 48 (ए) में संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है। अब अधिनियम में संशोधन कर यह इंतजाम किया जा रहा है कि सांसद और विधायक भी प्रशासक बनाए जा सकते हैं। जब चुनाव होंगे तो वे भी अध्यक्ष बनने की पात्रता रखेंगे। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन कैबिनेट में पारित होने के बाद जून-जुलाई में प्रस्तावित विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पहले जरूरी हुआ तो राज्यपाल लालजी टंडन के अनुमति से अध्यादेश के जरिए भी इसे लागू किया जा सकता है।

● **प्रवीण कुमार**

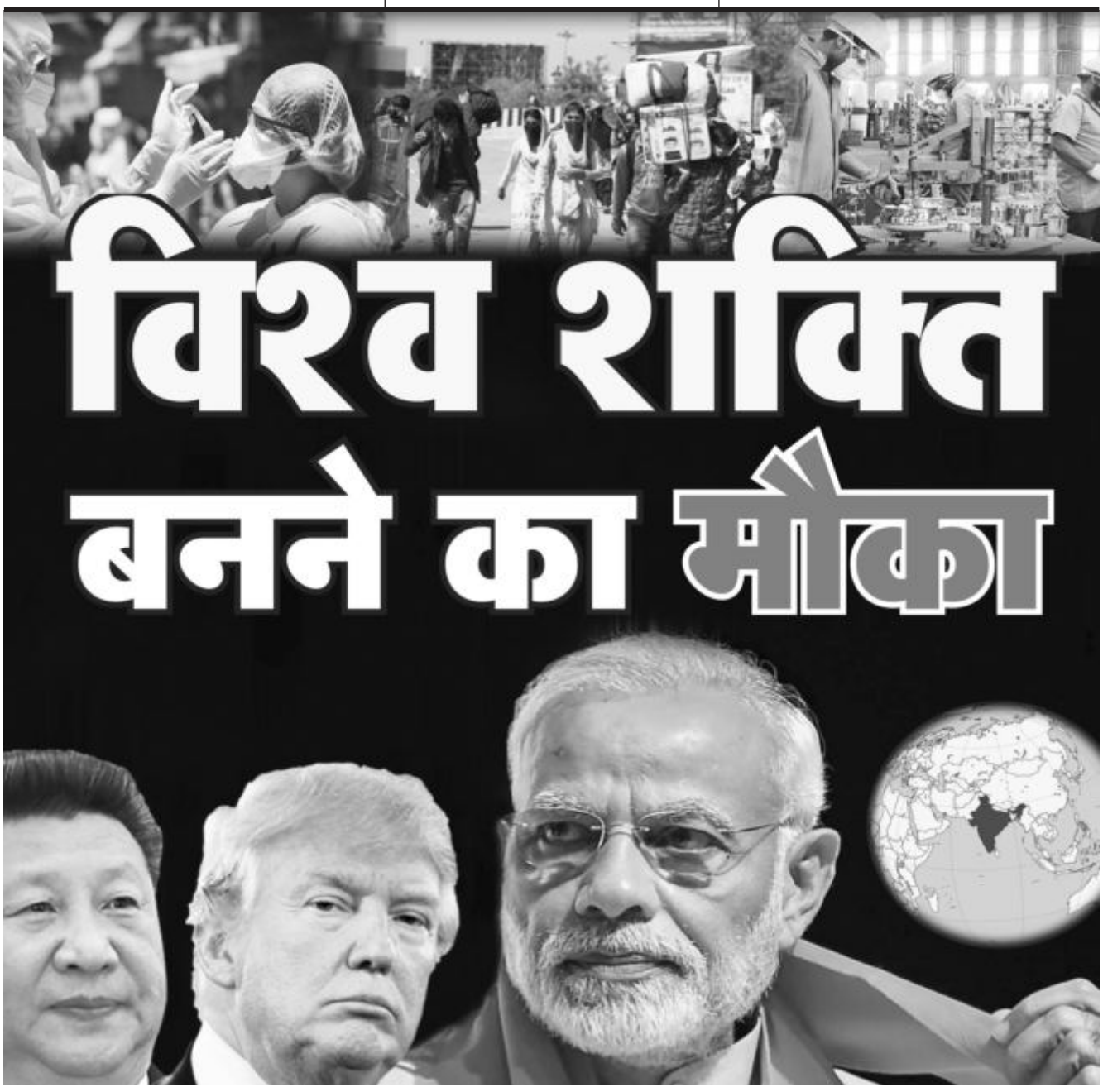

विश्व शक्ति बनने का मौका

कोरोना वायरस आफत के साथ संभावनाओं को भी लेकर आया है। जहां इस महामारी ने भारत में 15 करोड़ से अधिक लोगों को बेरोजगार कर दिया है, वहीं नई संभावनाओं का द्वार भी खोल दिया है। केंद्र हो या राज्य सरकारें सभी का फोकस गांवों पर हो गया है। इससे गांवों में ही रोजगार के अवसर निर्मित करने की योजना पर काम चल रहा है। वहीं यह कोशिश भी शुरू हो गई है कि विदेशी कंपनियों के लिए द्वार खोलकर भारत को विश्व शक्ति बनाया जाए।

● राजेंद्र आगाल

कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण अमेरिका और चीन के बीच तलवारें खिंच गईं हैं। दोनों देशों के झंडे तले दुनिया दो खेमों में बंटने लगी है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि चीन ने उस पर कोरोना वायरस से हमला किया है, वो उसे सबक सिखाएगा। उधर चीन ने **वर्ल्ड बैंक** को 300 करोड़ डॉलर का अनुदान देकर अपने मनी पॉवर की धौंस जमाई है। मिलिट्री पॉवर का भी इस्तेमाल वो ऐसे दौर में भी कर रहा है। साउथ चाइना सी में चीन का मिलिट्री अभ्यास चल रहा है, हांगकांग की स्वायतता पर वो लगातार हमले बोल रहा है। अमेरिका ने कहा है कि वो चुप नहीं बैठेगा, हर चीज का हिसाब लेगा। ऐसे में आशंकाएं लाजिमी हैं कि कहीं कोरोना वर्ल्ड वार के बीच, असली युद्ध भी तो नहीं छिड़ने वाला। इन दो महाशक्ति के बीच चल रहे शीतयुद्ध में भारत के लिए **तीसरी विश्व शक्ति** बनने का मौका है। अगर भारत ने सुव्यवस्थित रणनीति से काम किया तो यह संभव भी हो सकता है।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरे विश्व में 59,34,936 लोग संक्रमित और 3,67,166 की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में 1,82,143 संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 5,164 लोगों की मौत हुई है। लेकिन भारत ने जिस संयमित तरीके से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उससे पूरे विश्व की नजर भारत पर है। आलम यह है कि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया भारत को नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही उनकी मंशा भारत को चीन के खिलाफ मोहरा बनाने की हो, लेकिन अगर भारत कूटनीतिक रणनीति के साथ कोशिश करे तो वह विश्व की तीसरी महाशक्ति बन सकता है। बस जरूरत है समन्वय और समझदारी की। अभी तक भारत ने समझदारी का परिचय दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि बड़ी संख्या में चीनी कंपनियां भारत का रुख करने की तैयारी कर रही हैं। बस जरूरत है कि भारत सरकार अपनी नीति को लचीला बनाए। ताकि कंपनियों की स्थापना में कोई परेशानी न हो।

भारत के लिए वरदान

कोरोना वायरस को पैदा करने और तबाही फैलाने के आरोप से घिरे होने के कारण हजारों कंपनियां चीन से पलायन करने की तैयारी कर चुकी हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मानते हैं कि दुनिया का चीन से नाराज होना भारत के लिए वरदान की तरह है। उनका मतलब यह था कि चीन से नाराज देश और कंपनियां अपनी फैक्ट्रियों को चीन से बाहर लाकर दूसरे देशों में लगाने की कोशिश करेंगी और भारत के लिए ये एक बड़ा मौका होगा।

कोरोना वायरस से दुनियाभर में हुई तबाही के बाद से भारत के मुख्यधारा के मीडिया और सत्तारूढ़ पार्टी के करीबी अर्थशास्त्री इस तरह की उम्मीदें जगाते आ रहे हैं। इस मुहिम को इस बात से भी बल मिलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन के खिलाफ आलोचना तेज कर दी है। हाल के एक सर्वे के मुताबिक दो तिहाई अमेरिकी चीन को ही कोरोना महामारी का जिम्मेदार मानते हैं। ऐसे में भारत में ये उम्मीद करना कि चीन से बाहर निकलने वाली कंपनियां भारत का भी रुख करेंगी स्वाभाविक लगता है। ऐसे में भारत को इस कोशिश में जुट जाना चाहिए कि अधिक से अधिक कंपनियां भारत में स्थापित हों।

चाइना प्लस वन फॉर्मूला

विदेशी कंपनियों का फिलहाल फॉर्मूला है 'चाइना प्लस वन' यानी चीन में जमे रहो मगर एक कदम किसी दूसरी जगह भी रखो। इसका फायदा वियतनाम को हो रहा है। भारत के नाम केवल एप्पल का आईफोन-एक्सआर आया जिसकी असेम्बलिंग (प्रोडक्शन नहीं) चेन्नई में पिछले साल से शुरू हो गई है। भारत के आर्थिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि भारत के पास अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर के समय चीन में विदेशी कंपनियों को लुभाने का सबसे अच्छा मौका था। लेकिन ये अवसर हाथ से निकल गया। हैरानी इस बात पर है कि भारत का वाणिज्य मंत्रालय और दुनियाभर में भारतीय दूतावास पिछले ढाई-तीन सालों से चीन और इससे बाहर सक्रिय विदेशी कंपनियों को भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद ये अवसर हाथ से निकल गया। वाणिज्य मंत्रालय की 'इन्वेस्ट इंडिया' एक अलहदा बॉडी इसीलिए बनाई गई है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि 200 से अधिक कंपनियों ने भारत में कारखाने लगाने में दिलचस्पी दिखाई थी लेकिन कोरोना के फैलने के बाद अब 'अगले 18 महीनों तक इसमें कोई गतिविधि नहीं होने की संभावना है।'

कोरोना वायरस से चीन की बदनामी को भी एक अवसर के तौर पर देखा जा रहा है, मगर मोदी सरकार जानती है कि फिलहाल कोई बड़ी कंपनी चीन से भारत आने का इरादा नहीं रखती। चीन के स्तर का बुनियादी ढांचा मजबूत करने का, वैल्यू चेन का निर्माण करने का और सिंगल विंडो क्लीयरेंस की व्यवस्था को बनाने के लिए मोदी सरकार के छह साल और इससे पहले यूपीए सरकार के 10 साल काफी थे।

विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो कोरोना और ट्रेड वॉर जैसे अवसरों के बिना भी कंपनियां भारत में प्रोडक्शन यूनिट्स लगातीं। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 15 अगस्त को लाल किले से अपने पहले भाषण में विदेशी कंपनियों से कहा था, 'कम, मेक इन इंडिया।' लेकिन अब तक मेक इन इंडिया एक कामयाब मुहिम नहीं रही है। सच तो ये है कि विदेशी

चुनौती के बीच अवसर

संकट के दौरान ही विकल्प भी निकलता है। कोरोना महामारी ने दक्षिण एशिया के देशों को आपसी सहयोग और मजबूत करने के लिए एक बेहतर मौका दिया है। पिछले सात दशकों से भी ज्यादा समय से संघर्षरत भारत और पाकिस्तान को कोरोना का संदेश है कि पुराने विवादों को भूलिए और सहयोग के नए युग की शुरूआत कीजिए। लेकिन सहयोग का यह संदेश सिर्फ पाकिस्तान और भारत के लिए नहीं है, यह संदेश दक्षिण एशिया के उन तमाम देशों के लिए भी है जो गरीब हैं और अब वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं। कोरोना संकट ने दक्षिण एशिया के देशों के अर्थव्यवस्था को भारी धक्का पहुंचाया है। इसलिए इन देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग की जरूरत और बढ़ गई है। एशियाई देशों के लिए एक सुखद स्थिति यह रही कि इन देशों में कोरोना महामारी मृत्यु दर यूरोपीय और अमेरिकी देशों के मुकाबले कम है। अगर दक्षिण एशियाई देशों में मृत्यु दर ज्यादा होती तो हालात गंभीर होते, क्योंकि ज्यादातर देशों में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा दयनीय स्थिति में है। यह भी सत्य है कि कोरोना ने सिर्फ कुछ देशों की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया है, ऐसे में अब गरीब देश किसी अमीर मुल्क से भी बहुत ज्यादा मदद की उम्मीद नहीं लगा सकते। अमीर मुल्क खुद गहरे संकट में हैं और अपनी अर्थव्यवस्था बचाने में लगे है। इस भंवर से निकलने के लिए अब दक्षिण एशियाई देशों के समक्ष एक ही रास्ता है, और वह है आपसी सहयोग का। भारत हमेशा से आपसी सहयोग का हिमायती रहा है। पाकिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देश भारत का नेतृत्व स्वीकारते रहे हैं। इसलिए भारत को अब कुशल नेतृत्वकर्ता बनकर सामने आने का समय आ गया है।

अब तुम्हारे हवाले वतन देशवासियों!

लॉकडाउन 5.0 बस नाम मात्र का ही समझिए। ये 1 से 30 जून तक लागू जरूर रहेगा और इसे अनलॉक 1.0 मान कर चल सकते हैं। महीनेभर की इस अवधि के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। आसान भाषा में कहें तो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी सभी चीजों के लिए छूट ही छूट है, लेकिन कुछ शर्तें लागू हैं। पहला हफ्ता यूं ही रहेगा लेकिन दूसरे हफ्ते से ज्यादातर मामलों में छूट मिलेगी। एक महत्वपूर्ण बात- अगर अब भी कोई कहीं फंसा हुआ है तो मुश्किलें खत्म समझे। अब आने-जाने की पूरी छूट है। यानी अब किसी तरह के पास या परमीशन की जरूरत नहीं होगी। सबसे अहम बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने गाइडलाइन तैयार करने के अलावा एक तरीके से सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दी है और लोगों को अपनी सुरक्षा का खुद ख्याल रखना होगा ये बात हर वक्त याद रहे। मतलब साफ है। अब सभी को गांठ बांधकर समझ लेना होगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी- ये स्लोगन भले सड़कों पर लिखा देखने को मिला हो। भले ही सफर में दिखा हो, लेकिन अब इसे हर वक्त अच्छी तरह याद रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग खत्म, दुर्घटना संभव है। मास्क लगाना भूले, दुर्घटना संभव है। दो गज की दूरी भूले, दुर्घटना संभव है। लक्ष्मण रेखा भूले, दुर्घटना संभव है। ऐसे में बहुत ही जरूरी है कि आप अपना अच्छी तरह ख्याल रखें। अगर आप अपना ख्याल रखते हैं तो समझिए एक साथ कई लोगों का भला होता है। एक तो आपका और दूसरे आप के इर्द-गिर्द के सब लोगों का।

कंपनियां अब भी भारत में आने से हिचकिचाती हैं। उनके लिए भारत के पक्ष में कुछ बातें हैं जैसे कि स्किल्ड वर्क फोर्स की एक बड़ी संख्या, विशाल घरेलू बाजार, लोकतंत्र और सस्ती जमीनें। लेकिन चीन की तुलना में भारत कई क्षेत्रों में काफी पीछे है।

वैल्यू चेन के अपग्रेडेशन में कमी

कच्चे माल को प्राप्त करने से लेकर बने माल को बाजार में लाने तक की प्रक्रिया को वैल्यू चेन कहते हैं। इसमें चीन का मुकाबला दुनिया की कोई इकोनॉमी नहीं कर सकती। उदाहरण के तौर पर आप रेडीमेड कपड़े को ले लें जिसमें कच्चे माल की खरीदारी से लेकर तैयार माल के सप्लाई करने तक सात चरणों से गुजरना पड़ता है। लिवाइस जैसे बड़े गारमेंट ब्रैंड के कपड़ों को शोरूम तक लाने के लिए इन सात चरणों से होकर गुजरते हैं। भारत, वियतनाम, बांग्लादेश में वैल्यू चेन के इन सातों चरणों से दो या तीन मौजूद हो सकते हैं लेकिन चीन में ये सातों एक जगह मौजूद हैं। अगर लिवाइस जैसी कंपनी हैं तो चीन में उत्पादन आसान भी होगा और सस्ता भी। दिल्ली के फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में चीनी मामलों के विशेषज्ञ फैसल अहमद कहते हैं कि चीन से बड़े उत्पादों और फैक्ट्रियों को हटाने के लिए दुनिया के दूसरे देशों में मुकम्मल वैल्यू चेन है ही नहीं। वो कहते हैं, 'फिलहाल दुनिया की कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है जहां या तो बड़े पैमाने पर उत्पाद के साधन हों या निर्यात का पूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर। उनके अनुसार भारत को अपनी वैल्यू चेन को मजबूत करने और टेक्नोलॉजी के आधुनिकीकरण की सख्त जरूरत है।

श्रम, बिजली और भूमि सुधार

सरकार के नजदीक माने जाने वाले आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों ने सुझावों में विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए लैंड, पावर और लेबर के क्षेत्रों में सुधार पर जोर दिया है। उन्होंने कहा- 'हमें उग्र गति से, जीएसटी परिषद के समान एक भूमि परिषद, एक श्रम परिषद और एक ऊर्जा परिषद बनाने की जरूरत है।' ये उन विदेशी कंपनियों के लिए रास्ता आसान करेगा जो कारखानों को स्थापित करना चाहते हैं या एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं। भारत में औद्योगिक बिजली टैरिफ दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ में से एक माना जाता है। इसे कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कोई समझौता होना चाहिए।

सिंगल विंडो क्लीयरेंस

इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काफी जोर दिया है और इसमें बेहतरी भी हुई है लेकिन बाहर की कंपनियां अब भी शिकायत करती हैं कि उन्हें योजनाओं की मंजूरी में कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सरकार को दिए सुझाव में एक सुझाव ये है कि सिंगल विंडो क्लीयरेंस का निर्माण प्रधानमंत्री के दफ्तर में हो और विदेशी कंपनियों को पीएमओ के आलावा कहीं और जाने की जरूरत न पड़े। सुझाव ये भी है कि अगर चीन से मुकाबला करना है तो इन क्षेत्रों में काम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से करना होगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री को देश को पांच खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाना है और कोरोना के बाद वाली दुनिया में आगे बढ़ना है तो मौका है। वो कहते हैं, 'अभी करो, तेजी से करो।'

सुरक्षा चक्र मजबूत किया

विश्व व्यवस्था, क्षेत्रीय संतुलन और दक्षिणपूर्वी एशियाई देशों, एशिया प्रशांत के देशों के सागरीय संप्रभुता से खिलवाड़ करने वाले चीन के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए भारत द्वारा यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। कोरोना महामारी के बीच पिछले माह ही भारत ने चीन और अन्य पड़ोसी देशों से सीधे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर अपना सुरक्षा चक्र मजबूत किया। भारत के इस कदम ने चीन को काफी कुपित किया। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने इस संबंध में कहा था कि कुछ खास देशों से प्रत्यक्ष विदेश निवेश के लिए भारत के नए नियम डब्ल्यूटीओ के गैर-भेदभाव वाले सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं और मुक्त व्यापार की सामान्य प्रवृत्ति के खिलाफ हैं। मजे की बात यह है कि यह उस चीन की अपेक्षा है जिसने दुनिया को कोरोना महामारी का दंश दिया।

कोरोना आपदा की राजनीति

इस तरह कोरोना आपदा ने एक ऐसी बदलती विश्व व्यवस्था की दस्तक दे दी है, जहां आरोप-प्रत्यारोप के दौर के बीच पॉलिटिक्स ऑफ जेनरोसिटी यानी उदारता की राजनीति के जरिए वैश्विक छवि को निर्मित करने के प्रयास तो हो

ही रहे हैं, साथ ही ताकत की राजनीति के जरिए कोरोना के बाद के काल में अपनी वैश्विक हैसियत को ऊंचा करने का संघर्ष भी देखा जा रहा है। कोरोना आपदा की राजनीति ने अमेरिका की कमजोरी और चीन के गैर-जिम्मेदाराना नजरिए को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। इससे भारत जैसे उन देशों की वैश्विक भूमिका बढ़ गई है, जिनकी सॉफ्ट पावर के रूप में छवि भी बेहतर है और हाल के वर्षों में जिन्हें महत्वपूर्ण आर्थिक, सैन्य और तकनीकी ताकत के रूप में देखा जाने लगा है।

अमेरिका कमजोर हुआ

वैश्विक राजनीति में भारत ने पहलकारी भूमिका की तलाश की है और इसी दिशा में हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व में भारत सहित दुनिया के सात बड़े देशों की बैठक भी हुई जिसमें कोविड-19 की उत्पत्ति के प्रति पारदर्शिता लाने की मांग की गई है। हालांकि इसका मुख्य फोकस कोविड-19 को लेकर चीन की नकारात्मक भूमिका की आलोचना करना था। मगर भारत बखूबी जानता है कि कोरोना के चलते अमेरिका कमजोर हुआ है और अमेरिका के कमजोर होने से महत्वाकांक्षी चीन की वर्चस्ववादी नीतियों को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। वहीं पिछले कुछ वर्षों से जिस प्रकार चीन भारत को उसकी सीमाओं व पड़ोस में घेरने की नीति अपनाता रहा है, ऐसे में चीन को मिलने वाली यह बढ़त भारत के सामरिक हितों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए भारत ने वैश्विक गठजोड़ की नई राहें पकड़ी हैं।

भारत की बिग ब्रदर की छवि

भारत अपनी छवि को सॉफ्ट पावर के रूप में और अधिक मजबूत आधार देने की कोशिश में जुटा है। जहां मेडिकल डिप्लोमेसी के जरिए भारत सार्क देशों को एक बार फिर एक मंच पर साथ लाने में कामयाब होता दिख रहा है, वहीं पाकिस्तान के इस मंच पर भी गैरजिम्मेदाराना व्यवहार को निशाना बनाने के जरिए भारत ने दक्षिण एशियाई देशों को यह संदेश दे दिया कि भारत के लिए उसका पड़ोस प्रथम है। पड़ोसी देशों में भारत की बढ़ती स्वीकार्यता का बड़ा उदाहरण नेपाल द्वारा 17 मई को भारत सरकार द्वारा दिए गए स्वास्थ्य सहायता के लिए धन्यवाद प्रेषण के रूप में देखा जा सकता है। यह भारत की परंपरागत बिग ब्रदर की छवि को बदलने का और पड़ोस प्रथम नीति को अधिक प्रभावी बनाने का सर्वोत्तम अवसर है। अफगानिस्तान को दी गई चिकित्सकीय सहायता भारत की प्रोएक्टिव विदेश नीति का ही प्रमाण है। इस महामारी के समय एक तरफ जहां तालिबान ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि भारत पिछले चार दशक से अफगानिस्तान में नकारात्मक भूमिका निभाता आया है, तो वहीं अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान को इसका जवाब देते हुए कहा है कि भारत वह देश है जिसने हमें सबसे ज्यादा दान दिया है और सबसे ज्यादा मदद की है। वास्तव में भारत ने अपने बुद्धिमत्तापूर्ण कदमों से उन राष्ट्रों का भी विश्वास जीता है जो भारत का समय-समय पर अवसरवादी मानसिकता के कारण विरोध करते रहे हैं।

भारत ने निभाया चिकित्सा धर्म

भारत ने विश्व समुदाय को चिकित्सकीय सहायता देकर यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि वैश्विक स्वास्थ्य को वह वैश्विक मानवाधिकार के रूप में देखता है। भारत ने अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 10 टन चिकित्सकीय सामग्री, नेपाल को 23 टन आवश्यक औषधि जिसमें हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन और पैरासिटामॉल आदि शामिल है व भूटान को व्यापक चिकित्सकीय आपूर्ति की खेप भेजी है। भारत ने बांग्लादेश को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की एक लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने व संयुक्त अरब अमीरात को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के 50 लाख टैबलेट प्रदान किए हैं।

फिलहाल भारत कोरोना वायरस से प्रभावित करीब 55 देशों को सहायता और वाणिज्यिक आधार पर हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है। भारत ने अमेरिका, सेशेल्स और मॉरीशस समेत म्यांमार, ब्राजील व इंडोनेशिया जैसे देशों को भी यह दवा भेजी है। इन सभी देशों ने भारत का आभार व्यक्त किया है। इस बीच बदलते दौर में दुनिया में आर्थिक संरक्षणवाद जिस तरह बढ़ रहा है, उस स्थिति में कोरोना के बाद के काल में विश्व में भारत को अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था में बड़े संरचनात्मक सुधार करने होंगे। आज के विश्व में सफल घरेलू नीति ही विदेश नीति को अधिक ठोस आधार दे सकती है।

आसान नहीं आर्थिक त्रासदी से मुक्ति की राह

अब यह किसी से छिपा नहीं है कि कोरोना महामारी ने दुनिया समेत भारत की अर्थव्यवस्था को त्रासदी की ओर धकेल दिया है। एक ओर जहां कल-कारखाने से लेकर सभी प्रकार के कार्यों में व्यापक बंदी है, वहीं सरकार को मिलने वाले आर्थिक लाभ मसलन जीएसटी व आयकर आदि भी हाशिए पर हैं। इस बीच सरकार लोगों की स्वास्थ्य रक्षा और जीवन मोल को देखते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान कर चुकी है। लेकिन यह आर्थिक पैकेज राहत से ज्यादा बिना आय वाला योजनागत व्यय का ब्यौरा है। देखा जाए तो सरकार सारे इंतजाम कर रही है, पर समस्या इतनी बड़ी है कि सब नाकाफी है। देश में असंगठित कामगार इन दिनों पूरी तरह खाली हाथ हैं और लगातार उखड़ रही अर्थव्यवस्था के चलते उनकी राह में भूख और जीवन की समस्या भी स्थान घेर रही है। शहरों से मजदूर व्यापक पैमाने पर गांव की ओर जा रहे हैं। बरसों बाद यह भी पता चला कि भारत वाकई में गांव का ही देश है और जब सभ्यता व शहर पर गाज गिरती है, तब जीवन का रुख गांव की ओर ही होता है। सरकार के सामने अनेक दुविधाएं हैं। कोरोना से निपटना, आर्थिक त्रासदी से मुक्ति, ठप पड़ी व्यवस्था को सुचारू करना आदि। इसमें कृषि, उद्योग व सेवा संबंधी सभी इकाइयां शामिल हैं। कहा जाए तो लोक विकास के लिए नीतियां बनाने वाली सरकारें आज कोरोना महामारी के चलते चौतरफा समस्याओं से घिरी हुई हैं। नागरिकों पर भी गरीबी की गाज लगातार गिर रही है। सवाल यह है कि आर्थिक त्रासदी से आर्थिक सुशासन की राह पर गाड़ी कब आएगी?

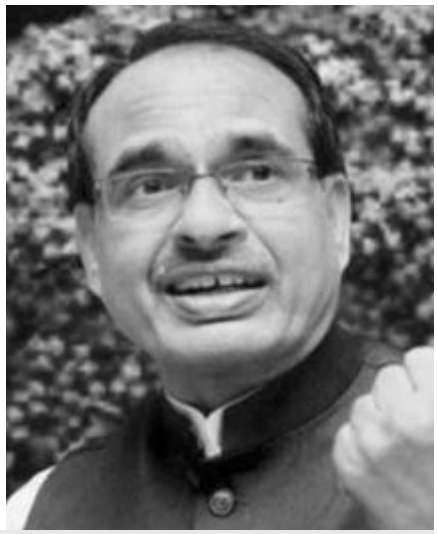

चीनी कंपनियों के लिए अलग नीति बनाएगी मप्र सरकार

कोरोना संकट के कारण ठप हुई आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने की कोशिशें शिवराज सरकार ने शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में विगत दिनों प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने अमेरिका की बड़ी कंपनियों के उच्च अधिकारियों से वेबिनार के माध्यम से बात की। इस दौरान यह भी भरोसा दिलाया गया कि जो कंपनी चीन से पलायन करके मध्य प्रदेश में अपनी इकाई स्थापित करेगी, उनके लिए अलग नीति बनाई जाएगी और विशेष पैकेज भी दिया जाएगा। अमेरिका की जो कंपनियां प्रदेश आना चाहती है, उनको भी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कोरोना संकट की वजह से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है। इसे फिर से खड़ा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संकट को अवसर के तौर पर देखते हुए अधिकारियों को अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के निर्देश दिए हैं। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारियों ने गत दिनों यूएस-इंडिया स्ट्रेटजी पार्टनरशिप फोरम के माध्यम से पेप्सी, केटरपिलर, क्युमिंस, वेरियन मेडिकल, नाइकी, वालमार्ट सहित अन्य कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान कंपनियों के अधिकारियों को बताया गया कि मध्य प्रदेश में उद्योगों के अनुकूल माहौल है। भविष्य में जो भी अमेरिका की कंपनियां विश्व के किसी भी भाग से भारत आना चाहती है तो मध्य प्रदेश उनको जरूरत के मुताबिक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। जो उद्योग चीन से पलायन करके मध्य प्रदेश में अपनी इकाइयां स्थापित करेंगे, उनके लिए शासन अलग नीति बनाएगा। इसके साथ ही विशेष पैकेज भी दिया जाएगा। इस पर काम चल रहा है।

एक समान विकास की जरूरत

भारत में अभी विकास और औद्योगिकीकरण में असमानता देखने को मिलती है। अधिकतर देशी-विदेशी कंपनियों का रुख नोएडा, गुरुग्राम, तमिलनाडु, मुंबई, बैंगलुरू जैसे शहरों की ओर होता है। इस कारण इन शहरों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता है। इसलिए केंद्र सरकार को सबसे पहले यह कोशिश करनी होगी कि वह देश के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करवाए। चीन या किसी और देश से आने वाली कंपनियों को मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार आदि राज्यों में स्थापित करवाए। ताकि वहां के लोगों को उनके ही राज्य में रोजगार मिल सके।

योगी की पहल सराहनीय

कोरोना के इस संक्रमणकाल में चीन से कंपनियों के पलायन की खबर आते ही उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दो मंत्रियों और कुछ अधिकारियों को इस काम में लगा दिया कि वे चीन से आने वाली कंपनियों को अपने यहां लाने का प्रयास करें। यही नहीं उन्होंने प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों के लिए भू-खंड भी आरक्षित करवा दिया। इसका प्रतिफल यह हुआ है कि कई कंपनियों ने उत्तरप्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों का भ्रमण किया है। इससे राज्य में औद्योगिक विकास की संभावना बढ़ी है। शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न प्रदेशों से पलायन करके उप्र पहुंचे मजदूरों के लिए माइग्रेशन कमीशन बनाने का निर्देश दिया है। प्रवासी मजदूरों एवं श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। यह आयोग प्रवासी मजदूरों को उनके कौशल के हिसाब से रोजगार उपलब्ध कराएगा। हाल के दिनों में अन्य राज्यों से करीब 23 लाख प्रवासी मजदूर उत्तरप्रदेश लौटे हैं। उत्तरप्रदेश सरकार की कोशिश है कि वह अपने प्रदेश के अधिक से अधिक श्रमिकों का पलायन रोके। यह तभी संभव है जब राज्य में औद्योगिक विकास होगा।

मौका मैदान मारने का

कोरोना संक्रमण का यह दौर मैदान मारने का मौका भी है। फिलहाल देश में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने यहां निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। देर से ही सही मध्य प्रदेश सरकार भी इस मौके का फायदा उठाने में जुट गई है। लेकिन सरकार की इस कोशिश को विपक्ष महज दिखावा बता रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते हैं कि पूर्व में भाजपा की सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास के बड़े-बड़े दावे करती रही। लेकिन आंकड़ेबाजी के इस खेल की पोल खुल गई है। वह कहते हैं कि हमें नहीं लगता है कि मप्र सरकार चीन से पलायन करने वाली किसी कंपनी को आकर्षित कर पाएगी।

पूर्व मुख्यमंत्री की बात में दम भी लगता है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के पूर्ववर्ती कार्यकाल में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए करीब एक दर्जन इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किए गए। हर समिट के बाद लाखों-करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश के दावे किए गए। जबकि हकीकत में यह तथ्य सामने आया कि निवेश करने वाली कंपनियों को यहां कायदे-कानून के चक्कर में इतने फेरे लगवाए गए कि उन्हें निराश होकर मप्र से मुंह मोड़ना पड़ा।

भारत के सामने बड़ा अवसर

चीन के प्रति विश्व में बढ़ते घृणा का भाव भारत के लिए बड़ा अवसर है कि वह आर्थिक संबंधों में चीन का विकल्प बन सके। ऐसे में जब विश्व की अधिकांश कंपनियां चीन से बाहर निकल रही हैं तो भारत उनके लिए बेहतर गंतव्य स्थल के रूप में खुद को स्थापित करने में लगा है। भारत द्वारा रक्षा कंपनियों के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को बढ़ा दिया गया है तो दूसरी तरफ भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत पर दिया जा रहा फोकस भी इसी उद्देश्य से प्रेरित है। वर्तमान आपदा के दौरान भारत की विदेश नीति में एक और महत्वपूर्ण बात जो देखी गई है, वह है गुटनिरपेक्ष देशों के संगठन का प्रभावी इस्तेमाल भारत की कूटनीतिक पहुंच और मानवतावादी प्रतिक्रिया को विश्व समुदाय के समक्ष रखने के लिए करना। भारतीय प्रधानमंत्री पर वर्ष 2016 और 2019 के 'नैम समिट' में भाग नहीं लेने और उसकी उपेक्षा के आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब पीएम मोदी द्वारा महामारी से निपटने के लिए इसके वर्चुअल समिट को महत्व दिया गया है। भारत ने नैम के 59 देशों को चिकित्सकीय सेवाओं की आपूर्ति भी की है। अब देखना यह है कि विश्व शक्ति बनने के कगार पर खड़े भारत का भविष्य क्या गुल खिलाता है।

अवैध खनन अनलॉक

कोरोना वायरस कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन अवैध खनन लॉक नहीं है। लॉकडाउन के बाद भी अवैध रेत के उत्खनन और परिवहन करने वाले रेत माफियाओं के हौंसले बुलंद हैं। बैतूल, होशंगाबाद, सीहोर, जबलपुर सहित प्रदेशभर में अवैध खनन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और पुलिस अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई भी कर रही है। उसके बावजूद अवैध खनन का कारोबार जोरों पर है।

उधर, प्रदेशभर में रेत खदानें बंद होने से रेत के दाम आसमान छू रहे हैं। खदानों से चोरी-छिपे निकल रही रेत के व्यापारी मनमाने दाम वसूल रहे हैं। इस सीजन में 25 से 27 रुपए फीट बिकने वाली रेत वर्तमान में 52 से 60 रुपए फीट बिक रही है। यह लॉकडाउन नहीं, सिस्टम की नाकामी का असर है। दिसंबर 2019 में खदानें नीलाम करने के बाद भी सरकार समय से खनन शुरू नहीं करा पाई है। जिसका फायदा बिचौलिए उठा रहे हैं। राजधानी सहित प्रदेशभर में रेत महंगी हो गई है और यह स्थिति अगले छह माह रहने वाली है। क्योंकि बारिश के चलते 15 जून से खदानों से रेत का उत्खनन बंद हो जाएगा। ऐसे में बिचौलिए भंडारित रेत को मनमाने दाम पर बेचेंगे। वर्तमान में नर्मदा सहित अन्य नदियों से चोरी-छिपे रेत निकाली जा रही है।

यह रेत भंडारित भी हो रही है और बेची भी जा रही इसलिए व्यापारियों ने मनमाने दाम वसूलना शुरू कर दिया है। मार्च से 15 जून तक आमतौर पर सभी घाट खुले रहते हैं। ऐसे में रेत के दाम 25 रुपए फीट या उससे भी नीचे पहुंच जाते हैं। रास्ते में चैकिंग ज्यादा हो या घुमावदार रास्ते से लाना पड़े, तो दाम 27 रुपए फीट होते हैं, पर इस बार 700 फीट भरती का ट्रक 17,500 से 19 हजार की बजाय 32 और 34 हजार रुपए में आ रहा है। वहीं खुली रेत (ट्राली या आटो से) 52 से 60 रुपए फीट तक बिक रही है। 34 जिलों के ठेकेदारों ने अनुबंध तक नहीं किया। खनिज विभाग ने अगस्त 2019 से प्रदेश के 1450 रेत खदानों की नीलामी शुरू की थी। दिसंबर 2019 में 40 जिलों की खदानें नीलाम भी कर दी गईं, पर इनमें से एक भी खदान सरकार शुरू नहीं करा सकी। ठेकेदार अभी तक पर्यावरण और उत्खनन की अनुमति ही नहीं ले पाए हैं।

हद तो यह है कि पांच महीनों में 34 जिलों में ठेकेदारों ने खनिज निगम से अनुबंध तक नहीं किया इसीलिए विभाग ने 30 मई तक अनुबंध करने वाले ठेकेदारों से उत्खनन के लिए छह माह अतिरिक्त देने का वादा किया था। पंचायत की खदानें भी बंद, सरकार नई खदानें शुरू नहीं कर पाई। ठेकेदारों को पर्यावरण व उत्खनन अनुमति नहीं दे पाई और ग्राम पंचायतों की 450 खदानें मार्च से बंद कर दीं। कमलनाथ सरकार की खनिज नीति में यह प्रावधान था। इस निर्णय ने समस्या को और विकराल बना दिया है।

उधर, नर्मदा सहित अन्य नदियों में धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है। बैतूल में तवा नदी पर रेत का अवैध तरीके से उत्खनन लंबे समय से किया जा रहा है। नदी से करीब आधा एकड़ क्षेत्र में अवैध उत्खनन माफियाओं द्वारा किया जाना सामने आया है। यहां अवैध रूप से खनन स्वीकृत रेत खदान से कुछ दूरी पर किया जा रहा था। विगत दिनों करीब 50 ट्रकों से रेत का अवैध खनन तथा परिवहन की जानकारी मिलने पर तहसीलदार, शाहपुर टीआई सहित पुलिस और राजस्व की टीम कार्रवाई करने निकली थी। इस दौरान रेत माफियाओं के इशारे पर ट्रकों के ड्राइवर, ग्रामीण तथा रेत भरने वाले मजदूरों ने टीम पर पथराव कर दिया। पुलिस ने इस घटना में 14 आरोपियों को पकड़कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है। शेष 21 आरोपियों की तलाश की जा रही है। इधर सैनिक फूड कार्पोरेशन को स्वीकृत खदान के अलावा पास ही 2300 वर्गफीट में अवैध खनन के निशान मिले हैं, जिसकी जांच जिला खनिज अधिकारी शशांक शुक्ला द्वारा की जा रही है।

● **अक्स ब्यूरो**

कंप्यूटर बाबा से तो अच्छा काम रहे मंत्री कमल पटेल

उधर, प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो लोग अवैध तरीके से मशीनों के माध्यम से नर्मदा नदी में रेत उत्खनन कर रहे हैं, उन पर इस नदी की हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज किया जाए। सरकार द्वारा प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा को जीवित इकाई माने जाने के बाद उन्होंने यह बात कही है। पटेल ने बताया कि मां नर्मदा हमारी जीवनदायिनी नदी है। प्रदेश सरकार द्वारा मां नर्मदा को एक जीवित इकाई माना गया है और यह हमारी श्रद्धा का केंद्र है। इसलिए मां नर्मदा का प्रत्येक कंकड़ शंकर है। इसलिए कहा जाता है कि नर्मदे हर-जिंदगी भर। उन्होंने कहा, नर्मदा से जेसीबी जैसी किसी भी प्रकार की मशीन से उत्खनन किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है तथा समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) एवं अन्य न्यायालयों ने भी सभी नदियों में मशीनों से उत्खनन करने पर रोक संबंधी आदेश दिए हैं। पटेल ने कहा, मैंने नर्मदापुरम एवं जबलपुर संभागों के 11 जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो लोग अवैध तरीके से मशीनों के माध्यम से नर्मदा की छाती छलनी कर रेत उत्खनन कर रहे हैं, उन पर मां नर्मदा की हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसी प्रकार कार्रवाई की जाए, जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की हत्या का प्रयास करने में होती है। पटेल नर्मदापुरम एवं जबलपुर संभाग के प्रभारी मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा, मैं प्रदेश के उन जिलों के अधिकारियों को भी शीघ्र पत्र लिखूंगा, जिन जिलों से होकर यह नदी गुजरती है और उनको भी निर्देश दूंगा कि जो लोग अवैध तरीके से मशीनों के माध्यम से नर्मदा में रेत उत्खनन कर रहे हैं, उन पर मां नर्मदा की हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज किया जाए।

बाकी राज्यों में चुनाव कब?

महाराष्ट्र में राज्य विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव संपन्न होने के साथ ही देश की राजनीति गर्माने लगी है। इसकी वजह यह है कि कई राज्यों में होने वाले चुनाव लंबित हैं। कोरोना वायरस के कारण चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। इसी कारण राज्यसभा के चुनाव भी टाल दिए गए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में चुनाव होना यह सवाल खड़ा करता है कि क्या प्रधानमंत्री की विशेष कृपा के बाद ही चुनाव होंगे? इससे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं।

महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'अभूतपूर्व हस्तक्षेप' के बाद विधान परिषद का चुनाव संपन्न हो गया, साथ ही इससे एक नया सवाल यह खड़ा हो गया है कि महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में विधान परिषद और कई राज्यों में राज्यसभा के लिए लंबित उपचुनावों का क्या होगा, जो कोरोना संक्रमण के संकट की वजह से लॉकडाउन के चलते मार्च महीने में ही टाल दिए गए थे?

गौरतलब है कि इस वर्ष राज्यसभा की 73 सीटों और तीन राज्यों की विधान परिषद की करीब 50 रिक्त सीटों के द्विवार्षिक चुनाव प्रस्तावित थे। इनमें से 18 राज्यों से राज्यसभा की 55 और तीन राज्यों– उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में विधान परिषद की करीब 28 सीटों के लिए बीती 26 मार्च को चुनाव होने थे, लेकिन मतदान से ठीक दो दिन पहले चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस संक्रमण का हवाला देते हुए इन चुनावों को टाल दिया था। हालांकि राज्यसभा की 55 में से 37 सीटों का चुनाव निर्विरोध हो चुका है और राष्ट्रपति के मनोनयन कोटे की खाली हुई एक सीट भी सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के मनोनयन से भरी जा चुकी है। लेकिन अभी भी 7 राज्यों में राज्यसभा की 18 सीटों के चुनाव होना बाकी है। सवाल उठता है कि चुनाव आयोग अपने फैसले से पीछे हटते हुए 21 मई को सिर्फ महाराष्ट्र में ही विधान परिषद के चुनाव किस आधार पर करवा रहा है? यह सवाल इसलिए कि कोरोना महामारी के जिस संकट को आधार बनाकर चुनाव टाले गए थे, वह आधार तो अब भी कायम है और वह अभी आगे भी काफी समय तक कायम रहेगा।

चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 18 सीटों और तीन राज्यों की विधान परिषद के चुनाव कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से अगले आदेश तक टाले जाने का फैसला 24 मार्च को जिस समय किया था, उससे चंद घंटे पहले ही मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी और लगभग 114 विधायकों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्वास मत हासिल किया था। जाहिर है जब सत्र चला तब विधानसभा के तमाम अफसर, क्लर्क, सुरक्षा गार्ड और मीडियाकर्मी भी वहां मौजूद रहे होंगे।

मध्य प्रदेश विधानसभा के इस सत्र से एक दिन पहले तक संसद का बजट सत्र भी जारी था। 23 मार्च को दोनों सदनों में वित्त विधेयक पारित कराया गया था। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने चुनाव टालने का फैसला कोरोना वायरस संक्रमण को वजह बताते हुए किया। हालांकि राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव ऐसे नहीं हैं कि जिनमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हों। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन होने के बावजूद सरकार के स्तर पर जिस तरह कई जरूरी और गैरजरूरी काम भी हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं, उसी तरह राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव भी हो सकते थे और अभी भी हो सकते हैं।

राज्यसभा चुनाव भी अधर में

कोरोना महामारी के चलते टाले गए राज्यसभा और दो राज्यों के विधान परिषद चुनाव जून से पहले होना संभव नहीं है। गौरतलब है कि राज्यसभा की 18 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया के बाद मतदान न होने के कारण अभी तक लंबित हैं। इनमें आंध्र प्रदेश की चार, झारखंड की दो, मध्यप्रदेश की तीन, मणिपुर की एक, राजस्थान की तीन, गुजरात की चार और मेघालय की एक सीट शामिल है। उधर, गत दिनों मप्र की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) वीरा राणा ने भी विधानसभा पहुंचकर चुनाव की व्यवस्था संबंधी जानकारी ली। प्रदेश की तीन सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव होने थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण उन्हें स्थगित कर दिया गया। अब फिर से सुगबुगाहट शुरू हुई है। सचिवालय से कई विधायकों को फोन करके स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है। उनसे ये भी पूछा गया कि वे कहां हैं। सूत्रों के अनुसार यह जानकारी इसलिए ली जा रही है कि यदि कोई विधायक कोरोना प्रभावित है, तो उसके लिए राज्यसभा चुनाव के दौरान क्या व्यवस्था की जाए। इधर, सीईओ राणा ने उस स्थान का जायजा लिया, जहां राज्यसभा चुनाव कराए जाते हैं। वहां के हॉल को देखकर उन्होंने कहा कि यह छोटा है, वर्तमान हालात को देखते हुए किसी बड़े हॉल में चुनाव कराना पड़ेगा।

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में

यह सही है कि विधानसभा या लोकसभा के उपचुनाव और स्थानीय निकाय चुनावों में सीधे आम मतदाता की भागीदारी रहती है, लिहाजा कोरोना संकट के चलते अभी उनका चुनाव नहीं कराया जा सकता। लेकिन सीमित मतदाताओं के जरिए होने वाले राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों को टालकर और प्रधानमंत्री के परोक्ष दखल से सिर्फ एक राज्य में चुनाव कराने का फैसला लेना बताता है कि चुनाव आयोग को भले ही संविधान ने एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय की हैसियत बख्शी हो, मगर चुनाव आयोग के मौजूदा नेतृत्व को यह हैसियत स्वीकार नहीं है। वह साफ तौर पर सरकार के आदेशपाल की भूमिका निभा रहा है। चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र की आधारशिला होती है, भले ही वह चुनाव पंचायत का हो या संसद का। किसी भी कारण से चुनावों का टाला जाना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। चुनाव आयोग के रवैए से कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर चलाए गए उस खतरनाक अभियान को भी बल मिलता है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी के संकट के मद्देनजर देश में अगले दस वर्ष तक सभी तरह के चुनाव स्थगित कर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दस वर्ष तक देश का नेतृत्व करने दिया जाए।

हालांकि ऐसा नहीं है कि इन चुनावों के बगैर कोई काम रुक रहा है, फिर भी अगर चुनाव आयोग चाहता तो ये चुनाव 26 मार्च को हो सकते थे। इनके लिए बहुत ज्यादा तैयारी करने की भी जरूरत नहीं थी। मिसाल के तौर पर झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के चुनाव के लिए कुल 81 मतदाता हैं। आयोग चाहता तो तीन से पांच मिनट के अंतराल पर हर विधायक के वोट डालने की व्यवस्था की जा सकती थी। विधानसभा भवन में, जहां मतदान की प्रक्रिया संपन्न होती है, वहां दो-दो मीटर की दूरी पर विधायकों के खड़े होने का बंदोबस्त हो सकता था। मास्क और सैनिटाइजर का भी इंतजाम किया जा सकता था। इसी तरह गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 177, मध्य प्रदेश में 3 सीटों के लिए 206, राजस्थान में 3 सीटों के लिए 200, आंध्र प्रदेश में 3 सीटों के लिए 175 और मणिपुर तथा मेघालय में एक-एक सीट के लिए 60-60 विधायक मतदाता हैं। इसी तरह महाराष्ट्र विधान परिषद की जिन 9 सीटों के लिए चुनाव होना हैं वे सभी विधानसभा कोटे की हैं, जिनके लिए 288 विधायकों को मतदान करना है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के लिए शिक्षक और स्नातक वर्ग की 11 सीटों के लिए और बिहार में इन्हीं वर्गों की 8 सीटों के लिए अलग-अलग जिला मुख्यालय पर वोट डलने हैं, जिसके लिए इंतजाम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मगर चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के बजाय चुनाव टालने का आसान रास्ता चुना। सवाल यही है कि जब चुनाव आयोग महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों के लिए 21 मई को चुनाव कराने का ऐलान कर चुका था तो बाकी राज्यों में विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव टाले रखने का क्या औचित्य है? कोरोना संक्रमण का संकट तो अभी लंबे समय तक जारी रहना है।

इसी साल अक्टूबर में उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की चार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की एक-एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होना है। इसी साल जुलाई में ही बिहार में राज्यपाल के मनोनयन और विधायकों के वोटों से चुनी जाने वाली विधान परिषद की 18 सीटें खाली होने वाली हैं। फिर नवंबर-दिसंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव भी होना है। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा की 24 सीटों पर उपचुनाव सितंबर महीने से पहले कराए जाने की संवैधानिक बाध्यता है। आंध्र प्रदेश और जम्मू-कश्मीर सहित कई राज्यों में स्थानीय निकाय चुनावों पर भी अभी रोक लगी हुई है। आखिर कोरोना संक्रमण के संकट को आधार बताकर इन सभी चुनावों को कब तक टाला जाता रहेगा?

बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने संभावना जताई है कि आगामी विधानसभा चुनाव डिजिटल तरीके से होगा और लोग घरों में बैठे-बैठे ही मतदान कर पाएंगे। उनके इस बयान का सरकार में सहयोगी जेडीयू के साथ कई विपक्षी दलों ने भी कड़ा विरोध किया है। उनके इस बयान पर कई दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सरकार में सहयोगी जनता दल-यूनाइटेड (जेडीयू) ने भी इस पर कड़ा विरोध किया है। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा, भाजपा नेता का यह प्रस्ताव अव्यावहारिक और अलोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव परंपरागत तरीके से ही होना चाहिए। त्यागी ने कहा, चुनाव में आप डिजिटल प्रचार करोगे, रैली करोगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, यह संभव नहीं है। इस बीच राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने भी सुशील मोदी के इस सुझाव का विरोध किया है। उन्होंने कहा है, 'सुशील मोदी हमेशा पिछले दरवाजे से विधान परिषद में पहुंचते रहे हैं, वो लोकतंत्र का मतलब ही नहीं समझते हैं। उनकी इन बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है।' सुशील मोदी ने अपने बयान में कहा था, इस बार चुनाव में राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा डिजिटल माध्यम से वोट मांगते नजर आएंगे। राजनीतिक पार्टियां मोबाइल और टेलीविजन के जरिए वोट की अपील करती दिख सकती हैं। मतदाता भी डिजिटली ऑनलाइन वोटिंग भी करते दिख सकते हैं। बिहार में राजनीतिक दल डोर-टू-डोर कैम्पेन कर सकते हैं। बता दें कि बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के बीच चुनाव कराने को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है।

कोरोना संकट के चलते निर्वाचन आयोग ने गत तीन अप्रैल को आदेश जारी कर इन सभी सीटों के लिए चुनाव अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिए थे। इनमें महाराष्ट्र विधान परिषद की नौ सीटों के चुनाव भी शामिल थे, जिन्हें अब राज्य में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मांग के बाद कराया जा चुका है। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग इन सीटों के लिए चुनाव कराने में जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि स्थितियां अभी सामान्य होती नहीं दिख रही हैं। सीटों के चुनाव न होने से कोई संवैधानिक संकट या बड़ी समस्या भी सामने नहीं आ रही है। इसके चलते इन सीटों के दावेदार कई बड़े नेताओं को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

● **इन्द्र कुमार**

छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू कर दी है। कांग्रेस के नजरिए से देखा जाए तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना एक तरीके से मनरेगा 2.0 ही है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में न्याय लागू कर कांग्रेस सरकार इसे मनरेगा बना पाएगी? कांग्रेस के सामने तत्कालिक सवाल भी यही है और सबसे बड़ा चैलेंज भी।

'न्याय' किसके लिए?

आखिरकार राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट न्याय योजना की शुरुआत हो ही गई। वैसी ही न्याय योजना जिसे लेकर अब राहुल गांधी ने यहां तक कह डाला था कि और कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इसे अस्थायी तौर पर ही लागू कर ले। कोरोना संकट पर सोनिया गांधी की तरफ से लिखी गई चिट्ठियों में भी **न्याय योजना** लागू करने का जिक्र रहा और राहुल गांधी भी लगातार किसी न किसी बहाने ये मांग करते रहे। न्याय योजना कांग्रेस 2019 के आम चुनाव में लाई थी, लेकिन तब भी कांग्रेस को इसका कोई फायदा नहीं मिल सका। कांग्रेस ने न्याय योजना छत्तीसगढ़ में लागू तो करा दी है, लेकिन क्या वह इसका फायदा उठा पाएगी। यह इसलिए कहा जा रहा है कि यूपीए शासनकाल के दौरान मनरेगा सहित जिन योजनाओं को शुरू किया गया था आज वे सभी भाजपा के कब्जे में हैं।

उधर, कांग्रेस का कहना है कि न्याय योजना अर्थशास्त्र के लिए नोबल पुरस्कार पाने वाले अभिजीत बनर्जी ने कांग्रेस के लिए बनाई थी, हालांकि, अभिजीत बनर्जी का कहना है कि उनसे सलाह जरूर ली गई थी, लेकिन उन्होंने इसे तैयार नहीं किया था। हाल फिलहाल अभिजीत बनर्जी और रघुराम राजन से राहुल गांधी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संकट से निबटने के उपाय पूछे थे और दोनों की राय यही रही कि गरीबों के खाते में सीधे मदद की रकम डाली जाए।

कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार के दौरान मनरेगा योजना शुरू की गई थी। तब आरजेडी कोटे से मनमोहन सरकार में मंत्री बने रघुवंश प्रसाद सिंह ने इसे लागू कराया था और माना गया कि 2009 में यूपीए की सत्ता में वापसी में मनरेगा की बहुत बड़ी भूमिका रही। मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को साल में 100 दिन काम की गारंटी दी जाती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल के बाद राहुल गांधी भी अब मांग करने लगे हैं कि मनरेगा के तहत 100 की जगह 200 दिन काम देने का प्रावधान किया जाए। कहने को तो न्याय योजना छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए लाई गई है, लेकिन इसे कांग्रेस अपने उत्थान से जोड़कर देख रही है। जिस तरह मनरेगा ने कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराई थी, अब कांग्रेस को लगता है कि न्याय योजना भी उसे फिर राष्ट्रीय राजनीति में खड़े होने में मददगार साबित हो सकती है।

बेहतर तो यही होता कि न्याय योजना सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि सभी कांग्रेस शासित राज्यों में लागू की गई होती। राजस्थान और पंजाब में भी। कोशिश ये भी की जाती कि इसे महाराष्ट्र और झारखंड में भी लागू किया जाता, जहां की सत्ता में कांग्रेस भी साझीदार है। ऐसा करने पर और कुछ हो न हो, कम से कम मोदी सरकार पर कुछ न कुछ दबाव तो बनता ही। कुछ कुछ वैसे ही जैसे इन राज्यों में प्रधानमंत्री

परित्याग में माहिर कांग्रेस

कांग्रेस पार्टी की विरासत के तेजी से क्षरण में मोदी की चतुराई से अधिक खुद कांग्रेस में दूरदर्शिता का अभाव परिलक्षित होता है। ग्रामीण आवास योजना को इंदिरा गांधी का नाम दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इसमें सामान्य नौकरशाही के स्तर से अधिक रूचि नहीं ली थी। 2009 लोकसभा चुनावों में यूपीए के बेहतर प्रदर्शन का श्रेय आमतौर पर मनरेगा को दिया गया था, लेकिन सोनिया गांधी के समर्थन के बावजूद आगे चलकर इसमें सुधार करने या इसे बढ़ावा देने में पार्टी की रूचि नहीं रही। कांग्रेस ने डीबीटी को शुरू करने के बाद जल्दी ही भुला दिया। लेकिन उसने सबसे बुरा व्यवहार आधार के साथ किया। विशिष्ट पहचान प्रणाली को बहुत धूमधाम से शुरू किया गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे त्याग दिया गया। पार्टी के भीतर प्रतिद्वंदिता, सरकार में आंतरिक मतभेद और सुसंगत नीति की कमी के कारण आम सहमति का अभाव था और इसका खामियाजा नीतियों, योजनाओं और नवाचारों को भुगतना पड़ा। कांग्रेस का नुकसान मोदी का फायदा साबित हुआ, कम से कम यही प्रतीत होता है।

नरेंद्र मोदी की घोषणा से पहले ही लॉकडाउन लागू हुआ और उसकी मियाद भी केंद्र सरकार के ऐलान से पहले ही बढ़ा दी गई। भूपेश बघेल ने न्याय योजना को लेकर सोनिया गांधी का एक वीडियो शेयर किया है।

देखा जाए तो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में न्याय योजना लागू कर खुद को ही चुनौती दे डाली है। कांग्रेस की चुनौती ये है कि वो न्याय योजना को इतने अच्छे तरीके से लागू करे कि इसके लाभार्थियों की जिंदगी पर बदलाव का असर भी दिखाई दे और फिर देश के हर राज्य में इसे लागू करने की मांग उठे। ऐसा होने पर कांग्रेस को भी केंद्र सरकार पर दबाव बनाने में आसानी होगी। वैसे भी हाल ही में राहुल गांधी ने कहा भी था कि मीडिया का साथ मिल जाने से मोदी सरकार पर दबाव बनाना आसान हो जाता है।

अगर वाकई न्याय योजना दमदार है। अगर वाकई न्याय योजना लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकती है। अगर वाकई न्याय योजना का असर मोदी सरकार के आर्थिक पैकेज के मुकाबले ज्यादा असरदार साबित हो सकता है तो निश्चित तौर पर लोगों के साथ साथ कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। फिर तो वो दिन भी आ सकता है जब मोदी सरकार अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी तौर पर न्याय योजना वैसे ही लागू कर दे जैसे मनरेगा को लागू करने के बाद उसके फंड में भी इजाफा किया गया है। राहुल गांधी ने तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया था। ये बात अलग है कि धन्यवाद कम और तंज ज्यादा लग रहा था क्योंकि ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का पुराना वीडियो शेयर किया था जिसमें वो मनरेगा की बुराई कर रहे थे।

ग्रामीण भारत पर पकड़ एक राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस की ताकत हुआ करती थी, पर धीरे-धीरे इस क्षेत्र में भाजपा जगह बनाने लगी जो कि पहले अधिकाधिक शहर केंद्रित पार्टी मानी जाती थी। हालांकि इसका चुनावी या राजनीतिक रूप से अधिक प्रतीकात्मक महत्व है। मोदी ने कांग्रेस की पहलकदमियों का इस्तेमाल अपनी जनकल्याणकारी छवि गढ़ने के लिए किया है। और यह संभव कैसे हुआ? ऐसा सिर्फ इसलिए हो सका क्योंकि कांग्रेस ने खुद ही अपनी बनाई योजनाओं को त्यागने या उसे अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में प्रचारित नहीं करने की मूर्खता की। इसके विपरीत, मोदी ने अपने प्रतिद्वंदी की पहल का चालाकी से उपयोग करने और आगे चलकर उन्हें अपनी योजनाओं के रूप में पेश करने के महत्व को समझा।

2014 में सत्ता में आने के बाद से ही नरेंद्र मोदी ने बड़ी सटीकता के साथ अपने पूर्ववर्तियों के कई नवाचारों को अपनाया है, जिससे उन्हें कल्याणकारी शासन का अपना मॉडल तैयार करने में मदद मिली है। याद करें 2014 का साल जब मोदी ने देश की सत्ता बस संभाली ही थी। उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दी गई आधार योजना को निकालकर झाड़ा-पोंछा, कई उच्चस्तरीय बैठकें की और स्पष्ट कर दिया कि विशिष्ट पहचान संख्या की इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में इस योजना की परिकल्पना करने वाली यूपीए सरकार ने इसका कानूनी आधार तैयार नहीं किया था। ये काम मोदी सरकार ने किया जिसने इसके समर्थन में कानून बनाया और उसके बचाव में लंबी और ध्रुवीकृत कानूनी लड़ाई लड़ी।

इसी तरह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डीबीटी योजना भी कांग्रेस द्वारा 2013 में बहुत धूमधाम के साथ शुरू की गई (जो आधार के साथ सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के वितरण की व्यवस्था को मजबूत करती है), जिसे मोदी ने गरीब समर्थक नीतियों के कार्यान्वयन में जमकर इस्तेमाल किया है और अभी कोरोनावायरस महामारी के दौरान भी उनकी सरकार ने गरीबों की मदद करने के लिए नकदी हस्तांतरण के इस तंत्र के उपयोग की बात की थी।

ग्रामीण आवास योजना 'इंदिरा आवास योजना' के **कार्यान्वयन से संबंधित** अनेक गड़बड़ियां थीं। मोदी ने इस योजना के महत्व को महसूस किया और इसका नाम बदलकर 2015 में इसे खुद से जोड़ लिया, लेकिन साथ ही इसमें कई बदलाव भी किए जिससे यह पहले की तुलना में अधिक प्रभावी और लोकप्रिय बन सकी। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले बार-बार सुनाई देने वाला एक जुमला था- 'मोदीजी ने घर दिया है', जिसने दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता हासिल करने में प्रधानमंत्री की बहुत मदद की।

अब एक बड़ी राशि आवंटित करते हुए मोदी ने मनरेगा को बिल्कुल अपना बना लिया है, ये अलग बात है कि 2015 में संसद में अपने संबोधन में उन्होंने इसे 'यूपीए की विफलताओं का जीता जागता स्मारक' करार दिया था। 2011 में यूपीए द्वारा शुरू की गई सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के आंकड़े आखिरकार 2015 में सामने आए और उसके बाद से ये लाभार्थियों को पहचानने और उन्हें लक्षित कर कल्याणकारी नीतियों के कार्यान्वयन में इस सरकार का आधार बन चुके हैं। दरअसल मोदी को अपने कार्यकाल के आरंभ में ही ये अहसास हो गया था कि 'सूट-बूट की सरकार' की छवि उनके पतन की वजह बन सकती है और बिना समय गंवाए उन्होंने 'जनकल्याण' का रुख कर लिया। उन्हें ज्यादा कुछ करना भी नहीं था, क्योंकि कांग्रेस ने अधिकतर तैयारी कर छोड़ी थी। उन्होंने बस अपनी रेसिपी के अनुसार उनको परस्पर मिलाने और मोदी तड़का लगाकर अपना बताते हुए बेचने का काम किया। बेशक, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने इन योजनाओं के महत्व को समझा और इन्हें लागू करने की इच्छाशक्ति प्रदर्शित की।

● **दिल्ली से रेणु आगाल**

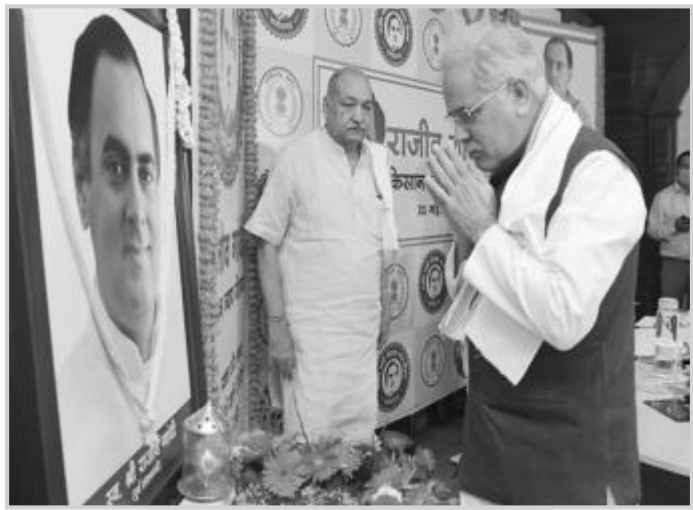

मोदी ने हड़पी कांग्रेस की विरासत

कांग्रेस ने कल्याणकारी तंत्र की सामग्री तैयार कर रखी थी। प्रधानमंत्री ने बस अपनी रेसिपी के अनुसार उनको परस्पर मिलाने और मोदी 'तड़का' लगाकर अपना बताते हुए बेचने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धीरे-धीरे लेकिन बहुत गंभीरता और राजनीतिक चतुराई के साथ, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों की अधिकांश कल्याणकारी विरासत को हड़प लिया है। आधार से लेकर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना और मनरेगा से लेकर ग्रामीण आवास योजना तक- मोदी सरकार ने कांग्रेस की कई बहुप्रचारित पहलकदमियों को अपना लिया है, जिसके बल पर भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण-बनिया पार्टी की अपनी पुरानी छवि को मिटाते हुए ग्रामीण भारत के हितैषी के रूप में खुद को स्थापित कर पा रही है। भाजपा के इस कदम से कांग्रेस को सबक लेना चाहिए कि किस तरह किसी योजना को अपने रंग में रंगा जाता है।

नक्सली समस्या पर लगाम

पुलिसकर्मियों की शहादत, लूट, आईईडी ब्लास्ट में कमी

नक्सल घटनाओं में इस वर्ष 19 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जबकि बीते साल यह आंकड़ा 53 था। इस तरह इस साल शहीद पुलिसकर्मियों की संख्या में 64.15 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। आंकड़े बताते हैं कि विगत वर्ष छह गोपनीय सैनिक तो इस साल तीन गोपनीय सैनिक शहीद हुए। पिछले साल आईईडी विस्फोट की 77 एवं इस वर्ष 41 घटनाएं हुईं। इस साल आईईडी विस्फोट की घटनाओं में 46.75 प्रतिशत की कमी आई। नक्सली घटनाओं में हथियार लूट की घटनाओं में 56.25 प्रतिशत की कमी देखी गई। राज्य के पुलिस महानिरीक्षक (नक्सल ऑपरेशन) सुंदर राज पी. ने कहा- 'नक्सल प्रभावित इलाकों में विश्वास, विकास और सुरक्षा का जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। सुरक्षा बल जहां घोर नक्सल प्रभावित इलाकों तक पहुंचे हैं, वहीं नक्सल संगठन कमजोर हुए हैं। पुलिस को जन सामान्य का साथ मिला है। पुलिस की ऑपरेशन कैपेबिलिटी से बड़ा बदलाव आया है।'

25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला स्थित झीरम घाटी में नक्सली हमले में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 30 से ज्यादा कांग्रेसी नेता मारे गए थे। इस दिल दहला देने वाली घटना के 7 साल बाद भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस दिन को झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाने का निर्णय किया है। देश में नक्सली हिंसा से वैसे तो कई राज्य जूझ रहे हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में तीन दशकों से पसरे लाल आतंक का अब तक कोई अंत नहीं हो पाया है। ये जरूर है कि लाल आतंक की हिंसा में राजनीतिक दलों से लेकर सुरक्षा जवान हर दिन मौत की नींद सोते जा रहे है। इस मामले में कई तरह की जांच आज भी चल रही हैं। झीरम में हुए माओवादी घटनाक्रम के पीछे साजिश की बातें भी बड़े जोर-शोर से हुईं। इस घटनाक्रम को हुए 7 साल बीत गए हैं। अब तक उस घटना से जुड़े बड़े माओवादी लीडरों की न तो गिरफ्तारी हो सकी है और न ही जांच एजेसियों की कोई रिपोर्ट सामने आई हैं।

छत्तीसगढ़ में सत्ता बदलने के बाद नक्सली समस्या पर लगाम लगाने की कोशिशें कामयाब होने लगी हैं। बीते एक साल के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि राज्य में जहां शहीद होने वाले जवानों की संख्या में कमी आई है, वहीं आम नागरिक भी नक्सलियों का निशाना बनने से बचा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार नक्सल समस्या को खत्म करने के लिए कार्ययोजना बनाने का दावा करते रहे हैं। उनका कहना है कि 'नक्सलवाद को खत्म करने के लिए विकास के साथ विश्वास और सुरक्षा चाहिए। सरकार पर भरोसा होना चाहिए। मैंने वहां आदिवासियों की जमीन वापस की। रोजगार के बेहतर अवसर दिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, कुपोषण के लिए डीएमएफ का पैसा खर्च किया। सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि नक्सली गतिविधियों में 40 प्रतिशत कमी आई है।'

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलवाद के लिए केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों की सरकार को घेरा है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि कोई भी बड़ा नक्सली छत्तीसगढ़ का नहीं है, इसके बाद भी सबसे ज्यादा नक्सल समस्या प्रदेश में है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की बैठक में यह प्रस्ताव रखा था कि पड़ोसी राज्य और केंद्र सरकार नक्सलियों के बड़े लीडरों को कंट्रोल करें, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि नक्सलियों के पास से जो हथियार बरामद हुए है, वह जर्मनी और इटली के थे, विदेशी हथियार और गोली यहां कैसे पहुंची। इसकी जांच और रोक तो राज्य सरकार कर नहीं सकती है। जो कारतूस मिले वो विदेशों या अन्य राज्यों की फैक्ट्रियों में बने हुए थे, वो यहां कैसे पहुंचे। इसके लिए केंद्र को गंभीर कदम उठाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झीरम कांड में एनआईए ने फाइनल रिपोर्ट दे दी है। हमने एसआईटी का गठन किया है। झीरम घाटी नक्सली हमले के पीछे जो षड्यंत्र रहा पूर्व में उसकी जांच नहीं हुई। गवाहों से पूछताछ नहीं हुई। नक्सलियों के प्रवक्ता गुड्सा उसेंडी ने समर्पण किया। पड़ोसी राज्य में वह बंद है। उससे आज तक पूछताछ नहीं की गई। इससे जुड़े तथ्य जनता के सामने आने चाहिए।

भूपेश बघेल का कहना है कि अगर सभी राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करें तो नक्सल समस्या का समाधान किया जा सकता है। वह कहते हैं कि नक्सल समस्या का समाधान सहानुभूति से नहीं कठोरता से ही हो पाएगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य का बड़ा हिस्सा नक्सल प्रभावित है। यहां के 14 जिले सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलरामपुर और कबीरधाम नक्सल समस्या से प्रभावित हैं। इन इलाकों में अतीत में नक्सली राजनेताओं से लेकर प्रभावशाली लोगों तक को अपना निशाना बना चुके हैं। राज्य में सत्ता बदलने के बाद इस समस्या से निपटना नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है। भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों में भरोसा पैदा करने की मुहिम चलाई तो दूसरी ओर सुरक्षा बलों के जरिए नक्सलियों को घेरने के प्रयास तेज किए।

राज्य में नक्सल अभियान से जुड़े एक अधिकारी की तरफ से उपलब्ध कराए गए आंकड़े के अनुसार, भूपेश सरकार के सत्ता संभालने के बाद नक्सली घटनाओं में काफी कमी आई है। बात मुठभेड़ों की करें तो बीते साल 2018 में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ की 166 घटनाएं हुईं, वहीं इस साल मुठभेड़ की 112 घटनाएं हुईं। इस प्रकार पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 32.53 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। इसी तरह पिछले वर्ष मुठभेड़ में 124 नक्सली मारे गए थे, जबकि इस वर्ष 77 नक्सली मारे गए हैं। विभिन्न नक्सली घटनाओं में पिछले साल 89 लोगों की जानें गई थीं, वहीं इस साल 46 नागरिकों की जानें गईं हैं। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में इस साल मृत लोगों की संख्या में 48.31 प्रतिशत की कमी आई है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

अब विष्णुदत्त बने मुसीबत का फंदा

विष्णुदत्त विश्नोई सुसाइड नहीं कर सकते

राजस्थान के राजगढ़ में थाना प्रभारी विष्णुदत्त विश्नोई के 'आत्महत्या' का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कोई ये मानने को तैयार ही नहीं है कि अपराधियों के छक्के छुड़ाने वाले एक दबंग और ईमानदार पुलिस अधिकारी ने इस तरह आत्महत्या की होगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलदीप विश्नोई ने भी आशंका जताई है कि ये आत्महत्या नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। कुलदीप विश्नोई ने अपने पत्र में लिखा है कि विष्णुदत्त विश्नोई की 'कथित आत्महत्या' की सीबीआई जांच कराई जाए। उन्होंने विष्णुदत्त को ईमानदार, कर्त्तव्यपरायण और जांबाज पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा कि 1997 में नियुक्ति के बाद वो जहां भी रहे, अपनी कर्त्तव्य निष्ठा से आमजनों और पुलिस विभाग के प्रति हमेशा से जवाबदेह रहे। उन्होंने कहा कि वो मान ही नहीं सकते कि विष्णुदत्त जैसे ऑफिसर ने आत्महत्या की है।

राजनीति में संयोग महत्वपूर्ण होते हैं। संयोग से समीकरण बनते हैं। संयोग से वे हालात पैदा होते हैं, जो भविष्य की तस्वीर दिखाते हैं। ऐसा ही संयोग राजस्थान की राजनीति में इस वक्त बनता दिख रहा है। असल में, एक पुलिस अधिकारी की आत्महत्या से इस वक्त प्रदेश की कांग्रेस सरकार और उसकी एक विधायक पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उसी तरह के हैं जिनसे 2011 में राजस्थान की कांग्रेस सरकार और उसके नेताओं को जूझना पड़ा था।

2011 में भंवरी देवी नाम की एक नर्स के गायब होने से राजस्थान की सियासत गरम हो गई थी। ठीक उसी तरह जैसे आज विष्णुदत्त विश्नोई की आत्महत्या पर सियासी उफान दिख रहा है। संयोगों की सियासत देखिए उस वक्त भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। मुख्यमंत्री आज की तरह ही अशोक गहलोत थे। विवादों के केंद्र में कांग्रेस नेता महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह उसी तरह थे, जैसे आज कृष्णा पुनिया पर उंगली उठ रही है।

विष्णुदत्त विश्नोई की आत्महत्या की खबर सामने आने के बाद न केवल सियासत गरम है, बल्कि सोशल मीडिया में आम लोगों की प्रतिक्रिया देखें तो ऐसा लगता है कि उन्हें भी इस पर यकीन नहीं हो रहा। ये राजस्थान के वे लोग हैं जिनके इलाके में अपने सेवा काल के दौरान विश्नोई तैनात रहे थे। इन लोगों ने विश्नोई के होने से अपराधियों में पैदा डर को देखा था। ये उन आंदोलनों के गवाह रहे हैं जो तब हुए जब विश्नोई का तबादला उनके इलाके से कर दिया गया था। विष्णुदत्त विश्नोई चुरू जिले के राजगढ़ थाना प्रभारी थे। गत दिनों अपने सरकारी क्वार्टर में फंदे से लटके मिले थे। कहते हैं कि उनकी पोस्टिंग पब्लिक डिमांड पर होती थी। जब किसी इलाके में अपराध बेकाबू हो जाता था तो विश्नोई को वहां भेजा जाता था। जाहिर है ऐसे अधिकारी की आत्महत्या की खबर से हर किसी को हैरान होना था और वे हुए भी।

विश्नोई दो सुसाइड नोट छोड़कर गए हैं। इनमें से एक में अपने जिले की एसपी तेजस्विनी गौतम को उन्होंने लिखा है; आदरणीय मैडम। माफ करना। प्लीज, मेरे चारों तरफ इतना प्रेशर बना दिया गया कि मैं तनाव नहीं झेल पाया। मैंने अंतिम सांस तक मेरा सर्वोत्तम देने का राजस्थान पुलिस को प्रयास किया। निवेदन है कि किसी को परेशान नहीं किया जाए। मैं बुजदिल नहीं था। बस तनाव नहीं झेल पाया। मेरा गुनहगार मैं स्वयं हूं।

दूसरा सुसाइड नोट उन्होंने अपने माता-पिता के नाम से लिखा था। इसमें लिखा है; आदरणीय मां-पापा। मैं आपका गुनाहगार हूं। इस उम्र में दुख देकर जा रहा हूं। उमेश, मंकू और लक्की मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपको बीच मझधार में छोड़कर जा रहा हूं। पता है ये कायरों का काम है। बहुत कोशिश की खुद को संभालने की, पर शायद गुरु महाराज ने इतनी सांस दी थी। उमेश दोनों बच्चों के लिए मेरा सपना पूरा करना। संदीप भाई पूरे परिवार को संभाल लेना प्लीज। मैं खुद गुनाहगार हूं। आप सबका विष्णु।

दोनों सुसाइड नोट में खुद को गुनहगार बताने वाले एक अधिकारी की आत्महत्या पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? इसकी वजह है वह दबाव जिसका जिक्र एसपी को लिखे नोट में विश्नोई ने की है। अब उन पर दबाव किस तरह का था यह उन्होंने साफ नहीं किया है। यही नहीं फंदे पर लटके पाए जाने से एक दिन पहले विश्नोई ने एक परिचित के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें गंदे पॉलिटिक्स में फंसाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने की बात भी कही थी। यहीं से पूरे मामले में एथलीट से कांग्रेस की विधायक बनीं कृष्णा पुनिया पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुनिया इसके लिए भाजपा की ओछी राजनीति को जिम्मेदार बताती हैं। उन्होंने विश्नोई की कॉल डिटेल निकाल पूरे मामले की जांच की मांग की है। यह भी कहा जा रहा है कि विश्नोई अपने थाने के कुछ पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने से भी नाराज थे। ऐसा कथित तौर पर कृष्णा पुनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहकर करवाया था।

नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि राजनीतिक-आपराधिक गठजोड़ का साथ न देने की कीमत विष्णुदत्त विश्नोई को चुकानी पड़ी। राठौड़ ने कहा कि पुलिस के आला अधिकारी भी संवेदनहीन होकर इस हत्याकांड की सच्चाई पर पर्दा डालने में लगे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शव को 12 घंटों तक फंदे से लटकते हुए ही छोड़े रखा गया। राठौड़ ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार को भी टीवी पर विश्नोई की मौत की सूचना मिली। राठौड़ ने कहा कि सुसाइड नोट के 3 पन्ने के होने की बात कही जा रही थी लेकिन अंत में दो पन्ने ही बताए गए। विष्णुदत्त विश्नोई की लोकप्रियता का आलम ये था कि पूरे राजगढ़ में उनकी आत्महत्या के बाद गम का माहौल है। पुलिस विभाग के लोग सड़कों पर ड्यूटी के दौरान ही रोते हुए दिखे। अब पूरा राजगढ़ थाना ही तबादला मांग रहा है।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

खतरे में उद्धव सरकार?

महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर किए गए लॉकडाउन के बीच एकबार फिर से सियासी हलचल शुरू हो गई है। एक ओर जहां महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उनके आवास पर मुलाकात कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे के घर पर एक गुप्त बैठक हुई। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या महाराष्ट्र में महाविकास आघाडी सरकार खतरे में है? या फिर केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है? जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र में सत्ता का केंद्र बने मातोश्री (उद्धव ठाकरे के घर) पर, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच गुप्त बैठक हुई। यह बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि लंबे अंतराल के बाद एनसीपी सुप्रीमो मातोश्री पहुंचे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद 36 दिन तक चले सत्ता के संघर्ष के बीच एक बार भी शरद पवार मातोश्री नहीं गए, और इस वक्त में उनका मातोश्री जाना कई सवाल खड़े कर रहा है।

इससे पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को मिलने के लिए राजभवन बुलाया। उनके साथ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी थे। 20 मिनट तक की मुलाकात के बाद बाहर निकलकर प्रफुल्ल पटेल ने कहा, 'राज्यपाल के बुलावे पर हम यहां आए हैं। हमारे बीच कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई।' हालांकि, प्रफुल्ल पटेल का यह बयान लोगों के गले नहीं उतरा कि अगर राजनीतिक चर्चा नहीं करनी थी, तो फिर राज्यपाल ने शरद पवार को मिलने क्यों बुलाया था? इन सब घटनाक्रम के बीच शरद पवार ने बयान जारी कर कहा कि उद्धव सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस की मदद से सरकार स्थिर है। जो अटकलें लगाई जा रही हैं, वह बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि मैं राज्यपाल से मिलने जरूर गया था, लेकिन यह शिष्टाचार भेंट थी। तमाम विषयों पर उनसे बातचीत हुई। मुझसे राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अच्छा काम कर रहे हैं। उद्धव से मातोश्री से मिलने पर लग रहीं अटकलों पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति पर बातचीत के लिए उद्धव से मिलने गए थे। कोरोना को लेकर यह बैठक हुई। मालेगांव में कोरोना की स्थिति पर भी चर्चा हुई। बाला साहेब की यादें भी ताजा हुईं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि कोरोना का इलाज और ठाकरे सरकार को गिराने का डोज अब तक विरोधियों को नहीं मिला है, संशोधन जारी है। विरोधी खुद ही क्वारैंटाइन हो जाएं यही सही रहेगा। महाराष्ट्र को अस्थिर करने का प्रयास सफल नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में डेढ़ घंटे तक बातचीत की। अगर कोई सरकार की स्थिरता के बारे में खबरें फैला रहा है, तो इसे उनके पेट का दर्द माना जाना चाहिए। सरकार को कोई चिंता नहीं है।

सूत्रों के मुताबिक करीब 20 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल और अमित शाह के बीच एक बार मंत्रणा हो चुकी है। इसके बाद ही भाजपा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को टारगेट करना शुरू किया है। सरकार के खिलाफ राज्य भर में भाजपा का आंदोलन, भाजपा नेताओं का सोशल मीडिया पर शिवसेना के खिलाफ आक्रामक होना, देवेंद्र फडणवीस का सीधे उद्धव ठाकरे को टारगेट करना। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल का उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला बोलना और एनसीपी के खिलाफ मौन रहना किसी स्ट्रेटेजी का भाग हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में सरकार और राजभवन के बीच विभिन्न मुद्दों पर लगातार बढ़ते जा रहे टकराव के मद्देनजर यह सामान्य संकेत नहीं है। मुंबई और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि भाजपा जल्द से जल्द कुछ भी करके महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी चाहती है। फिर चाहे वह शिवसेना के साथ हो या शिवसेना के बगैर। दिल्ली के सूत्रों का यह भी कहना है कि महाराष्ट्र में भाजपा की सत्ता का रास्ता राजभवन से ही निकलेगा। इसीलिए भाजपा लगातार राज्य में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें राजभवन राजनीति के केंद्र में रहे।

भाजपा नेता नारायण राणे ने कहा, 'सरकार कुछ नहीं कर सकती। लोगों की जान नहीं बचा सकती है। सरकार विफल हो रही है। इस सरकार में कोरोना से सामना करने की क्षमता नहीं हैं। इसलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए।' राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के बाद राणे ने सेना बुलाने की भी बात कही है। राणे ने कहा, 'हमने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि लोगों की जान बचाने, उनको सही इलाज देने के लिए महानगरपालिका और राज्य सरकार के अस्पतालों को सेना के हवाले कर दिया जाए।' राणे ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे अनुभवहीन मुख्यमंत्री हैं जो पुलिस और प्रशासन को नहीं चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अस्पतालों की हालत खराब है।

● **मुंबई से बिन्दु माथुर**

कुछ तो पक रहा है

पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में दखल रखने वालों को यह लग रहा है कि राज्य की राजनीति में कुछ तो पक रहा है। राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार खासकर शिवसेना और राज्यपाल के बीच बढ़ते टकराव और राज्य में कोरोना वायरस के अनियंत्रित होते जाने की खबरों के बीच राष्ट्रपति शासन की चर्चा के चलते शरद पवार का राज्यपाल से मिलने जाना कई तरह की राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे रहा है। इसकी एक बड़ी वजह शरद पवार के साथ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का राजभवन जाना भी है। क्योंकि, प्रफुल्ल पटेल अपने गुजराती कनेक्शन की वजह से केंद्र की राजनीति में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के भी करीबी माने जाते हैं।

प्रियंका से किसको खतरा?

उत्तर प्रदेश की सीमा से प्रियंका गांधी की बसें तो लौट गईं, लेकिन राजनीति घुस कर रफ्तार भरने लगी है। ये भले लगता हो कि मजदूरों के नाम पर हुई बसों की राजनीति में प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है, लेकिन असलियत तो ये है कि सबसे ज्यादा घाटे में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बसपा नेता मायावती हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने बसों के मामले को बेवजह इतना तूल दे दिया? क्या ऐसा नहीं लगता कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव और मायावती को फिलहाल पीछे छोड़ दिया है? सबसे बड़ा सवाल तो एक ही है – प्रियंका गांधी की राजनीतिक घेरेबंदी में योगी आदित्यनाथ फंस कैसे जाते हैं?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शायद ही कभी अखिलेश यादव और मायावती के हाथ मिलाने से घबराहट में देखा गया हो। 2018 के उपचुनावों में जब सपा-बसपा ने गोरखपुर और फूलपुर में संयुक्त उम्मीदवार उतारे तो योगी आदित्यनाथ उसे टिप्पणी के लायक भी नहीं समझते रहे। भाजपा की हार के बाद कहे भी थे कि जरा हल्के में ले लिया गया और नतीजा उलटा हो गया। आम चुनाव में तो खैर बदला भी ले लिए और अखिलेश-मायावती के गठबंधन को एक खास दायरे को लांघने तक नहीं दिया और हाल ये हो गया कि गठबंधन ही टूट गया।

2019 के आम चुनाव में तो योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को भी सिर्फ एक सीट पर समेट दिया। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि राहुल गांधी को अमेठी से बोरिया बिस्तर समेटने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर धावा बोलती हैं अपने मन की करके ही लौटती हैं। जिन बातों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार के अफसर प्रियंका गांधी को पहले साफ मना कर देते हैं, बाद में वही काम कांग्रेस नेता के मन मुताबिक करने को मजबूर हो जाते हैं। सोनभद्र में स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने नरसंहार के पीड़ितों से मिलने से ही रोक दिया था और फिर मिलाने के लिए गाड़ी में बैठाकर उस गेस्ट हाउस तक ले गए जहां प्रियंका गांधी को हिरासत में रखा था। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शनों के दौरान लखनऊ पुलिस ने प्रियंका गांधी के सारे रास्ते रोकने की कोशिश की, लेकिन बाद में पुलिस एक्शन के शिकार लोगों के घरों में जाकर इमोशनल तस्वीरें लेने और ट्वीट करने की पूरी छूट दे दी। बिलकुल वही काम मजदूरों के लिए प्रियंका गांधी की भेजी गई बसों के साथ भी योगी सरकार ने किया है।

फर्ज कीजिए योगी सरकार ने बसों का मामला सीधे-सीधे खारिज कर दिया होता तो कौन-सा पहाड़ टूट जाता? जो राजनीतिक दांव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश को लेकर चलती हैं, उससे बड़ी चालें कांग्रेस नेतृत्व दिल्ली में चलता है। दिल्ली दंगों का केस ही देख लीजिए। पहले सोनिया गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कठघरे मे खड़ा करने की कोशिश की। उसके बाद राष्ट्रपति भवन जाकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से अमित शाह को बर्खास्त करने के लिए ज्ञापन दिलवाया और फिर मीडिया के सामने आकर बयान भी दिलवाया। तुरंत ही भाजपा के कुछ नेताओं ने मोर्चा संभाला और 1984 के दंगों की याद दिलाते ही गुब्बारा फूटकर हवा हो गया।

जबसे कोरोना संकट आया है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी हर रोज किसी न **किसी बहाने** मोदी सरकार पर हमला बोलते हैं, लेकिन एक-दो भाजपा नेता सामने आते हैं और बड़े आराम से न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कई बार तो संबित पात्रा जैसे प्रवक्ताओं के स्तर पर ही मामला शांत हो जाता है। तो क्या उप्र में इतनी हलचल योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक अपरिपक्वता की वजह से मच जाती है? ये सब देखकर तो ऐसा ही लगता है कि योगी आदित्यनाथ अगर प्रियंका गांधी की बसें भेजने की पेशकश को नजरअंदाज कर दिए होते तो ज्यादा सुखी रहते। ये भी तो हो सकता था कि सरकार चुप रहती और कांग्रेस के राजनीतिक हमले का जवाब भाजपा नेता लखनऊ में दे देते और योगी आदित्यनाथ पर आंच तक न पहुंच पाती। अब तो हालत ये है कि ट्विटर पर भी लोग बस पॉलिटिक्स का भरपूर मजा लूट रहे हैं। कई लोग तो कोरोना संकट में सरकारी इंतजामों तक से जोड़ दे रहे हैं।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

अखिलेश और मायावती तो हाथ मलते रह गए

उप्र में सत्ताधारी भाजपा के बाद सबसे बड़े विपक्षी दल के तौर पर अखिलेश यादव की सपा है और उसके बाद बसपा। अपना दल के बाद पांचवें पायदान पर रहने वाली कांग्रेस की हैसियत तो इतनी भर बची है कि लोकसभा में रायबरेली से सोनिया गांधी की सीट और विधानसभा में कुल जमा 7 विधायक हैं। फिर ऐसा क्या है कि प्रियंका गांधी की राजनीति का योगी आदित्यनाथ पर असर होता है? यही यक्ष प्रश्न मायावती और अखिलेश यादव के सामने भी होगा ही। जिस कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव 2017 के चुनावों में गठबंधन के तहत एक-एक सीट के लिए रुला डाले थे उसे उप्र में भाजपा इतना महत्व क्यों देने लगती है? ठीक वैसे ही 2019 में जब सपा-बसपा गठबंधन बना मायावती ने कांग्रेस को आसपास फटकने तक नहीं दिया था, लेकिन वक्त की नजाकत देखिए कि सिर्फ एक या दो बार नहीं बार-बार प्रियंका गांधी बाजी मार ले जा रही हैं और मायावती हों या अखिलेश यादव गुबार देखते रह जाते हैं। देखा जाए तो उन्नाव रेप पीड़ित की मौत के वक्त प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और मायावती तीनों फील्ड में नजर आए थे। वरना, ज्यादातर वक्त सभी ट्विटर से ही आजकल काम चला रहे हैं। प्रियंका गांधी और अखिलेश-मायावती में एक फर्क जरूर नजर आता है, प्रियंका गांधी हर मौके पर फील्ड में उतर जा रही हैं, जबकि अखिलेश यादव और मायावती या तो ट्विटर पर बयान जारी कर रहे हैं या ज्यादा से ज्यादा मीडिया के सामने आकर। जाहिर है फील्ड का ज्यादा असर होता है इसलिए फायदा भी वैसा ही मिलता है।

बेफिक्री का राज

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस समय एक चिंतित व्यक्ति होना चाहिए। बिहार के लाखों या संभवत: करोड़ों मजदूर और छोटे व्यवसायी देश के विभिन्न इलाकों में फंसे हुए हैं और बिहार लौटना चाहते हैं। ये लोग बिहार की अर्थव्यवस्था में भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य में प्रवासी मजदूरों द्वारा भेजी जाने वाली रकम अब कम हो सकती है या बंद हो सकती है। अन्य राज्यों में वे तकलीफ में हैं और रास्ते में भी तमाम तरह की तकलीफों से गुजर रहे हैं। उनमें से लौटने वाले कई लोग संक्रमण लेकर लौट रहे हैं और उनसे बिहार में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका है। नीतीश कुमार को चिंता होनी चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से बिहार देश के सबसे बदहाल राज्यों में है और ऐसे में अगर बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो ये राज्य के लिए बुरी खबर होगी। अभी जो स्थिति है, उसे संभाल पाने में बिहार का तंत्र खासकर चिकित्सा संरचना असफल साबित हो रही है। लेकिन एक राजनेता के तौर पर उनकी सबसे बड़ी चिंता ये होनी चाहिए कि ये सब तब हो रहा है जबकि बिहार में विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है। तय कार्यक्रमों में अगर कोविड-19 या किसी और घटनाक्रम ने व्यवधान नहीं डाला तो इस साल नवंबर महीना खत्म होने से पहले बिहार में नई विधानसभा का गठन हो चुका होगा यानी सितंबर या अक्टूबर महीने में चुनाव घोषित हो जाएंगे। लेकिन **बिहार में सत्ताधारी जेडीयू** के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी तरह की परेशानी या हड़बड़ी में नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसी कोई चिंता या तनाव जेडीयू या बिहार में उनके पार्टनर भाजपा और एलजेपी में भी नजर नहीं आ रही है। मानो कोरोनावायरस का बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं होने वाला हो।

कोरोना से निपटने में जैसी तत्परता केरल ने दिखाई, उसका अंश मात्र भी बिहार के संदर्भ में नजर नहीं आया। प्रति दस लाख लोगों की आबाद पर टेस्टिंग के मामले में बिहार देश के सबसे फिसड्डी राज्यों में है। बिहार में क्वारंटाइन सेंटर्स की बदहाली के बारे में मीडिया में कई खबरें आ चुकी हैं। बिहार लौटने के इच्छुक प्रवासियों को बिहार वापस लाने को लेकर भी बिहार सरकार ने तत्परता नहीं दिखाई। दरअसल शुरुआती दौर में तो बिहार ने इन मजदूरों को वापस लाने का विरोध यह कहकर किया था कि ऐसा करना सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। ये भी गौर करने की बात है कि सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों वाला राज्य बिहार है, लेकिन पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन झारखंड आती है क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे लेकर प्रो-एक्टिव होते हैं। हालांकि, इस संकट का आकार इतना बड़ा है कि सिविल सोसायटी संगठनों और एनजीओ या खासकर विपक्षी राजनीतिक दलों की राहत पहुंचाने की क्षमता बहुत सीमित है, इसके बावजूद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता लोगों को मदद पहुंचाने में शुरुआत से ही सक्रिय नजर आए। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का भी प्रयोग किया।

बिहार में लालू-विरोध अब भी मुद्दा है

लोग हमेशा किसी दल, नेता या राजनीति के पक्ष में वोट नहीं डालते। कई बार वे किसी दल या नेता को सत्ता में आने से रोकने के लिए भी वोट डालते हैं। नीतीश कुमार का सत्ता में आना और बने रहना सिर्फ इसलिए नहीं है कि वे सुशासन और विकास के तमाम नारों का इस्तेमाल करते हैं। बिहार नीतीश कुमार के 15 साल के निरंतर राज के बावजूद देश का सबसे पिछड़ा और लाचार राज्य है। नीतीश कुमार की मुख्य राजनीतिक ताकत ये है कि वे लालू यादव और उनके परिवार तथा यादव-मुसलमान गठबंधन को सत्ता में आने से रोकने में सफल रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में सामाजिक परिवर्तन (जिसे राजनीति विज्ञानी क्रिस्टोफ जेफ्रोले ने साइलेंट रिवोल्यूशन कहा था) की लहर को रोकने वाली शक्ति के प्रतीक हैं। उनकी ये ताकत जब तक बनी हुई है तब तक लालू विरोधी वोटर को इस बात की परवाह नहीं होगी कि नीतीश सरकार ने कोरोना संक्रमण के दौरान क्या किया और क्या नहीं किया। ये तबका तेजस्वी यादव की पार्टी या उनके गठबंधन को इसलिए वोट नहीं डाल देगा कि तेजस्वी यादव ने जनता की मदद करने की कोशिश की।

सवाल उठता है कि इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी के समय बिहार के सत्ताधारी दल इतने बेफिक्र कैसे हैं और वो भी तब जब चुनाव होने ही वाले हैं। दरअसल, चुनाव जीतने का तरीका बदल चुका है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चुनाव लड़ने और जीतने के नए तरीके का इजाद किया है, जो सत्ताधारी दल के पक्ष में है। जनधन खाता धारकों और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए योग्य लोगों के विशाल डाटा बेस के मौजूद होने के कारण सरकारों के लिए ये संभव हो गया है कि चुनाव से पहले हर खाताधारक को कुछ नकदी ट्रांसफर कर दी जाए। एनडीए ने बिहार में एक मजबूत गठबंधन बनाया है, जिसमें जेडीयू, भाजपा और एलजेपी हैं। जेडीयू-भाजपा का गठबंधन बिहार में लगातार चुनावी जीत हासिल कर रहा है और इसकी काट विपक्ष अभी तक निकाल नहीं पाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी बिहार में एक भी सीट नहीं जीत पाया। एनडीए सोच सकता है कि 2019 में उसे जिताने वाले लोग सिर्फ कोरोना संकट के कारण अपना राजनीतिक रुझान और वफादारी नहीं बदल लेंगे। एनडीए ने सामाजिक तौर पर सवर्ण जातियों, कुछ गैर-यादव पिछड़ी जातियों और दलितों के एक हिस्से (मुख्य रूप से पासवान) का सामाजिक समीकरण बनाया है। इसके अलावा उसके पास नरेंद्र मोदी का चेहरा तो है ही, जिसकी चमक अभी फीकी नहीं पड़ी है।

एनडीए के नेता शायद ये सोच रहे हैं, और वे सही भी हो सकते हैं, कि बिहारी मजदूरों की ज्यादा नाराजगी उन राज्यों और उन रोजगारदाताओं से होगी, जिन्होंने इस संकट के दौरान उन्हें मंझधार में छोड़ दिया। इसके अलावा एनडीए, खासकर भाजपा लगातार तबलीगी जमात (इसे आप मुस्लिम पढ़ सकते है) का मामला उछालकर ये संदेश दे रही है कि अगर जमात वाले न होते, तो भारत में इतने केस नहीं होते न उन्हें इतनी तकलीफ होती। ये बात भाजपा की हिंदू-मुस्लिम द्वेत याना बायनरी की राजनीति में बिल्कुल फिट हो जाती है। देखना होगा कि भाजपा चुनाव तक इस मुद्दे को जिंदा रख पाती है या नहीं, या फिर वह इसी मिजाज का कोई और मुद्दा लेकर आती है।

● **विनोद बक्सरी**

नेपाल नाराज क्यों... ?

भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क का उद्घाटन किया था, जिसे लेकर नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई थी। अब नेपाल खुलकर भारत के खिलाफ बयानबाजी करने पर उतारू हो गया है। यही नहीं, भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर दावा करने वाले 'नए नक्शे' के जारी करने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भारत के खिलाफ आक्रामक बयान दिया है। उन्होंने संसद में दिए एक भाषण में कहा कि 'भारतीय वायरस' चीनी और इतालवी वायरस की तुलना में अधिक घातक लगता है। ओली ने नेपाल में कोरोना वायरस के प्रसार के लिए भारत को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत से आ रहे हैं, वे देश में वायरस फैला रहे हैं। भारत से आए लोगों में इटली और चीन से लौटने वालों के मुकाबले कोरोना के गंभीर संक्रमण मिले हैं। जिस तरह नेपाल अपने बोल बोल रहा है, उससे इस मामले में चीन की भूमिका पर्दे के पीछे से स्पष्ट नजर आ रही है।

इससे पहले नेपाल की सरकार ने देश के नए राजनीतिक नक्शे को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। इस नए नक्शे में भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को भी शामिल किया गया है। धमकाने वाले शब्दों में केपी ओली ने कहा कि वह एक इंच जमीन भारत को नहीं देंगे। वहीं सरकार के एक मंत्री ने कहा कि सरकार भारत की तरफ से हो रहे अतिक्रमण को लंबे वक्त से बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन फिर भारतीय रक्षा मंत्री ने लिपुलेख में नई सड़क का उद्घाटन कर दिया। भारत हमारी वार्ता की मांग को गंभीरता से नहीं ले रहा है। इससे पहले कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को लेकर भारत और नेपाल के बीच काफी समय से सीमा विवाद जारी है जो अब पहले से तेज हो गया है। गत दिनों पहले ही भारत ने लिपुलेख इलाके में सीमा सड़क का उद्घाटन किया था जिस पर नेपाल ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। जबकि 6 महीने पहले ही भारत ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था जिसमें कि लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को भारत का हिस्सा बताया गया था। इधर, नेपाल भी लंबे समय से इन इलाकों पर दावा जताता रहा है। नेपाल का कहना है लिपुलेख उसका इलाका है जबकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसने अपने इलाके में सड़क बनाई है।

नेपाल की आपत्ति पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पिछले दिनों कहा था, 'हाल ही में पिथौरागढ़ जिले में जिस सड़क का उद्घाटन हुआ है, वो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में पड़ता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री इसी सड़क से जाते हैं।' वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री ने संसद में कहा, 'लिपुलेख मुद्दे को सुलझाने के लिए हमारी सरकार के प्रतिनिधि चीन से बात कर रहे हैं। चीन ने कहा है कि लिपुलेख से मानसरोवर तक की सड़क भारत-चीन के बीच ट्रेड और पर्यटन रूट के लिए है और इससे लिपुलेख के ट्राई-जंक्शन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा।'

दूसरी ओर, पिछले हफ्ते को भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड एनलिसिस की ओर से आयोजित प्रोग्राम में कहा था कि भारत-नेपाल सीमा विवाद में कोई तीसरी ताकत शामिल है। सेना प्रमुख ने अपने बयान में सीधे और स्पष्ट तौर पर यहां चीन का संकेत किया है। भारत द्वारा लिपुलेख-धारचुला मार्ग तैयार किए जाने पर नेपाल द्वारा आपत्ति किए जाने के सवाल पर जनरल नरवणे ने कहा कि यह मानने के कई कारण हैं कि उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे तक भारत के सड़क बिछाने पर नेपाल किसी और के कहने पर आपत्ति जता रहा है। इस मुद्दे पर पड़ोसी देश की प्रतिक्रिया हैरान करने वाली थी। नरवणे ने यह भी कहा कि चीनी सेना के साथ हाल की तनातनी पर भारतीय सेना सिलसिलेवार तरीके से निपट रही है।

दरअसल, सुगौली संधि के आधार पर नेपाल कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर अपना दावा पेश करता है। नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच 1816 में सुगौली की संधि हुई थी, जिसके तहत दोनों के बीच महाकाली नदी को सीमारेखा माना गया था। विश्लेषकों का कहना है कि भारत-नेपाल सीमा विवाद महाकाली नदी की उत्पत्ति को लेकर ही है। नेपाल का कहना है कि महाकाली नदी लिपुलेख के नजदीक लिम्पियाधुरा से निकलती है और दक्षिण-पश्चिम की तरफ बहती है, जबकि भारत कालपानी को नदी का उद्गमस्थल मानता है और दक्षिण और आंशिक रूप से पूर्व में बहाव मानता है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच विवाद है। इधर, अब तक चीन ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी थी लेकिन पहली बार उसने अपना मुंह इस पर खोला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शाओ लिजिआन से सवाल किया, 'भारत ने कालापानी इलाके में एक सड़क बनाई है और इस इलाके को लेकर नेपाल-भारत में विवाद है। नेपाल की सरकार ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है और कहा है कि भारत नेपाल की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। पिछले हफ्ते भारत के सेना प्रमुख ने मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड एनलिसिस की ओर से आयोजित प्रोग्राम में कहा था कि पूरे विवाद में कोई तीसरी ताकत शामिल है। आपका इस पर क्या कहना है?'

● **विशाल गर्ग**

नेपाल इतना उतावला क्यों?

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'कालापानी का मुद्दा भारत-नेपाल का द्विपक्षीय मुद्दा है। हमें उम्मीद है कि यह विवाद दोनों देश आपसी बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे और कोई भी पक्ष एकतरफा कार्रवाई करने से बचेगा ताकि मामला और जटिल ना हो। उधर कोरोना संकट के चलते भारत ने नेपाल सीमा विवाद पर वार्ता को भी टालने का आग्रह किया है। उधर नेपाल जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को वार्ता के जरिए सुलझाना चाहता है। इसके लिए नेपाल ने भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि को हाल में काठमांडू बुलाया था और इस संबंध में एक नोट भी दिया था। इस पर भारत ने कोरोना काल के चलते वार्ता को कुछ समय के लिए टालने की बात कही थी लेकिन नेपाल ने इसे खारिज कर दिया। अगले कुछ दिन भारत की प्रतिक्रिया न आने के बाद नेपाल ने अपना नया राजनीतिक मैप जारी किया है। अब नेपाल के इस कदम के बाद भारत की प्रतिक्रिया देखने लायक होगी।

चीन की हिमाकत

दुनियाभर को कोरोना जैसा भयानक संक्रमण देने वाला चीन तनिक भी बाज नहीं आ रहा है। वह अब भारत से टकराव के मूड में लग रहा है। उसकी सेना ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पैंगोंगत्सो झील और गालवान घाटी में अपने सैनिकों की संख्या और गतिविधियां बढ़ा दी है। पर अब भारत भी पूरी तरह तैयार है। चीन की तबीयत से क्लास लेने के लिए भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लद्दाख में 14 कोर के मुख्यालय लेह का दौरा किया और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बलों की सुरक्षा तैनाती की सेना के अफसरों से गहन चर्चा की। चीन के नेतृत्व को शायद गलतफहमी हो गई है कि उनका मुल्क अजेय है। वह अजेय और अति शक्तिशाली होता तो फिर वह हांगकांग में लंबे समय से चल रहे आंदोलन को दबा चुका होता। वह अजेय होता तो अब तक ताइवान को खा गया होता। चीन के इरादे शुरू से ही विस्तारवादी रहें है। यह ही उसकी विदेश नीति का मूल आधार है। पर इस बार उसका मुकाबला भारत से हो रहा है जो अब 1962 वाला भारत नहीं रह गया है।

बुद्ध, महावीर और गांधी का देश संकट की घड़ी में एक जुट होकर उससे लड़ेगा। हमें अंहिसा पसंद है, पर हमारे नायकों में कर्ण और अर्जुन भी हैं। भारत से टकराने का अर्थ है कि चीन को अपनी अर्थव्यवस्था को चौपट होने का निमंत्रण देना। भारत-चीन के बीच 100 अरब डॉलर का व्यापार होता है। इसमें चीन बड़े लाभ की स्थिति में है। वह भारत से जितना माल आयात करता है, उससे बहुत अधिक भारत को निर्यात करता है। उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो भारत उससे अपना आयात भारी मात्रा में घटा सकता है। वैसे भी भारत में चीन के खिलाफ जमीनी स्तर पर पूरा माहौल बन चुका है। औसत भारतीय तो चीन से 1962 से ही नफरत करता ही था अब कोरोना महामारी के बाद और ज्यादा करने लगा है।

बहरहाल, सेना प्रमुख का चीन से लगी सीमाओं का दौरा करना ही यह साफ संकेत है कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। सरहदों पर दोनों ओर के हजारों सैनिक एक-दूसरे के आमने-सामने जमे हुए हैं। चीन की तकलीफ तब शुरू हुई थी जब कुछ समय पहले हमारी फौजों ने सरहदों से लगते कुछ इलाको में आवश्यक सैनिक निर्माण करने शुरू किए। हम काम तो अपनी सीमा के अंदर ही कर रहे थे, पर इसका चीनी सैनिकों ने विरोध किया। चीन को इसलिए भी तकलीफ रहने लगी है, क्योंकि भारत अब चीन की नाजायज गतिविधियों और हरकतों को सहन नहीं करता। अब भारत का पहले की तरह से रक्षात्मक रवैया नहीं रहता। यही चीनी नेतृत्व को हैरान करता है।

इस बीच, उत्तरी सिक्किम में भी विगत 9 मई को भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी जिसमें कई चीनी सैनिक घायल हुए थे। दरअसल चीन को उसकी औकात हमने डोकलाम विवाद के समय सही ढंग से बता दी थी। तब हमारे वीर सैनिकों ने उसे बुरी तरह खदेड़ दिया था। इस तरह के आक्रामक भारत की चीन ने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। इसलिए डोकलाम में अपमान का बदला चीन किसी न किसी रूप में लेने की फिराक में रहता है। उसे समझ लेना चाहिए कि इस बार भी नतीजे डोकलाम वाले ही या उससे भी सख्त आएंगे। भारत सरकार ने भी साफ कर दिया है कि सीमा पर भारतीय सैनिक जो भी कर रहे हैं वे अपने इलाके में कर रहे हैं। उस पर किसी को आपत्ति करने का कोई अधिकार ही नहीं है। अब वक्त का तकाजा है कि भारत चीन से अपने अक्साई चीन पर किए कब्जे के 86,000 किलोमीटर क्षेत्र को छुड़वाए।

चीन और भारत के बीच एक लंबी सीमा है। यह सीमा हिमालय पर्वतों से लगी हुई है जो म्यांमार तथा पाकिस्तान तक फैली है। इस सीमा पर चीन बार-बार अतिक्रमण करने की चेष्टा करता रहता है। हालांकि उसे हमारे वीर जवान कसकर कूटते भी हैं। बहरहाल, भारत-चीन के बीच ताजा विवाद के आलोक में ब्रिक्स को लाना जरूरी है। यह पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें भारत-चीन के साथ-साथ ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका भी हैं। ब्रिक्स देशों में विश्वभर की 43 फीसदी आबादी रहती है, और विश्व का सकल घरेलू उत्पाद का 30 फीसदी इन्हीं पांच देशों में है और विश्व व्यापार में इन देशों की 17 फीसदी हिस्सेदारी है। कहने को तो सभी ब्रिक्स देश आपस में व्यापार, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कृषि, संचार, श्रम आदि मसलों पर परस्पर सहयोग का वादा करते हैं। पर लगता है कि इनके वादे कागजों पर ही होते हैं। ये सिर्फ शिखर सम्मेलन भर कर लेते हैं। जब ब्रिक्स समूह देशों का कोई नालायक साथी गड़बड़ करता है, तो सब बाकी सदस्य देश चुप हो जाते हैं।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

भारत को अपनी भावी भूमिका के बारे में सोचना होगा

भारत के कूटनीतिज्ञों को चीन से अपने भावी संबंधों के साथ-साथ ब्रिक्स की भूमिका पर भी देर-सवेर विचार करना ही होगा। क्या इस समय चीन को रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कसा नहीं जाना चाहिए? क्या ब्रिक्स देशों के सदस्यों को अपने इन दो सदस्य देशों के विवाद को सुलझाने की दिशा में आगे नहीं आना चाहिए? पर हैरानी यह होती है कि फिलहाल किसी भी देश ने चीन को समझाया या कसा नहीं है। तो फिर इस तरह के निकम्मे तथा अकर्मण्य मंच में रहने का लाभ ही क्या है? इस बीच, भारत को नेपाल से अपने संबंधों को लेकर भी ध्यान से कदम उठाने होंगे। नेपाल से भारत के रोटी-बेटी के रिश्ते से भी ऊपर खून का रिश्ता है। अनगिनत गोरखा सिपाहियों ने भारत के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। दोनों देशों के बीच सीमा का विवाद बातचीत से शांतिपूर्वक हल होना चाहिए। कालापनी इलाके के अलावा एक और भी इलाका दोनों देशों के बीच में विवादास्पद है - सुस्ता वाला इलाका जो कि गोरखपुर से लगता है। उसकी देखरेख सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) करती है। भारत को कूटनीति से ही काम लेना पड़ेगा। हम नेपाल को चीन या पाकिस्तान की श्रेणी में रखने की भूल भी नहीं कर सकते।

महिला हिंसा का गढ़ परिवार

हर साल 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। परिवार! जिसका महिमामंडन सर्वव्यापी है। परिवार नाम की संस्था को हमारे यहां सबसे आदर की नजर से देखा जाता है। परिवार को हर चीज से ऊपर माना जाता है। आज विश्व परिवार दिवस पर परिवार के उस पहलू पर चर्चा करते हैं जिसे आमतौर पर हम अनदेखा करते हैं और सच्चाई से आंख मूंद लेते हैं। परिवार के महिमामंडन में सबसे महत्वपूर्ण होती है भावनात्मक चाशनी। हम इस चाशनी में इतना डूबे रहते हैं कि कभी सिक्के का दूसरा पहलू देख ही नहीं पाते। परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे और सवाल हैं जिन पर सोचना बहुत जरूरी है। जिस घर-परिवार में सबसे ज्यादा महिलाएं खटती हैं उनके नजरिए से कभी परिवार को देखा ही नहीं जाता। परिवार के वैचारिक पहलुओं पर एक बार के लिए यहां चर्चा नहीं करते हैं बल्कि इसे स्याह-सफेद तरीके से कानून और आंकड़ों के जरिए समझते हैं।

महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानूनों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं सती कानून से जिसे सती प्रिवेंशन एक्ट कहा जाता है जो 1987 में लागू हुआ था। परिवार इस कानून के दायरे में आता है। एक समय औरत को पति के साथ जिंदा जला देने वाले जघन्य अपराध में परिवार की हिस्सेदारी थी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम-1961, दहेज के अपराध में 100 फीसदी परिवार शरीक है। वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों की भागेदारी रहती है और इनकी भूमिकाएं बदलती रहती हैं। कानून बनने के बावजूद दहेज भी चल रहा है और दहेज हत्याएं भी चल रही हैं। वर्ष 2018 की एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार दहेज हत्या के 7277 मामले दर्ज हुए हैं। यानी हर रोज 20 लड़कियों को दहेज के लिए मार दिया जाता है। ये संख्या वर्ष 2017 में 7166 थी। यानी अपराध की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम-1994, जिसे भ्रूण हत्या को रोकने के अमल में लाया गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात 919 है। भ्रूण हत्या जैसे अपराध का कार्यस्थल परिवार ही है और निजी जन इसमें शामिल हैं। अगर हम परिवार को बालिकाओं का वध-स्थल कहें तो क्या गलत कहेंगे। क्या हम इस अपराध के लिए परिवार को बरी कर सकते हैं? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005, ये कानून भी परिवार और हमारे सबसे करीबियों पर लागू होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार पति और नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के एक लाख चार हजार एक सौ पैंसठ (1,04,165) मामले दर्ज हुए हैं। यानी हर रोज 285, यानी हर घंटे 11 महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। ये अपराध भी परिवार और घर की चार दीवारी के अंदर अपने करीबियों द्वारा अंजाम दिया जाता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 31 प्रतिशत महिलाएं अपने पति से हिंसा शिकार होती हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006, जिस कानून को सबसे पहले 1929 में पारित किया गया था। यूनिसेफ के अनुसार भारत में हर साल साढ़े दस लाख से ज्यादा लड़कियों का बाल विवाह कर दिया जाता है। यकीनन इसमें गरीबी की वजह से कुछ मजबूरियां भी होंगी लेकिन ये भयानक है। लड़कियों को बचपन में सेक्स गुलाम बना देना और उस समय में बच्चा पैदा करने के लिए भेज देना जब वो खुद बच्ची है, इसे भयानक नहीं तो और क्या कहेंगे। इस अपराध में परिवार और करीबी शामिल हैं।

ऊपर दिए गए आंकड़े उन अपराधों से संबंधित हैं जिनको अपराध की तरह से कानूनी मान्यता मिली है। अभी बहुत सारे ऐसे आपराधिक व्यवहार हैं जो परिवारों में प्रचलित हैं और उन्हें अपराध की तरह नहीं देखा जाता। बहुत सारे जघन्य अपराधों के लिए भी अलग से कोई कानून नहीं है। उदाहरण के लिए इज्जत के नाम पर होने वाली हत्याओं के लिए अलग से कोई कानून नहीं है। जबकि लंबे समय से महिला आंदोलन और सिविल सोसाइटी इसके लिए मांग कर रही है। वैवाहिक बलात्कार पर कोई कानून नहीं है। बड़े पैमाने पर महिलाएं इसकी शिकार हैं। लेकिन इसे अपराध की तरह देखा ही नहीं जाता। शादी के साथ ही औरत के शरीर पर एकमुश्त और कदीमी अधिकार पुरुष को मिल जाता है। अजीब बात ये है कि इसे हमारा समाज स्वाभाविक और सामान्य मानता है। इसके अलावा अन्य बलात्कार और यौन उत्पीड़न की वारदात में भी बड़ी संख्या में परिजन और परिचितों के शामिल होने के आंकड़े सामने आते हैं।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

मात्र 38 प्रतिशत महिलाओं के नाम पर ही जमीन का पट्टा

अब परिवार में महिलाओं के श्रम और संसाधनों पर अधिकार एवं निर्णयों में भागेदारी की स्थिति देखिए। मात्र 38 प्रतिशत महिलाओं के नाम पर ही जमीन का पट्टा है। इसमें सिर्फ महिलाओं को ही मिलने वाली योजना और संयुक्त पट्टा भी शामिल है। मात्र 45 प्रतिशत महिलाओं के पास मोबाइल फोन है। अगर बिल्कुल बेसिक हाइजिन की बात करें तो 57 प्रतिशत महिलाओं को आज भी माहवारी के दौरान बेसिक हाइजिन सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये आंकड़ें चीख-चीखकर एक कहानी को बता रहे हैं। महिलाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कानून हैं और जो जघन्य अपराध हैं परिवार उसकी कार्यस्थली है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध श्रेणी के अंतर्गत दर्ज हुए कुल अपराधों में से 31 प्रतिशत अपराध पति और करीबियों के द्वारा किए गए हैं। क्या हमें परिवार को अपराध मुक्त करने की सख्त जरूरत नहीं है? क्या हम ये नहीं देखना चाहते? हमें ये समझना होगा कि परिवार नाम की संस्था में सुधार की सख्त आवश्यकता है। हमें इसे आलोचनात्मक नजरिए से देखना होगा और परिवार के जनतांत्रीकरण के लिए और इसे अपराध मुक्त करने के प्रयास तेज करने होंगे।

जीवन का सत्य है भगवत गीता

हिन्दू धर्म में भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है। इसके श्लोक जीवन को जीने की दिशा दिखाते हैं। भगवत गीता के श्लोक हमारे जीवन जीने की राह आसान कर देंगे। भगवत गीता के श्लोक जीवन का सत्य बताते हैं। श्रीमद्भगवत गीता के उपदेशों में मानव के कल्याण का रहस्य छिपा हुआ है। धर्मयुद्ध में जब अर्जुन धर्मसंकट में फंस गए तब भगवान ने उन्हें गीता का रहस्य समझाया। आज भी गीता के उपदेश लोकप्रिय हैं। करोड़ों लोग इन उपदेशों को आत्मसात करके जीवन का आंनद ले रहे हैं। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को जीवन में उतार लेता है उसे सही मायने में जीने की कला आ जाती है।

जीवन में कुछ भी स्थाई नहीं है- रणभूमि में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन! कुछ भी स्थाई नहीं होता है। जो आया है वह जाएगा। जिसने जन्म लिया है उसे मरना ही पड़ेगा। ऐसे में मोह व्यर्थ है। जो व्यक्ति इस मोह में घिर जाता है वह सिर्फ अपनी परेशानियों को ही बढ़ाता है। ये संसार, शरीर कुछ भी स्थाई नहीं है। मनुष्य का जीवन जब तक है तब तक श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए। लोगों के हित में कार्य करने चाहिए। आपके द्वारा अच्छे कार्यों की छाप रह जाती है बाकी सब मिट जाता है। इसलिए जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियां उदाहरण लें। ये दुनिया इसी तरह से चलती है और आगे भी चलती रहेगी। व्यक्ति को सदा ही अच्छे कार्यों की तरफ अग्रसर रहना चाहिए।

जीवन में अच्छी चीजों का हिस्सा बनना चाहिए- व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ घटित होता रहता है। लेकिन ज्ञान और जागरूकता के अभाव में यह निर्णय नहीं ले पाता है कि उसे किन चीजों का हिस्सा बनना चाहिए। सफल व्यक्ति हर चीज का ज्ञान रखता है फिर वह बुरी हो या अच्छी। जानकारी हर चीज की होनी चाहिए। लेकिन अच्छी चीजों का हिस्सा बनना चाहिए और बुरी चीजों का नहीं। लेकिन बुरी चीजें व्यक्ति को अधिक प्रभावित करती हैं। ऐसे में व्यक्ति अच्छी चीजों को त्यागकर बुरी चीजों को अपना लेता है और यहीं से उसके पतन का आरंभ होता है।

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः।
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः।।

यानी शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म नहीं करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन के माध्यम से मनुष्यों को समझाते हैं कि हर मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए जैसे- विद्यार्थी का धर्म है विद्या प्राप्त करना, सैनिक का कर्म है देश की रक्षा करना। जो लोग कर्म नहीं करते, उनसे श्रेष्ठ वे लोग होते हैं जो अपने धर्म के अनुसार कर्म करते रहते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए तो शरीर का पालन-पोषण करना भी संभव नहीं है। जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य तय है, उसे वो पूरा करना चाहिए।

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।।

यानी श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति भी ऐसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति जिस कर्म को करता है, उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने बताया है कि श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद व गरिमा के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि वह जिस तरह का व्यवहार करेगा, सामान्य व्यक्ति भी उस की नकल करेगा। जो काम श्रेष्ठ पुरुष करेगा, सामान्य व्यक्ति उसी को अपना आदर्श मानेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी संस्थान में उच्च अधिकार पूरी मेहनत और निष्ठा से काम करते हैं तो वहां के दूसरे कर्मचारी भी उन्हीं की तरह काम करेंगे, लेकिन अगर उच्च अधिकारी काम नहीं करेंगे तो कर्मचारी उनसे भी ज्यादा आलसी हो जाएंगे।

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्म संगिनाम्।
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्।।

यानी ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करे। किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही कराए। यह प्रतिस्पर्धा का दौर है, यहां सब आगे निकलना चाहते है। ऐसे में संस्थानों में यह होता है कि कुछ चतुर लोग अपना काम तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन अपने साथ के मनुष्य को उसी काम को टालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या फिर काम के प्रति उसके मन में लापरवाही का भाव भर देते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य वही होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। उसी मनुष्य का भविष्य सबसे ज्यादा उज्ज्वल भी होता है।

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।
म वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः।।

यानी जो मनुष्य जिस प्रकार से मेरी भक्ति करता है। यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुसार मैं उसे फल देता हूं। सभी लोग हर प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान श्रीकृष्ण बता रहे हैं कि संसार में जो व्यक्ति जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करता है, दूसरे भी उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो लोग भगवान का स्मरण मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो किसी अन्य इच्छा से भगवान का स्मरण करते हैं, उनकी वह इच्छा भी भगवान की कृपा से पूरी हो जाती है। कंस ने सदैव भगवान को मृत्यु के रूप में स्मरण किया। इसलिए भगवान ने उसे मृत्यु प्रदान की। हमें परमात्मा को वैसे ही याद करना चाहिए, जिस रूप में हम उसे पाना चाहते हैं।

● ओम

झूठे रिश्ते

देर शाम तक मौसम रौद्ररूप दिखाता रहा। ओलों भरी बरसात ने मई के महीने को जनवरी जैसा ठंडा बना दिया था। मौसम के इस बदलाव को रामेश्वर सहन नहीं कर पाए। रात बारह-एक बजे के बीच उनकी तबियत एकदम से बिगड़ गई। सर्दी-जुकाम ने उनके गले को बंद कर दिया। उन्हें घुटन सी महसूस हुई तो अपनी पत्नी को नींद से जगाकर सारा हाल बता दिया।

पत्नी भागी-भागी गई और बड़े बेटे के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। बड़ी मुश्किल से बेटा जागकर बाहर आया।

'क्या हुआ मां?' उवासी भरता हुआ बोला।

रामेश्वर की पत्नी ने सारा घटनाक्रम बताया तो बेटे ने एकदम से अपने सिरपर दोनों हाथ मारे और बोला -'ये लक्षण तो कोरोना के हैं।'

कोरोना का नाम सुनते ही सारे घर में हलचल सी मच गई। एक भयंकर डर ने सभी के सोचने-समझने की क्षमता को शून्य कर दिया। आनन-फानन में रामेश्वर के कमरे को बाहर से ताला लगा कर बंद कर दिया गया।

बेचारे रामेश्वर सुबह तक खांसते-हांफते हुए किसी तरह जिंदा बने रहे। सुबह तड़के सरकारी एम्बुलेंस आई और उन्हें ले गई। पूरा परिवार दूर से ही उन्हें जाता देखता रहा। रामेश्वरजी को लग रहा था कि वे हॉस्पिटल नहीं यमपुरी को जा रहे हैं। कुछ दिन बाद पता चला कि रामेश्वर को कोरोना नहीं हुआ था, क्योंकि उनकी हर रिपोर्ट निगेटिव आई थी। मौसम के बदलाव की वजह से सामान्य खांसी-जुकाम ने उनके शरीर में कोरोना वायरस संक्रमण जैसे लक्षण पैदा कर दिए थे।

रामेश्वर के घर वालों को उनके पूर्ण स्वस्थ होने का समाचार जैसे ही मिला। बेटा-बहू, पत्नी सब उन्हें लेने हॉस्पिटल पहुंच गए। पर यह क्या रामेश्वर ने घर जाने से स्पष्ट मना कर दिया। वे शहर के वृद्धाश्रम में जाने का फैसला पहले ही कर चुके थे, क्योंकि उस रात उन्हें झूठे रिश्तों की असलियत पता चल चुकी थी।

रामेश्वर की घरवाली दूर खड़ी मुंह में साड़ी का एक कोना दबाए रो रही थी, तो दूसरी ओर खड़े बेटा-बहू रामेश्वर को मिलने वाली तीस हजार प्रतिमाह की पेंशन के मातम में फूट-फूटकर रो रहे थे, और रामेश्वरजी मुस्कराते हुए वृद्धाश्रम की गाड़ी में बैठकर चले गए।

— मुकेश कुमार ऋषि वर्मा

ताकत का आभास

बंधी बुहारी से हो हमको,
शक्ति भरा अहसास।
मिलकर रहते वे ही करते,
ताकत का आभास।।
सबने मिलकर ही सागर पर,
किया सेतु निर्माण।
ऐसे ही संदेश बताते,
हमको वेद पुराण।।
रहते जो संयुक्त रूप से,
भरे आत्मविश्वास।
मिलकर रहते वे ही करते,
ताकत का आभास।।
सदा आत्मबल से ही मानव,
पार करें मझधार।
बने सदा सामर्थ्यवान ही,
दलबल का सरदार।।
भरा पड़ा है अखिल विश्व में,
इसका तो इतिहास।
मिलकर रहते वे ही करते,
ताकत का आभास।।
सरल नीर ही सदा तोड़ता,
पत्थर तीव्र बहाव।
उसे नहीं कमजोर मानिए,
मित्रों सरल स्वभाव।।
क्षमा वही करता निर्बल को,
जज्बा जिसके पास।
मिलकर रहते वे ही करते,
ताकत का आभास।।

— लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला

आत्मनिर्भर

बड़े गांव के बड़े मुखिया साहब वर्षों से अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, घर-द्वार सब भंडार भरे थे, गांव के सभी किसान, नौकरपेशा, मजदूर किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी।

अचानक गांव में बड़ा भारी संकट आ गया। दूसरे गांव में से पूरे गांव में एक बीमारी फैल जाती है, जिसमें कई बच्चे, बूढ़े अधमरे हो जाते हैं, बहुत लोग मर जाते हैं। इस भीषण संकट में रोज किसी न किसी का शव उठाना पड़ता है। चैत की खड़ी फसल खेत में ही सूखकर बिखर गई। कुछ ही दिनों में खाने की समस्या होने लगी। लगातार गिरते मरते ग्रामीण एक-दूसरे के आंसू देखकर रोते जा रहे हैं। सूखी लकड़ियों का टोटा होने लगा। बचे-खुचे हरे पेड़ भी खत्म हो गए। एक दिन अचानक गांव के मुखिया प्रकट होते हैं और अपनी चौपाल पर सबको बुलाकर कहते हैं।

मेरे प्यारे गांव वालों, मुझे पता है इस बीमारी ने सबको रुलाया है, कई परिवारों ने अपने स्वजनों को खोया है।

अब आप चिंता मत करो, हम आने वाली बरसात में नहर से अपने गांव तक पानी लाएंगे। उच्च कोटि के अनाज के बीज लेकर आएंगे। हम आने वाले दिनों में एक फैक्ट्री लगाएंगे, जिसमें गांव के जवान लड़के नौकरी करेंगे। किसी को अब दूसरे के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। हमारी बैंकों में जो धन जमा है, उसका दस प्रतिशत हम उन सभी को बांटेंगे, जो गरीब हैं। सभी अपने घरों में उन वस्तुओं को बनाएंगे जो शहरों से आती हैं। हम अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाएंगे।

तभी एक किसान ने खड़े होकर अपने गमछे से आंसू पौंछते हुए पूछा, चौधरी साहब ये बता दो, गांव में जो लाशें रखी हैं जिन्हें जलाने के लिए लकड़ी नहीं हैं, जो लोग बीमारी से, भूख से मर रहे हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? इतना सुनते ही चौधरी साहब अपने पालतू पहलवानों को इशारा करते हैं, तभी चार पहलवान खड़े हुए और उसे उठाकर ले गए और गांव के बाहर एक अंधे कुए में फेंक आए।

- डॉ. शशिवल्लभ शर्मा

विदेशी कोच क्यों नहीं टिकते?

बीते महीने भारतीय बैडमिंटन कोच फ्लैंडी लिम्पल ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बीते तीन सालों में अनुबंध पूरा होने से पहले अपना पद छोड़ने वाले वे चौथे कोच हैं। इंडोनिशिया के फ्लैंडी लिम्पल को बीते साल मार्च में भारतीय बैडमिंटन की डबल्स टीम का विशेष कोच नियुक्त किया गया था। उन्हें भारतीय टीम को टोक्यो ओलंपिक तक अपनी सेवाएं देनी थीं। फ्लैंडी लिम्पल से पहले बीते तीन सालों में जो विदेशी कोच अनुबंध पूरा किए बिना चले गए, उन्होंने भी व्यक्तिगत कारणों का ही हवाला दिया था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कुछ ही समय बाद ये सभी दूसरी टीमों से जुड़ गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वास्तव में इन लोगों के भारतीय टीम को छोड़ने की वजहें वही थीं, जो इन्होंने बताई थीं। और क्या फ्लैंडी लिम्पल ने भी व्यक्तिगत कारणों के चलते ही अपना पद छोड़ा है?

इंडोनेशियाई कोच मूलो हांड्यो को फरवरी 2017 में तीन साल के लिए भारतीय एकल पुरुष बैडमिंटन टीम का कोच नियुक्त किया गया था। इसी साल किदाम्बी श्रीकांत ने पांच सुपरसीरीज जीती थीं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके आलावा साईं प्रणीत ने सिंगापुर ओपन का खिताब अपने नाम किया था। इन दोनों की इस चमक के पीछे मूलो हांड्यो की ही मेहनत बताई गई थी। बैडमिंटन के महान खिलाड़ियों में से एक तौफीक हिदायत के मेंटर रह चुके हांड्यो को उनके कड़े ट्रेनिंग सेशन के लिए जाना जाता है। भारतीय एकल खिलाड़ियों के लिए उन्होंने ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम तैयार किया था, जिसमें लंबे-लंबे सेशन हुआ करते थे। श्रीकांत और साईं प्रणीत जैसे शीर्ष एकल खिलाड़ियों को ऐसी ट्रेनिंग की आदत डालने में समय जरूर लगा, लेकिन आदत पड़ने के बाद इनके खेल में गजब का बदलाव दिखाई दिया।

हांड्यो के आने के बाद भारतीय बैडमिंटन अपने रंग में दिखाई देने लगा था। भारतीय खिलाड़ी दुनियाभर में अपनी छाप छोड़ रहे थे। अचानक एक दिन मूलो हांड्यो के कोच पद छोड़ने की खबर आई। हांड्यो का कहना था कि वह अपने परिवार को और समय देना चाहते हैं। लेकिन, भारतीय टीम को छोड़ने के कुछ ही रोज बाद ही वे सिंगापुर के मुख्य कोच बन गए।

मलेशिया के टान किम हर भारतीय बैडमिंटन टीम को सबसे लंबे समय तक सेवाएं देने वाले कोचों में से एक थे। साल 2015 में जब उन्हें पांच साल के लिए भारतीय डबल्स बैडमिंटन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो उन्होंने टोक्यो ओलंपिक-2020 में भारत को मेडल दिलवाने का लक्ष्य रखा था। उन्होंने इसे लेकर काफी मेहनत भी की। डबल्स के खिलाड़ी चिराग शेट्टी और स्वास्तिक साईराज रंकीरेड्डी एक-दूसरे के साथ जोड़ी बनाने के इच्छुक नहीं थे। लेकिन कोच किम हर ने न केवल इन्हें साथ आने के लिए तैयार किया बल्कि इनके लिए एक रोडमैप भी तैयार किया। इसके बाद इस जोड़ी ने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता। यह जोड़ी अब तक दुनियाभर में कई बड़े खिताब अपने नाम कर चुकी है। चिराग शेट्टी और स्वास्तिक साईराज की जोड़ी इस समय शीर्ष 10 में आती है। किम हर के मार्गदर्शन में एन सिक्की रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा की महिला जोड़ी ने भी राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता। लेकिन, 2019 में जब फ्लैंडी लिम्पल भारतीय डबल्स टीम से जुड़े तो टिम हर ने भारतीय बैडमिंटन संघ से अपना अनुबंध साल 2024 तक करने की बात कही। भारतीय बैडमिंटन संघ इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इस घटना के कुछ रोज बाद ही टान किम हर ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए भारतीय टीम को छोड़ने की घोषणा कर दी। वे इसके तुरंत बाद जापान की राष्ट्रीय टीम से जुड़ गए।

बीते साल अप्रैल में ही किम जी ह्यून को भारतीय महिला टीम का कोच नियुक्त किया गया था। उन्हें भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल के साथ काम करना था। लेकिन साइना के इनकार के बाद उन्हें पीवी सिंधु का कोच नियुक्त किया गया। इसके बाद अगस्त 2019 में ह्यून का नाम तब सुर्खियों में आया, जब उनके मार्गदर्शन में पीवी सिंधु ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती। सिंधु ने इस जीत के बाद ह्यून की जमकर तारीफ की थी और उन्हें इसका श्रेय भी दिया था। लेकिन हैरानी तब हुई, जब सिंधु के विश्व चैंपियन बनने के एक महीने बाद ही ह्यून ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने पति की बीमारी को इस्तीफे का कारण बताया।

भारतीय बैडमिंटन संघ के साथ-साथ फ्लैंडी लिम्पल ने भी अनुबंध पूरा होने से पहले ही टीम छोड़ने की वजह पत्नी की बीमारी को बताया है। लेकिन, जाते-जाते फ्लैंडी लिम्पल ने जो कुछ बोला है उससे पता चलता है कि उनके जाने की वजह केवल यही नहीं है। बैडमिंटन के जानकार भी मानते हैं कि भारतीय बैडमिंटन जगत में डबल्स से ज्यादा सिंगल्स को तवज्जो दी जाती है। इसके चलते न केवल डबल्स के कोच, बल्कि खिलाड़ी भी खुद को दरकिनार किया हुआ महसूस करते हैं।

हालांकि, इंडोनेशियाई कोच के भारतीय टीम को छोड़ने की एक वजह उनके और खिलाड़ियों के बीच सामंजस्य न बैठ पाने को भी बताया जाता है। बताते हैं कि लिम्पल के कड़े ट्रेनिंग शेड्यूल से कई वरिष्ठ खिलाड़ी खुश नहीं थे। बीते साल दिसंबर में लिम्पल के साक्षात्कार से भी इसका पता लगता है, इसमें उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों के रवैए पर सवाल उठाए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, 'डबल्स के मोर्चे पर भारतीय खिलाड़ियों का रवैया बहुत ही अजीब है। डबल्स में आपको व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि एक जोड़ी के तौर पर सोचना होता है। यहां तो खिलाड़ी कई बार मेरी ही बात नहीं मानते। सभी देशों में अलग-अलग कल्चर है, लेकिन एक कोच के रूप में मेरे अपने विचार हैं। जो चाहता हूं, उसे करना बहुत मुश्किल नहीं है।'

● आशीष नेमा

कहीं गोपीचंद वजह तो नहीं

भारतीय बैडमिंटन की समझ रखने वाले कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय बैडमिंटन में अभी भी फुलेला गोपीचंद का प्रभाव है। बैडमिंटन खेलने वाला हर खिलाड़ी यही चाहता है कि वह गोपीचंद के सुझावों पर गौर करे। ऐसे में जब विदेशी कोच भारतीय बैडमिंटन टीम में आता है तो उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर गोपीचंद का हस्तक्षेप। बताया जाता है कि भारत में विदेशी कोच इसी कारण नहीं टिक पाते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि विदेशी कोच यहां के खिलाड़ियों को अपने देश की टेक्निक के हिसाब से खेलने को कहते हैं लेकिन भारतीय खिलाड़ी अपने ही तरीके से खेलते हैं। ऐसे में विदेशी कोच यहां से रवाना होना ही उचित समझते हैं।

लॉकडाउन में जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनका सोचकर दुख होता है: फातिमा सना शेख

लॉकडाउन में दंगल फेम फातिमा सना शेख ने जिंदगी को अलग तरह से देखना सीख लिया है। उन्हें इस लॉकडाउन से उकताहट और घबराहट तो होती है, मगर वे जानती हैं कि ये जरूरी है। यहां वे लॉकडाउन, अपनी फिल्मों और दूसरे मुद्दों पर बात करती हैं।

लॉकडाउन के बारे में पूछे गए सवाल में फातिमा कहती हैं- लॉकडाउन के शुरू में बहुत उलझन होती थी, फिर धीरे-धीरे आदत पड़ गई, मगर अब बहुत उकता गई हूं। मैं रहती बेशक अकेले हूं, लेकिन इसी बिल्डिंग में मेरे मम्मी, पापा और भाई भी रहतें हैं। खुशकिस्मती से मैं अपने परिवार के साथ ही हूं। मुझे घर बैठें कोई तकलीफ नहीं हो रहीं है, क्योंकि मुझे इसकी आदत है। पर मुझे अपने परिवार और दोस्तों की चिंता होती है। जिन लोगों के पास घर या पैसा नहीं है, वह लोग अपना ख्याल कैसे रखेंगे। बस यही सोचकर दुख होता है।

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित होने के सवाल पर वे कहती हैं- जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार सक्रिय होकर कम कर रही है, उससे मुझे संतुष्टि है। अगर आप सोशल मीडिया पर बीएमसी या मुंबई पुलिस का पेज फॉलो करें, तो आप देख सकते हैं कि वह कितनी सारी चीजें कर रही है। वह गरीबों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिससे उनको राहत मिल सके। मैं अपने आपको खुशनसीब मानती हूं कि मैं महाराष्ट्र में रहती हूं। हमारी सरकार हर मामले में बहुत इन्वॉल्व है। दिन भर में मुझे कभी-कभार एंजायटी फील होती है। मैं कोशिश करती हूं कि ज्यादा निगेटिव चीजें न पढ़ूं। अगर आप ऐसी खबरें पढ़ते हैं, तो आप पूरा दिन वही सोचते रहते हैं। दुनिया में जो हो रहा है, वह बहुत दुख की बात है। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, बस घर पर रह सकती हूं। शायद कुछ पैसे फंड्स में दान कर सकती हूं, जिससे गरीबों की हेल्प हो सके।

पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए: विवेक

17 साल पहले अचानक एक दिन विवेक ओबेरॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें कहा कि सलमान खान ने फोन पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। यह वह दौर था जब कहा जा रहा था कि सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप हो गया है और विवेक कथित तौर पर ऐश्वर्या के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे। इस बात को गुजरे एक लंबा वक्त बीत गया लेकिन विवेक से अभी तक यह सवाल पूछा जाता है। कहा जाता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवेक और सलमान के रिश्ते बेहद खराब हो गए। सलमान पर यह भी आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने विवेक का बॉलीवुड में करियर बर्बाद कर दिया। एक इंटरव्यू में विवेक ने कहा, ये बहुत पुरानी बात है। मैं अपने निजी जीवन में उस मुकाम पर पहुंच चुका हूं कि ये सारी चीजें मुझे बहुत छोटी लगती हैं। इस नेगेटिव एपिसोड के बारे में बात करते हैं तो इससे किसी का भी फायदा नहीं होता है। शायद हमें पॉजिटिव घटनाओं के बारे में चर्चा करनी चाहिए। पुरानी बातों को भूलकर आगे निकल जाना चाहिए। मेरे दिल में किसी के लिए कोई गिले-शिकवे या गुस्सा नहीं हैं।

पाखी हेगड़े बोलीं- भोजपुरी से गई नहीं हूं, बॉलीवुड से फिर लौटूंगी

ऐक्ट्रेस पाखी हेगड़े का मानना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से जो उन्हें सम्मान और प्यार मिला है, उसे वह कभी नहीं भूल सकतीं। उन्होंने कहा कि अभी वह बॉलीवुड की तरफ जरूर जा रही हैं। पर, भोजपुरी से लगाव हमेशा रहेगा। इस दौरान हेगड़े ने यह भी दावा किया कि जल्द ही वह भोजपुरी में लौटेंगी और दमदार वापसी करेंगी।

एक हालिया इंटरव्यू के दौरान पाखी ने कहा, मैं भोजपुरी से गई कहां हूं। सभी लोग यही पूछ रहे हैं कि अब कब लौटेंगी। अरे मैं यहीं हूं। बॉलीवुड से कुछ प्रॉजेक्ट थे इसलिए अभी इसी पर ध्यान है। हालांकि लॉकडाउन में सबकुछ रुका हुआ है। पर, मैं भोजपुरी में लौटूंगी और उसी तरह से लौटूंगी जैसे पाखी ने शुरुआत की थी। मतलब दमदार। पाखी आगे कहती हैं, मेरे लिए हर इंडस्ट्री एक समान है। पर, भोजपुरी इनमें सबसे बढ़कर है। मैंने सबसे अधिक काम यहीं किया है। सबसे अधिक प्यार पाखी को भोजपुरी इंडस्ट्री में मिला है। फिर पाखी यहां से जाने का कैसे सोच सकती है। मैं यहीं हूं और हमेशा यहीं रहूंगी।

साहब जिस ऑफिस में जाते हैं, उस ऑफिस के कान खड़े हो जाते हैं। सभी दोपाए उनके सम्मान में सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते है। मानो राष्ट्रध्वज को सम्मान दे रहे हों। कोई भी विश्राम की मुद्रा में नहीं रह पाता। साहब की खुशी ही उनकी खुशी होती है। हर कोई इसी कोशिश में रहता है कि साहब को कैसे भी खुश रखा जाए।

साहब का बसंत

साहब टेंशन में हैं। साहब का टेंशन में होना कोई मामूली बात नहीं है। साहब कोई मामूली हस्ती नहीं हैं। अफसरों के अफसर हैं। देश सेवा की बलवती इच्छा के कारण इस पिछड़े इलाके में आए हैं। कुछ पेटियां देकर और खोखा भर कमाने का प्रण लेकर। उनके तार सीधे राजधानी से जुड़े हैं। रोब-दाब ऐसा कि डरकर मुर्दे भी खड़े हो जाएं। लोग उनके आदेश के लिए हाथ बांधे खड़े रहते हैं। उनके बैठे बिना कोई भी बैठने की जुर्रत नहीं कर पाता।

फिर उनके पालतू श्वान प्यारे टॉमी के कान खड़े क्यों नहीं हैं? कल तक तो अच्छे-भले खड़े हुआ करते थे। आज कान खड़े क्यों नहीं कर रहा है? साहब चिंतित हैं। उनकी फैमिली चिंतित है। प्रकृति में भले ही बसंत आ गया हो, किंतु उनके लिए तो पतझड़ छा गया है। साहब के सभी अधीनस्थ भी टेंशन में हैं। साहब टेंशन में हों तो उनके मातहत टेंशन फ्री कैसे रह सकते हैं? साहब के दुख ने सबके कान खड़े कर दिए। उनमें होड़ लगी है कि कौन टॉमी के कान पुन: खड़े करवाने में सफल होकर साहब की नजरों में चढ़ता है। सभी अपनी योग्यता सिद्ध करने में जुटे हैं। टॉमी ने उन्हें एक अवसर प्रदान किया है। सभी एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। सभी साहब की गुड बुक में आना चाहते हैं।

साहब जिस ऑफिस में जाते हैं, उस ऑफिस के कान खड़े हो जाते हैं। सभी दोपाए उनके सम्मान में सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते है। मानो राष्ट्रध्वज को सम्मान दे रहे हों। कोई भी विश्राम की मुद्रा में नहीं रह पाता। साहब की खुशी ही उनकी खुशी होती है। साहब को जो मुद्रा पसंद हो, वे उसी मुद्रा को धारण कर लेते हैं और यह तुच्छ श्वान साहब की खुशी के लिए अपने कान भी खड़े नहीं कर सकता। धिक्कार है।

कोई दोपाया होता तो साहब उसकी खाट खड़ी कर चुके होते। लेकिन वे इस चौपाए के आगे विवश हैं। उसकी हिमाकत के आगे नतमस्तक हैं। क्या करें वे इसे छोड़ भी तो नहीं सकते। जब टॉमी उनके तलवे चाटता है तो उन्हें बहुत सुकून मिलता है। लगता है, वे राजा हैं और रियाया उनके पैरों पर अपना माथा टेक रही है। रियाया के माथे का स्पर्श पाकर उनके चरणों को अवर्णनीय सुख मिलता है। यह सुख किसी मामूली आदमी को नहीं मिलता। तलवे चटवाए बिना उन्हें चैन नहीं मिलता। उन्हें इसकी लत हो गई है।

कान से साहब का संबंध विद्यार्थी जीवन से ही है। उन्हें याद है जब वे स्कूल में पढ़ते थे, तब गुरुजी उनके कान मरोड़ा करते थे। खैर! अब तो वह स्वस्थ परंपरा लुप्त-सी हो गई है। इसी कान मरोड़ने की बदौलत उनका गणित बहुत स्ट्रोंग है। जब भी वे दौरे पर निकलते हैं तो किसी स्कूल में जरूर जाते हैं। बच्चों से सत्रह, उन्नीस, सत्ताईस और उनतीस का पहाड़ा जरूर पूछते हैं। यदि बच्चों को पहाड़ा नहीं आता है तो वे गुरुजी का कान पकड़कर मरोड़ देते हैं। इस तरह वे गुरुजी को उनकी औकात बता देते हैं। जता देते हैं कि अब कान मरोड़ने का नंबर मेरा है। वो गुरु धन्य हैं, जिन्होंने उन्हें गुरु के भी कान मरोड़ने लायक बनाया है। ऐसे समय बेचारे गुरुवर बिना चू-चपड़ के तकलीफ सहते रहते हैं। जिस क्षण साहब कान छोड़ते हैं, उसी क्षण वे अपनी नौकरी की सलामती के लिए अपना तुच्छ शीश उनके अमूल्य चरणों में रख देते हैं।

> **‘कान से साहब का संबंध विद्यार्थी जीवन से ही है। उन्हें याद है जब वे स्कूल में पढ़ते थे, तब गुरुजी उनके कान मरोड़ा करते थे। खैर! अब तो वह स्वस्थ परंपरा लुप्त-सी हो गई है। इसी कान मरोड़ने की बदौलत उनका गणित बहुत स्ट्रोंग है।’**

इतने दमदार साहब की नाक में दम एक श्वान ने कर रखा है। यह बात अच्छी नहीं है। इन पंक्तियों के लिखने तक टॉमी ने अपने कान खड़े नहीं किए हैं। साहब गहरी चिंता में डूबे हैं। उनके मातहत अच्छे-अच्छे डॉक्टरों को ट्राय कर रहे हैं। पूजन-अर्चन चल रहा है। देखते हैं, कब, कैसे और किसके प्रयास से श्वान के कान खड़े होते हैं। उस कुत्ते (सॉरी! टॉमी) को भी चाहिए कि अपनी कुत्तागिरी छोड़े। अपने कान खड़े करके साहब को खुश करे। साहब खुश तो देश खुश। अरे! तूने खुशी के कान क्यों मरोड़ रखे हैं?

बहरहाल, प्रकृति में चारों तरफ भले ही बसंत छाया हो, किंतु साहब का बसंत तो तभी आएगा, जब उनके कुत्ते (सॉरी! टॉमी) के कान खड़े होंगे। उनका खोखा भर कमाने का सपना पूरा होगा।

● **गोविंद सेन**

वाटर हार्वेस्टिंग कराएं, जल सकंट से मुक्ति पाएं

बादल अमृत-सा जल लाता
अपने घर आंगन बरसाता
आओ करें इसका संग्रहण
बह ने जाए अमृत कलश
नदी नहर नल झील सरोवर
वापी कूप कुंड नद निर्झर
सर्वोत्तम सौन्दर्य प्रकृति का
कल-कल ध्वनि संगीत मनोहर
जल से अन्न पत्र फल पुष्पित सुन्दर उपवन है ।
जल पीकर जीते सब प्राणी जल ही जीवन है ।।

सौजन्य से : राष्ट्रीय पाक्षिक अक्स

विश्वसनीय खबरों के लिए पढ़ते रहिए

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

E-Magazine पढ़ने और PDF डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं

www.akshnews.com

वार्षिक सदस्यता के लिए संपर्क करें, 150, जोन-1, एम.पी.नगर भोपाल

फोन:0755-4017788,2575777

D-17008